सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

वर्ष 03, अंक 219, नई दिल्ली, गुरुवार 16 अक्टूबर 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता.

03 नारायण ने किया इंडियन आइडल में अपने नए रोल का खुलासा

06 जलवायु संकट का भावनात्मक सेहत पर असर

08 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जोरदार ऐलान: बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को...

दिल्ली-एनसीआर में गूजेगीं पटाखों की आवाज: सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के लिए ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग को सशर्त मंजूरी दी है, जिसमें केवल CSIR-NEERI प्रमाणित पटाखों की अनुमति है और बाहरी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस निर्णय के बाद केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिवाली के बाद प्रदूषण स्तर की निगरानी कर कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेंगे, जिससे वायु गुणवत्ता प्रबंधन की कड़ी समीक्षा होगी।

संजय बाटला

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के लिए ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग को सशर्त मंजूरी दी है, जिसमें केवल CSIR-NEERI प्रमाणित पटाखों की अनुमति है और बाहरी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस निर्णय के बाद केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिवाली के बाद प्रदूषण स्तर की निगरानी कर कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेंगे, जिससे वायु गुणवत्ता प्रबंधन की कड़ी समीक्षा होगी।

इस बार दिवाली दिल्ली और एनसीआर ग्रीन पटाखों वाली होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 21 अक्टूबर तक सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। वहीं, इन पटाखों की बिक्री केवल 15 से 25 अक्टूबर तक निर्धारित जगहों पर ही की जा सकेगी।

मौजूद जानकारी के अनुसार, अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल CSIR-NEERI द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की ही बिक्री होगी और पुलिस की ओर से अचानक निरीक्षण किए जाएंगे ताकि कोई निर्माता ग्रीन पटाखों के मानकों का उल्लंघन न करे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना पर्याप्त डेटा के पूरी तरह पटाखों पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं था और इसलिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें उत्सव मनाने की आजादी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना दी गई है।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि दिल्ली-एनसीआर में बाहर से कोई पटाखा नहीं लाया जा सकता और नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। CSIR-NEERI के अनुसार, ग्रीन पटाखों से पारंपरिक पटाखों की तुलना में 20–30% कम हानिकारक कण उत्सर्जित होते हैं। इन्हें हरे CSIR-NEERI लोगो और एनक्रिप्टेड QR कोड से पहचाना जा सकेगा, जिससे उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित हो।

हालांकि, पर्यावरणविद और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस निर्णय के प्रति सतर्क हैं। भवरिन कंधारी ने कहा कि दिल्ली की सर्दियों में प्रदूषण जमा होने के कारण ग्रीन पटाखों का केवल 30% उत्सर्जन कम होना पर्याप्त नहीं है। माता-पिता भी बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस दिवाली वाहन, निर्माण और बिजली से पहले से ही उच्च स्तर के प्रदूषण में पटाखों की छूट हवा की गुणवत्ता को और बिगाड़ सकती है।

पिछले वर्षों में ग्रीन पटाखों ने कचरा और धूल कम करने में मदद की है, लेकिन अध्ययन बताते हैं कि ये भी लंग्स में गहरे प्रवेश करने वाले अल्ट्राफाइन कण छोड़ते हैं। गौरतलब है कि पटाखों की बिक्री और फोड़ने के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCBs) निरंतर निगरानी करेंगे और दिवाली के बाद प्रदूषण स्तर की रिपोर्ट कोर्ट को प्रस्तुत करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय का आभार... दिल्ली में ग्रीन पटाखों की अनुमति मिलने पर सीएम रेखा गुप्ता क्या बोलीं?

राजधानी में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ग्रीन पटाखों की अनुमति दे दी है। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर कहा कि दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह पर राजधानी में ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली और दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की अनुमति दे दी है। इस आदेश से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया कि दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह पर राजधानी में ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार। यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

हमारा लक्ष्य- त्योहारों की रौनक बरकरार रहे

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जनभावनाओं का सम्मान करते हुए स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इस दीपावली, हम सब मिलकर ग्रीन पटाखों के साथ उत्सव और पर्यावरण संरक्षण का सामंजस्य स्थापित करें और 'हरित एवं खुशहाल दिल्ली' के संकल्प को साकार करें।

"टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत" सेवा ही संकल्प है!

पिंकी कुंडू, महासचिव टोलवा ट्रस्ट

हमारा मकसद सिर्फ मदद नहीं, बदलाव लाना है।

A voice for the voiceless, and a hand for the helpless.

हमारा उद्देश्य है समाज के उन हिस्सों तक पहुँचना जो आज भी भूख, शिक्षा और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हम जरूरतमंदों को बिना भेदभाव के भोजन, बच्चों को मुफ़्त शिक्षा, और समाज को जागरूकता देने का कार्य कर रहे हैं।

क्या मिलेगा हमसे जुड़कर

Ground-level food distribution,

Getting children free education,

हम मानते हैं – छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है।

If you believe in humanity, equality, and service — then you're already a part of our family.

हमें सपोर्ट करें और एक आवाज़ बनें इस बदलाव की।

Together, let's serve. Together, let's change.

टोलवा ट्रस्ट पंजीकृत से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और फार्म भरकर जुड़े,

www.tolwa.com/member.html

स्कैनर को स्कैन कर के भी आप टोलवा ट्रस्ट पंजीकृत से फार्म भर कर जुड़ सकते हैं,

वेब साइट पर www.tolwa.com पर भी जाकर आप फार्म भर के टोलवा ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं। www.tolwa.com

SCAN ME

टोलवा ट्रस्ट पंजीकृत
tolwaindia@gmail.com
www.tolwa.com

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

मुबारकपुर डबास में फिर बंद हुई बस सेवा दिल्ली सरकार की लापरवाही पर ग्रामीणों में नाराजगी

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मुबारकपुर डबास में एक बार फिर से डीटीसी बस सेवा ठप हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण क्षेत्र की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बाधित हो गई है।

जानकारी के अनुसार, गांव में पिछले पांच वर्षों तक सड़कों की खराब स्थिति के चलते बसें नहीं चल पा रही थीं। करीब 15 महीने पहले बस सेवा बहाल की गई थी, लेकिन अब 9 अक्टूबर से एक बार फिर परिचालन बंद है। इसके कारण मुबारकपुर डबास के साथ-साथ मदनपुर डबास, रानीखेड़ा, रसूलपुर और आसपास की दर्जनों कॉलोनियों के निवासी बस सुविधा से वंचित हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) द्वारा 11 केवीए का ग्रिड कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इस काम के तहत भूमिगत केबल रानीखेड़ा से मुबारकपुर डबास सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक बिछाई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी ने सड़क खोदने के लिए किसी सरकारी विभाग से अनुमति नहीं ली, जिससे बस सेवा बंद करनी पड़ी।

चौगामा विकास समिति के महासचिव विजेंद्र डबास ने इस स्थिति पर सरकार और निगम प्रशासन की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि "सरकार को ऐसा प्रबंध करना चाहिए था कि परिवहन व्यवस्था बाधित न हो। काम के साथ बस सेवा भी जारी रह सकती थी, लेकिन दबे-कुचले इलाकों की सुध लेने वाला कोई नहीं है।"

विजेंद्र डबास ने मांग की है कि इस निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही और जनता को असुविधा के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकारी प्रतिनिधि और अधिकारी दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं।

"डीटीसी बचाओ अभियान" दसवां दिन

दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जी

अंबेडकर नगर विधानसभा से विधायक अजयदत्त जी

बदरपुर विधानसभा से विधायक श्री रामसिंह नेताजी

नई दिल्ली संवाददाता - पंकज शर्मा

नई दिल्ली। DTC बचाओ अभियान के दसवें दिन बुधवार को भारतीय मजदूर संघ से पदाधिकारी व अन्य कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने दिल्ली के एक सांसद और तीन विधायकों को पत्र दिया डीटीसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के द्वारा दिल्ली के सभी 70 विधायकों को कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की मांगों का ज्ञापन देने की कड़ी में आज दक्षिणी दिल्ली से सांसद श्री रामवीर बिधूड़ी जी 2. बदरपुर विधानसभा से विधायक श्री राम सिंह नेताजी 3. अंबेडकर नगर विधानसभा से विधायक श्री अजय दत्त जी एवं 4.विश्वास नगर विधानसभा से विधायक ओम प्रकाश जी को ज्ञापन देकर समस्याओं से अवगत कराया गया।

आज दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में बसें समाप्त हो चुकी हैं, दिल्ली सरकार द्वारा किलोमीटर पर हायर की गई दिल्ली में प्राइवेट कंपनियां अपने पैर फैला रही हैं,जो अपने किलोमीटर पूरे करने के चक्कर में रोजाना दिल्ली की जनता को अपनी मंजिल पर पहुंचाने की जगह उन्हें हादसों का शिकार बना रही हैं, इस समय दिल्ली परिवहन निगम अपना अंतिम समय गिन रही है, चरणबद्ध तरीके से सरकारी बसों को दिल्ली की सड़कों से हटाया जा रहा है, दिल्ली में सरकारी बसें न होने के कारण दिल्ली की जनता को घंटों सड़कों पर इंतजार करना पड़ रहा है DTC, दिल्ली की जनता एवं कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को इन समस्याओं से बचाने के लिए भारतीय मजदूर संघ द्वारा यह अभियान चलाया गया है, संघ द्वारा परिवहन निगम तथा DTC कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए यह सराहनीय कार्य किया जा रहा है, आज भारतीय मजदूर संघ से जुड़े अन्य कर्मचारी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक श्री संजीव झा के पास पहुंचे, विधायक जी यूनियन के कर्मचारियों से तबीयत खराब होने के कारण मिलने में असमर्थ रहे, दूसरी और दिल्ली परिवहन निगम के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी मॉडल टाउन से BJP के विधायक श्री अशोक गोयल जी के पास पत्र देने पहुंचे तो बिहार विधानसभा चुनाव के चलते विधायक जी दिल्ली में मौजूद नहीं थे जिस कारण उन्होंने 18 अक्टूबर के बाद कर्मचारियों को मिलने का समय दिया। कर्मचारी यह ज्ञापन पत्र जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हैं एवं यूनियन के पदाधिकारी द्वारा सभी कर्मचारियों को सूचना दी गई कि जल्द से जल्द अपनी विधानसभा में जाकर अपने क्षेत्र के विधायकों को यह पत्र देने का कार्य पूर्ण किया जाए, दिल्ली सरकार सरकार बनने के लगभग 10 महीने बाद भी दिल्ली परिवहन निगम के कांटेक्ट कर्मचारियों के लिए पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा जारी किया गया समान काम समान वेतन एवं बेसिक da लागू नहीं कर पाई, जिस सर्कुलर को दिल्ली परिवहन निगम भूतपूर्व MD (सचिन शिंदे) द्वारा जारी कर दिया गया था I

दिल्ली के सभी 7 सांसद एवं 70 विधानसभा के विधायको को ज्ञापन पत्र सौंपने के 10 दिन तक अगर दिल्ली सरकार कोई भी ठोस कदम DTC कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की मांगों के लिए नही उठाती है तो DTC कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी BMS यूनियन के साथ आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है, यूनियन द्वारा सरकार को बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी सरकार मामले को संज्ञान नहीं ले रही है,

दिल्ली परिवहन मजदूर संघ प्रदेश कार्यालय अजमेरी गेट दिल्ली 110006

1. अध्यक्षः गूगन सिंह
2. महामंत्रीः भानु भास्कर

दीवाली से पहले दिल्ली जाम, दो किलोमीटर का सफर तय करने में लग गए दो घंटे

दीपावली से पहले दिल्ली की सड़कों पर भारी जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गिफ्ट खरीदने और दफ्तर से लौट रहे लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस की गैरमौजूदगी से स्थिति और बिगड़ गई। पुलिस ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है और अतिरिक्त टीमें तैनात करने का वादा किया है।

नई दिल्ली। दीपावली से पहले बुधवार शाम दिल्ली की सड़कों पर लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। गिफ्ट देने और खरीदारी के लिए घरों से निकले लोगों के साथ-साथ दफ्तरों से लौट रहे कर्मचारियों को परेशानी झेलनी पड़ी। हालात ऐसे बने कि दो किलोमीटर का सफर तय करने में लोगों को दो घंटे तक का समय लग गया।

शाम के समय दफ्तरों से निकलते ही हर ओर वाहनों की कतारें लग गईं। सड़क पर कार, बाइक, आटो और कैब का सैलाब उमड़ पड़ा। जैसे-जैसे भीड़ बढ़ी, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था चरमरा गई। लोगों का कहना है कि कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस के जवान नदारद थे, जिससे ड्राइवरों को खुद ही रास्ता बनाकर आगे बढ़ना पड़ा।

ट्रैफिक कंट्रोल रूम को शाम के कुछ घंटों में ही 30 से ज्यादा जाम की शिकायतें मिलीं। इनमें दक्षिण, मध्य और उत्तरी दिल्ली के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। एक अधिकारी के मुताबिक, दीपावली से पहले गिफ्ट वितरण, बाजारों में भीड़ और दफ्तरों से घर लौटने वालों के कारण अचानक ट्रैफिक का दबाव कई गुना बढ़ गया।

कुछ वीआईपी इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी तो दिखी, लेकिन बाकी सड़कों पर उनकी अनुपस्थिति से हालात बिगड़ते गए। कई जगहों पर लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर लिखा कि पुलिस सिर्फ बड़े अधिकारियों के गुजरने वाले रास्तों पर तैनात थी।

जानकारी के मुताबिक, यातायात जाम का सबसे अधिक असर आईटीओ, रिंग रोड, मथुरा रोड, रोहतक रोड, पहाड़गंज, दरिया गंज, कश्मीरी गेट, सरदार पटेल मार्ग, दिल्ली गेट, तीन मूर्ति, एनएच-9, आश्रम, श्रद्धानंद मार्ग सहित कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था चरमरा गई।

जाम में फंसे लोगों ने बताया कि घर पहुंचने में उन्हें दोगुना समय लग गया। कई ने कहा कि सिर्फ 15 मिनट की दूरी तय करने में डेढ़ से दो घंटे का वक्त लग गया। कुछ इलाकों में एंबुलेंस और जरूरी सामान ले जाने वाले वाहन भी फंसे रहे, जिससे लोगों में नाराजगी देखने को मिली।

ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि आने वाले दिनों में अनावश्यक यात्रा से बचें, सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करें और भीड़भाड़ वाले बाजारों में जाने से पहले वैकल्पिक मार्ग की जानकारी अवश्य लें। साथ ही दावा किया गया है कि आने वाले त्योहारों के दौरान पुलिस की अतिरिक्त टीमें तैनात की जाएंगी ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न बने।

अधिकतर घरों में बच्चे यह दो प्रश्न अवश्य पूछते हैं जब दीपावली भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है? राम और सीता की पूजा क्यों नही?

अधिकतर घरों में बच्चे यह दो प्रश्न अवश्य पूछते हैं जब दीपावली भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है? राम और सीता की पूजा क्यों नही

दूसरा यह कि दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है, विष्णु भगवान की क्यों नहीं

इन प्रश्नों का उत्तर अधिकांशतः बच्चों को नहीं मिल पाता और जो मिलता है उससे बच्चे संतुष्ट नहीं हो पाते।आज की शब्दावली के अनुसार कुछ 'लिबरल्स लोग' युवाओं और बच्चों के मस्तिष्क में यह प्रश्न डाल रहें हैं कि लक्ष्मी पूजन का औचित्य क्या है, जबकि दीपावली का उत्सव राम से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर वह बच्चों का ब्रेनवॉश कर रहे हैं कि सनातन धर्म और सनातन त्यौहारों का आपस में कोई तारतम्य नहीं है।सनातन धर्म बेकार है।आप अपने बच्चों को इन प्रश्नों के सही उत्तर बतायें।

दीपावली का उत्सव दो युग, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी उस दिन प्रगट हुई थी इसलिए लक्ष्मीजी का पूजन होता है। भगवान राम भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने घर घर दीपमाला जलाकर उनका स्वागत किया था इसलिए इसका नाम दीपावली है।अतः इस पर्व के दो नाम है लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा है दूजा दीपावली जो त्रेता युग प्रभु राम और दीपों से जुड़ा है।

लक्ष्मी गणेश का आपस में क्या रिश्ता है

और दीवाली पर इन दोनों की पूजा क्यों होती है?

लक्ष्मी जी सागरमन्थन में मिलीं, भगवान विष्णु ने उनसे विवाह किया और उन्हें सृष्टि की धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया। लक्ष्मी जी ने धन बाँटने के लिए कुबेर को अपने साथ रखा। कुबेर बड़े ही कंजूस थे, वे धन बाँटते ही नहीं थे।वे खुद धन के भंडारी बन कर बैठ गए। माता लक्ष्मी खिन्न हो गईं, उनकी सन्तानों को कृपा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम कुबेर के स्थान पर किसी अन्य को धन बाँटने का काम सौंप दो। माँ लक्ष्मी बोली कि यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं उन्हें बुरा लगेगा।

तब भगवान विष्णु ने उन्हें गणेश जी की विशाल बुद्धि को प्रयोग करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को भी कुबेर के साथ बैठा दिया। गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वे बोले, माँ, मैं जिसका भी नाम बताऊँगा , उस पर आप कृपा कर देना, कोई किंतु परन्तु नहीं। माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दी।अब गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न, रुकावट को दूर कर उनके लिए धनागमन के द्वार खोलने लगे।कुबेर भंडारी देखते रह गए, गणेश जी कुबेर के भंडार का द्वार खोलने वाले बन गए। गणेश जी की भक्तों के प्रति ममता कृपा देख माँ लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र श्रीगणेश को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपने पति नारायण के सँग ना हों, वहाँ उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहें।

दीवाली आती है कार्तिक अमावस्या को, भगवान विष्णु उस समय योगनिद्रा में होते हैं, वे जागते हैं ग्यारह दिन बाद देव उठनी एकादशी को। माँ लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है शरद पूर्णिमा से दीवाली के बीच के पन्द्रह दिनों में।इसलिए वे अपने सँग ले आती हैं अपने मानस पुत्र गणेश जी को।

इसलिए दीवाली को लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है।

पुष्य नक्षत्र

संक्षिप्त उत्तरः पुष्य नक्षत्र हिंदू ज्योतिष में एक अत्यंत शुभ मानी जाने वाली नक्षत्र है, जिसे कई मान्यताओं में धन-समृद्धि, खरीदारी, और नए आरंभ के लिए लाभकारी माना जाता है। सामान्य तौर पर Diwali/Pradosh आदि अवसरों के आसपास पुष्य योग को शुभ माना जाता है, खासकर अगर यह नक्षत्र खरीदारी, धन-सम्पदा, भवन-गहनों आदि के लिए घड़ी-समय पर आ जाए।

तथ्यात्मक विवरण

- क्या हैः पुष्य नक्षत्र 27-nakshatra में से एक है और इसे "पोषणकर्ता" या "प्रसन्नता देने वाला" तारा मानते हैं। यह चंद्रमा के कर्क राशि में रहने के साथ जुड़ा माना जाता है, और इसका स्वामी ग्रह शनि तथा अधिष्ठाता ग्रह गुरु/बृहस्पति माना जाता है।[1][2][3]

- सकारात्मक प्रभावः पुष्य को सर्वाधिक मंगलकारी और लाभदायक माना जाता है। नए वस्तु-खरीदना, सोना-चांदी, संपत्ति आदि खरीदने के लिए सामान्यतः शुभ माना जाता है, क्योंकि यह धन-संरक्षण और समृद्धि को बढ़ाने का संकेत देता है।[1][2]

- सावधानियाँ/वर्जनाएँः कुछ पंचांग और लेखन पुष्य केCertain दिनों में विवाह जैसे कुछ कार्यों के लिए निषेध या सावधानियाँ भी बताते हैं। शुक्र और बुध के कुछ योग पुष्य के समय अशुभ प्रभाव भी दे सकते हैं। अतः पुष्य-nakshatra के नवीन आरम्भों के लिए सही तिथि और समय की पुष्टि आवश्यक है।[4][5]

क्या करें/क्या न करें (व्यावहारिक सुझाव)

- खरीदारी के लिए समयः पुष्य नक्षत्र के दौरान Gold, Jewellery, वाहन, भूमि-आस्तियाँ या बड़े निवेश की शुरुआत करना शुभ माना जाता है, खासकर पुष्य के शुभ चरणों में। दीपावली के पहले पुष्य योग भी लोकप्रिय माने जाते हैं। परन्तु यह हर साल की तिथि और समय पर निर्भर होता है, इसलिए व्यक्तिगत पंचांग/अष्टक की पुष्टि करें।

- क्या बचना चाहिएः कुछ लेखों में पुष्य के कुछ दिन अशुभ योग से जुड़े बताए गए हैं (जैसे शुक्रवार/बुधवार के पुष्य दिन)—इनमें विवाह जैसे निर्णयों को टालना बेहतर समझा गया है। समय-स्थितियों का सावधानी से मिलान करें।

भारतीय सनातन संस्कृति

कोई भी संस्कृति विकास के दौर में अपने अनुभवों के आधार पर उत्पन्न जरूरतों और अपेक्षाओं की पूर्ति की दिशा में कार्यरत हो कर आगे बढ़ती है। समाज जाने-अनजाने अपने अनुभवों से सीखते हुए अपने क्रियाकलापों को संशोधित भी करता रहता है।

पिछला ज्ञान अगले ज्ञान प्राप्ति की सीढ़ी बन जाता है। इस प्रक्रिया में कई सारी बातें अपने कड़वे अनुभवों के कारण वह, छोडने या संशोधित करने का प्रयास करता रहता है और कई सारी बातों में उसे कुछ नया करने की आवश्यकता अनुभव होती है, जिसे वह कई तरह के नवाचारों से पूरा करने का प्रयास करता है।

ये नवाचार भौतिक आवश्यकताओं से लेकर सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, कलात्मक, सुरक्षात्मक, शासनात्मक आदि अनेक प्रकार के होते हैं। इन सबके मेल से एक संस्कृति का निर्माण होता है जिसमें कई अनायास और सप्रयास तत्व जुड़े रहते हैं। सप्रयास तत्व संशोधन की प्रक्रिया में से निकलते हैं और अनायास तत्व समाज की 'कम से कमतर संघर्ष' की आवश्यकता वाला मार्ग अनुसरण करने की सहज प्रवृत्ति का परिणाम होते हैं। जो समाज जितने अधिक स्वतंत्र रहे उतने अधिक वहाँ सप्रयास संशोधन के प्रयास हुए।

इस दृष्टि से भारतीय संस्कृति को देखें तो इसके लिए गुप्त काल तक स्वतंत्र रहने सोचने का जो लंबा अवसर मिला उसी में इसके साहित्य, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्वेद, गणित, कला, वास्तु शास्त्र आदि का विकास हुआ। उसके बाद के परतन्त्रा का काल तो अपने अस्तित्व को बचाने के संघर्षों की भेंट ही चढ़ता रहा, जिसमें कई अच्छी चीजें मिट गईं और कई अनैतिक प्रकल्प सुदृढ़ होते गये। क्योंकि संशोधन का समय ही कहाँ था। कई नए दोष भी पनप गए।

वर्तमान में हमें जातिवाद एक बड़ा दोष नजर आता है जिसके आधार पर छोटा और बड़ा निर्धारित करना, पूर्णतः अवैज्ञानिक और मानवतावाद की नजर से और आध्यात्मिक नजर से भी तर्कसम्मत कदापि नहीं है।

इसे सारे अहंकार छोड़ कर समाप्त करने की दिशा में हम जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना ही हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा। जातिमुक्त समाज समय की मांग भी है। इसे ही हम सामाजिक न्याय कह रहे हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, रंग, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर कोई भी भेद सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता। इस बात को हृदयंगम करने का आसान तरीका है समानुभूति।

अर्थात पीड़ित के स्थान पर अपने आपको रख कर सोचना। हमारे साथ कोई ऐसा करे तो हमें कैसा लगेगा। इससे बहुत बड़ी शक्ति मानसिक तौर पर मिलती है जिसके बल पर हम आत्म संशोधन के बड़े से बड़े कदम, समाज की निंदा स्तुति की परवाह किए बिना उठा सकते हैं। दहेज, बाल विवाह, जनसंख्या नियंत्रण का अभाव, प्रकृति विनाशक जीवन पद्धति आदि सांस्कृतिक दूषण भी समाज में विद्यमान हैं।

इनसे मुक्ति सर्वांगीण प्रगति के लिए जरूरी है। लेकिन कुछ दोष आ जाने के कारण हमें किसी भी संस्कृति के गुणों से अनभिज्ञ होकर उसके साथ घृणा करने से भी बचना चाहिए। इससे हम दीर्घ कालीन अनुभव से संचित सकारात्मक संस्कार से अपने आप और समग्र समाज को वंचित कर देंगे। कोई भी संस्कृति ऐसी नहीं है जिसमें दोष न हों। और कोई भी संस्कृति ऐसी भी नहीं जिसमें गुण न हों। इसलिए गुण-दोष के आधार पर ही विवेचन होना चाहिए।

आत्मरक्षा में धर्मयुद्ध करना मनुष्य का परम धर्म है

करवट बदल रहा है मौसम, सर्दी-खांसी और खराश कर रही परेशान?

नींबू रस में मिलाकर इस चीज का करें सेवन, जल्द मिलेगी राहत...

नींबू का रस और शहद दोनों में ही एंटीऑक्सीडेंट गुण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए गले में खराश होने पर नींबू के रस में शहद मिलाकर पीने से राहत मिलती हैं।

दरअसल, शहद में सूजन-रोधी और बैक्टीरिया-रोधी गुण भी होते हैं, जो श्वसन रोगों को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नींबू में मौजूद अम्लता बलगम को तोड़ती है और संक्रमण को दूर रखती है। यदि आप इस रस में थोड़ी काली मिर्च पाउडर मिलाकर पीए तो दर्द और सूजन से राहत मिलेगी।

इस रस को पीने से गले की खुश्की और जलन से राहत मिलती है. साथ ही गले में नमी बनी रहती है। नींबू और शहद का सेवन बच्चों को छोड़कर हर कोई कर सकता है।

नींबू के रस में शहद और ताजा अदरक का रस मिलाकर पीना बच्चों सहित सभी के गले की खराश के लिए बहुत प्रभावी है।

नींबू में मौजूद विटामिन सी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और बलगम को बाहर निकालता है।

अदरक में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण उपचार प्रक्रिया को तेज करते हैं।

सर्दी-खांसी से बचने के लिए शहद और नींबू भी अधिक कारगर है।

इसके लिए 200 मिलीलीटर पानी में अदरक का एक छोटा टुकड़ा उबालें। फिर इसमें एक चम्मच शहद और नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाएं। इसको पीने जल्द राहत मिल सकती है। ये दवाओं की तुलना में तेजी से राहत प्रदान कर सकता है।

कार्तिक मास पर्व / उत्सव...

* शनिवार, 18 अक्टूबर 2025
धन त्रयोदशी, प्रदोष पर्व
भगवान धन्वंतरी जयंती
यम दीपदान

* रविवार, 19 अक्टूबर 2025
नरक चतुर्दशी

* सोमवार, 20 अक्टूबर 2025
दीपावली महापर्व,
महालक्ष्मी पूजन,

* मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025
स्नान, दान, देव, पितृ कार्य
अमावस्या

* बुधवार, 22 अक्टूबर 2025
गौ - गोवर्धन पूजा

* गुरूवार, 2* अक्टूबर 2025
भाई दूज महापर्व

* बुधवार, 29 अक्टूबर 2025
गोपाष्टमी, सायंकाल
गौपूजन
गौ माता को 56 भोग,
महाआरती

* गुरूवार, *0 अक्टूबर 2025
अक्षय (आँवला) नवमी
प्रातः - भगवान विष्णु का पूजन
सायंकाल - 56भोग,
अन्नकूट महोत्सव

* शनिवार, 1 नवम्बर 2025
देव प्रबोधिनी एकादशी
तुलसी विवाह
छोटी दीपावली

* बुधवार, 5 नवम्बर 2025
कार्तिक पूर्णिमा

कृपया इसे अवश्य पढ़ें – अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी

एक मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर चौथे वर्ष के मेडिकल छात्रों को पढ़ा रहे थे।

उन्होंने छात्रों से पूछा — "बुज़ुर्ग लोगों में मानसिक भ्रम (Mental Confusion) के सबसे आम कारण क्या हैं?"

कुछ छात्रों ने उत्तर दिया — "ब्रेन ट्यूमर।"

प्रोफेसर बोले — "नहीं।"

दूसरे छात्रों ने कहा — "अल्ज़ाइमर रोग (स्मृति लोप) के शुरुआती लक्षण।"

प्रोफेसर ने फिर कहा — "नहीं।"

जब सभी छात्र उत्तर देने में असमर्थ हो गए, तो प्रोफेसर ने उत्तर बताया

"डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी)"

यह सुनकर छात्र चकित रह गए।

परंतु यह कोई मज़ाक नहीं था।

डिहाइड्रेशन क्यों ख़तरनाक है?

60 वर्ष की उम्र के बाद शरीर में प्यास का अहसास कम होने लगता है। इसलिए बुज़ुर्ग लोग पानी कम पीते हैं, जिससे शरीर जल्दी निर्जलित (dehydrated) हो जाता है।

जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो यह पूरे शरीर की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है।

डिहाइड्रेशन से हो सकते हैं —

अचानक मानसिक भ्रम या अस्थिरता

लो ब्लड प्रेशर

हृदय की धड़कन तेज़ होना

सीने में दर्द (एंजाइना)

कोमा

यहाँ तक कि मृत्यु भी

60 वर्ष की उम्र के बाद शरीर का पानी का स्तर 50% से भी कम रह जाता है।

यह उम्र के साथ होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन बहुत हानिकारक साबित हो सकती है।

महत्वपूर्ण निष्कर्ष

बुज़ुर्ग लोग आसानी से डिहाइड्रेशन के शिकार हो सकते हैं,

क्योंकि वे प्यास लगने का अनुभव ही नहीं कर पाते।

भले ही वे स्वस्थ दिखें,

लेकिन शरीर में पानी की कमी उनकी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को धीमा कर देती है।

दो महत्वपूर्ण सुझाव

1 बुज़ुर्गों के लिए —

नियमित रूप से तरल पदार्थ पीना बहुत आवश्यक है।

तरल पदार्थों में शामिल करें:

पानी

फलों के रस

नारियल पानी

सूप

चाय

पानी से भरपूर फल — तरबूज, खरबूजा, आड़ू, अनानास, संतरा आदि

हर दो घंटे में थोड़ा-थोड़ा तरल ज़रूर लें।

2 परिवार के सदस्यों के लिए —

यह सुनिश्चित करें कि आपके घर के बुज़ुर्ग नियमित रूप से पानी और तरल पदार्थ लेते रहें।

यदि वे पानी पीने से मना करें, चिड़चिड़े लगें, ध्यान केंद्रित न कर पाएं या सांस लेने में परेशानी महसूस करें —

तो यह डिहाइड्रेशन के स्पष्ट संकेत हैं।

निष्कर्ष और संदेश

पानी ही जीवन है — और बुज़ुर्गों के लिए तो यह अमृत समान है।

उन्हें बार-बार पानी या तरल पदार्थ पीने के लिए प्रेरित करें।

इस जानकारी को दूसरों के साथ साझा करें।

यह संदेश किसी के जीवन की रक्षा कर सकता है।

विश्व खाद्य दिवस आज

हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पेट भर खाना नहीं खा पाते। इस दिन का मकसद यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि भोजन सिर्फ ज़रूरत नहीं, बल्कि हर इंसान का हक है। दुनिया में अनाज और खाने-पीने की चीज़ों की कमी नहीं है, फिर भी लाखों लोग भूखे पेट सोते हैं। इसका मतलब साफ है कि खाने की सही व्यवस्था और समान बंटवारा नहीं हो रहा। यही सोच कर इस दिन की शुरुआत हुई थी।

कब मनाया जाता है ये दिन?

==========

विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत साल 1979 में संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी FAO यानी Food and Agriculture Organization ने की थी।

क्यों मनाया जाता है ये दिन?

==========

* इस दिन को मनाने का मकसद था - सबके लिए खाने की व्यवस्था को बेहतर बनाना और भूख को पूरी तरह खत्म करना।

* इस दिन को मनाने का एक और बड़ा कारण यह है कि लोग समझें - पोषक भोजन कितना ज़रूरी है, और खाने की बर्बादी कितनी नुकसानदायक।

विश्व खाद्य दिवस का महत्व

==========

जागरूकता

यह दिन लोगों को भूख और कुपोषण की गंभीर वैश्विक समस्याओं के बारे में शिक्षित करता है।

कार्रवाई

विश्व खाद्य दिवस लोगों को खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि खाद्य पदार्थों की बर्बादी को कम करना और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना।

भोजन का अधिकार

==========

विश्व खाद्य दिवस इस बात पर जोर देता है कि सभी को पौष्टिक भोजन का अधिकार है। और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे।

हम क्या कर सकते हैं?

==========

* जितना जरूरत हो उतना ही खाना लें।

* खाने की बर्बादी न करें।

* बचा हुआ खाना जरूरतमंदों को दें।

* स्थानीय किसानों से खरीदी को बढ़ावा दें।

पोषण और साफ-सफाई पर ध्यान दें।

हर छोटा कदम एक बड़ी बदलाव की शुरुआत हो सकता है।

कैसे करें घर की सफाई

कहते हैं जिस घर में साफ-सफाई होती है वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि धन की देवी मां लक्ष्मी को सफाई अत्यंत प्रिय है। परंतु वास्तु शास्त्र में सफाई को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं, जिनके अनुसार घर की सफाई की जाए तो घर में सुख-समृद्धि के सारे रास्ते खुल जाते हैं।

अपने घर को साफ रखना किसको पसंद नहीं होता। घर की साफ सफाई से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तो बढ़ता ही है साथ की घर में बीमारियां भी कम फैलती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी हर वस्तु का प्रभाव घर के सदस्यों की तरक्की, सेहत और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि यदि आप वास्तु के कुछ नियमों का पालन कर घर की साफ-सफाई करें तो आपके घर में सदैव सुख-समृद्धि बनी रहेगी।

साफ-सफाई का समय

वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि कभी भी सूर्यास्त के बाद या फिर सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घर में झाड़ू नहीं लगाई जानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह समय माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश करने का होता है, लेकिन

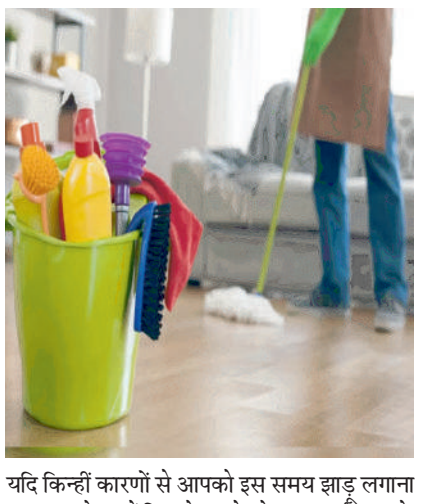

यदि किन्हीं कारणों से आपको इस समय झाड़ू लगाना पड़ जाए तो इसमें निकले कचरे को सुबह सूर्य उदय के बाद ही घर से बाहर फेंकें।

घर के कोनों का रखें ध्यान

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा, ईशान कोण और वायव्य कोण का साफ सुथरा और खाली होना बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि घर की इन दिशाओं में धन के देवता कुबेर का वास होता है। इसीलिए घर के सभी कोनों की साफ-सफाई रखना बहुत जरूरी है।

बाथरूम की साफ सफाई

ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग अपने घर को तो साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन बाथरूम की साफ सफाई की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। आपको बता दें कि घर के साथ-साथ अपने टॉयलेट, बाथरूम को साफ रखना भी बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा घर के बाथरूम और टॉयलेट में कभी भी मकड़ी के जाले लगने ना दें। ऐसा होने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है।

छत पर कबाड़

वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि घर की बालकनी या छत पर टूटी फूटी चीजें या कबाड़ इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा होने से घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। साथ ही टूटी फूटी चीजों में पानी जमा होने के कारण मलेरिया जैसी घातक बीमारियां भी पनपती हैं।

महिला पत्रकारों के बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस: आत्मा पर चोट

ओंकारेश्वर पांडेय

भारत की राजधानी—जिसे हम भारतवर्ष, माँ भारती कहते हैं जहाँ महिला शक्ति को दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, वहाँ एक ऐसा क्षण घटित हुआ जिसने पूरे राष्ट्र को असहज कर दिया।

एक तालिबानी मंत्री, आधिकारिक राजनयिक दौरे पर दिल्ली आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन महिला पत्रकारों को प्रवेश नहीं दिया गया।

यह केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं थी। यह हमारे संविधान, हमारी संस्कृति और उस राष्ट्र की आत्मा पर चोट थी जो सदैव नारी सम्मान को सर्वोपरि मानता है।

हालाँकि तालिबान ने अगले दिन महिला पत्रकारों को आमंत्रित कर एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की लेकिन जो अपमान हो चुका था, वह छवि पर स्थायी दाग छोड़ गया।

भारत की विदेश नीति का मोड़: तालिबान से आधिकारिक मुलाकात

9 से 16 अक्टूबर 2025 तक अफगानिस्तान के तालिबान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर आए। शुक्रवार को उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की।

यह भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। नई दिल्ली तालिबान से संवाद कर रही है जबकि उसने अब तक तालिबान शासित अफगानिस्तान को मान्यता नहीं दी है।

भारत की सुरक्षा गणना और बदलती भूराजनीतिक परिस्थितियाँ इस संवाद को समझा सकती हैं लेकिन समय, प्रस्तुति और तालिबान के महिला विरोधी रवैये पर चुप्पी कई सवाल खड़े करती है:

- क्या भारत एक ऐसे शासन को सामान्य बना रहा है जो महिलाओं को मिटा देता है?
- क्या यह रूस और चीन को संकेत है जो तालिबान से संपर्क में हैं?
- या यह प्रशासनिक उदासीनता है, जहाँ संवैधानिक मूल्यों को बलि चढ़ा दिया गया?

अगला दिन: सुधार नहीं, छवि बचाव

वैश्विक आलोचना के बाद तालिबान ने दिल्ली में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस बार महिला पत्रकारों को आमंत्रित किया।

लेकिन यह कोई सुधार नहीं था—यह एक छवि बचाव की रणनीति थी जो अंतरराष्ट्रीय निंदा और घरेलू शर्मिंदगी के दबाव में की गई।

इस दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्ताकी से लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध को लेकर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा, यह "हराम" नहीं है, बस "स्थगित" है, एक ऐसा उत्तर जो तर्क और मानवता दोनों का अपमान करता है।

तालिबान का लैंगिक रंगभेद: एक सुनियोजित बहिष्कार

अगस्त 2021 से तालिबान ने अफगान महिलाओं को सुनियोजित रूप से सार्वजनिक जीवन से बाहर कर दिया:

- छठी कक्षा के बाद लड़कियों की शिक्षा पर रोक
- महिलाओं को NGO, मीडिया, और सरकारी सेवा से बाहर
- पार्क, जिम, और सैलून तक में प्रवेश वर्जित
- बिना पुरुष अभिभावक के यात्रा पर रोक
- विरोध करने पर जेल, मारपीट, और गायब कर देना आम

संयुक्त राष्ट्र ने इसे "Gender Apartheid" यानी लैंगिक रंगभेद कहा है—एक शब्द जो पहले केवल दक्षिण अफ्रीका के नस्लीय भेदभाव के लिए प्रयुक्त होता था।

वैश्विक अस्वीकृति—एक अपवाद के साथ

हाल तक तक, संयुक्त राष्ट्र के 193

सदस्य देशों में से किसी ने भी तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी थी लेकिन 3 जुलाई 2025 को रूस ने इस परंपरा को तोड़ते हुए तालिबान को आधिकारिक मान्यता दी। इससे पहले अप्रैल 2025 में रूस ने तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा दिया था।

बाकी दुनिया—मुस्लिम बहुल देश, कम्युनिस्ट शक्तियाँ और ऐतिहासिक सहयोगी—अब भी तालिबान को अस्वीकार करती हैं।

ऐसे भेदभावपूर्ण आयोजन को भारत की धरती पर अनुमति देना हमारे संवैधानिक आत्मा का अपमान है:

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था:

"किसी समाज की प्रगति का मापदंड उसकी महिलाओं की स्थिति से होता है।"

भारत की आध्यात्मिक परंपराएँ नारी को दिव्य शक्ति मानती हैं:

- "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:"
- "मातृदेवो भव" – तैत्तिरीय उपनिषद
- ऋग्वेद (10.85.46): "जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ सभी कर्म निष्फल होते हैं।"

स्वामी विवेकानंद ने कहा:

"जब तक नारी की स्थिति सुधरेगी नहीं, तब तक समाज का कल्याण असंभव है।"

सभी धर्मों में नारी का सम्मान: भारत की बहुधार्मिक चेतना

भारत की आत्मा केवल सनातन धर्म से नहीं, बल्कि हर प्रमुख धर्म से नारी सम्मान की ज्योति जलाती है:

- इस्लाम: "स्वर्ग माँ के पैरों के नीचे है।"

- ईसाई धर्म: "वह शक्ति और गरिमा से परिपूर्ण है।" (नीतिवचन 31:25)
- सिख धर्म: "नारी से जन्म, नारी से सृष्टि।" – गुरु नानक
- जैन धर्म: चंदनबाला की करुणा और ज्ञान पूजनीय
- बौद्ध धर्म: "स्त्रियाँ भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं।" – गौतम बुद्ध
- पारसी धर्म: अनाहिता देवी को उर्वरता और बुद्धि की देवी माना जाता है
- आदिवासी परंपराएँ: महिलाएँ भूमि, संस्कृति और इतिहास की संरक्षक हैं
- दलित आंदोलन: "किसी समाज की प्रगति का मापदंड उसकी महिलाओं की स्थिति से होता है।" – डॉ. अंबेडकर

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह कोई नीति विचलन नहीं बल्कि नीति का असली चेहरा है जहाँ नैतिक स्पष्टता को रणनीतिक अस्पष्टता में खो दिया गया है।

जनता के आक्रोश के बाद, भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अफगान दूतावास द्वारा आयोजित की गई थी और भारत की कोई भूमिका नहीं थी।

सरकार को चाहिए था कि वह महिला पत्रकारों के अपमान की खुलकर निंदा करती और ऐसे किसी भी विदेशी प्रतिनिधिमंडल को आगामी प्रवेश से वंचित करती जो भारत के संविधान और सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान करे।

यदि भारत अपने मूल्यों की रक्षा नहीं करता तो वह संयुक्त राष्ट्र, G20 और वैश्विक मंचों पर महिला अधिकारों के नैतिक नेतृत्व को खो देगा।

Fun Way Learning NGO में दीवाली बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। लंगर भी लगाया गया और सभी को मिठाई भी बाँटी गई।

एनएफ डीएल फतेहनगर टीम की वैशाली शर्मा द्वारा ज्वालापुरी, पश्चिम विहार में किया गया साइबर सुरक्षा जागरूकता सत्र

परिवहन विशेष न्यूज

विभिन्न समुदाय के सदस्यों के साथ सफलतापूर्वक साइबर सुरक्षा जागरूकता सत्र (Cyber Security Awareness Session) आयोजित किया गया। सत्र बहुत ही इंटरएक्टिव रहा और प्रतिभागियों की उत्सुकता व सीखने की इच्छा देखकर मन प्रसन्न हो गया। हमने साइबर सेफ्टी, सोशल मीडिया जागरूकता, डिजिटल वेलबीइंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। प्रतिभागियों ने अपने विचार और अनुभव साझा किए, जिससे चर्चा और भी जानकारीपूर्ण व रोचक बन गई। हमें गर्व है कि इस पहल में कई समुदाय सदस्यों ने सक्रिय भाग लिया, जिससे यह सत्र वास्तव में अर्थपूर्ण और प्रभावशाली बन गया।

अंतरराष्ट्रीय सम्मान समारोह में 151 विशिष्ट हस्तियों को मिला सम्मान

'हिंदी-उर्दू अदबी संगम' दिल्ली का ग़ालिब इंस्टीट्यूट में हुआ भव्य आयोजन

डॉ. शंभू पंवार

नई दिल्ली। राजधानी की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था हिंदी-उर्दू अदबी संगम, दिल्ली के तत्वावधान में ग़ालिब इंस्टीट्यूट में एक भव्य अंतरराष्ट्रीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूएसए से प्रसिद्ध समाजसेवी इंद्रजीत शर्मा ने की, जबकि मुख्य अतिथि श्रीमती मनीषा शर्मा (राजभाषा प्रमुख, पंजाब नेशनल बैंक, दिल्ली) थी एवं विशिष्ट अतिथियों में डॉ. सविता चढ़ा (अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार, दिल्ली), इंजी. ए. डब्ल्यू. अंसारी (संयुक्त निदेशक, एमसीडी दिल्ली), डॉ. हरिप्रसाद तिमिलिसेना व श्रीमती कल्पना पौडेल (नेपाल), सुश्री कौशल सुमाली (श्रीलंका) तथा डॉ. भरत सिंह (चेयरमैन, पी.आई.आई.टी. कॉलेज, नोएडा) मौजूद रहे।

समारोह का प्रथम सत्र सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, कवि सम्मेलन और मुशायरे को समर्पित था, जिसमें देशभर से आए कवि-शायरों ने अपनी ओजस्वी व संवेदनशील रचनाओं से श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। लोक परंपराओं और भारतीय सांस्कृतिक विविधता की झलक इस सत्र की विशेषता रही। द्वितीय सत्र में विभिन्न क्षेत्रों—शिक्षा, साहित्य, चिकित्सा, विधि, समाजसेवा, राजनीति और पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 151 प्रतिष्ठित विभूतियों को अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।सम्मानित होने वालों में प्रमुख नाम हैं —

दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर ज्योति स्वरूप गौड़, अंतरराष्ट्रीय लेखक व पत्रकार डॉ. शंभू पंवार, डॉ. गीतांजलि नीरज अरोड़ा, डॉ. कल्पना पाण्डेय, सैयद सऊद जैद, सृष्टि गुलाटी, डॉ. शकुंतला मित्तल, डॉ. अंजु क्वात्रा, डॉ. करण आर्य, खगेंद्र प्रसाद उपाध्याय, डॉ. मनोज कुमार केन, मुस्तफा कमाल, रविता मलिक, ममता सिंह, डॉ. सोनिया रानी सहित देश-विदेश की अनेक विशिष्ट शख्सियतें।

पुस्तकों, कैलेंडर का लोकार्पण

समारोह के दौरान कई पुस्तकों का विमोचन भी किया गया—

'अंतरराष्ट्रीय स्तर की अनमोल शख्सियतें', डॉ. नक़वी की कृति 'सफ़रनामा एक कलमकार',

संस्था की परिचय पत्रिका 'मेरे ख्वाब मेरे साथ' और कैलेंडर 2026 का लोकार्पण हुआ।

नीति आयोग द्वारा जनपद एटा के जिलाधिकारी को आकांक्षात्मक ब्लॉकों में उत्कृष्ट कार्य हेतु किया गया पुरस्कृत...

अंकित गुप्ता दिल्ली

जनपद के ब्लाक अवागढ में मध्यम तीव्र कुपोषण (मैम) और गंभीर तीव्र कुपोषण (सैम) बच्चों पर किये गये कार्य तथा विकास खण्ड जैथरा में टी0बी0 पर किए गए कार्यों की सराहना की गई...

नीति आयोग द्वारा बेहतर कार्य के लिए अवागढ़, जैथरा ब्लाक को एक-एक लाख रूपये की धनराशि देकर किया गया पुरस्कृत...

नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद एटा के दो ब्लॉकों अवागढ़ एवं जैथरा को उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए पुरस्कृत किया गया है। यह उपलब्धि जनपद के विकास कार्यों, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र में की गई उल्लेखनीय प्रगति का परिणाम है। नीति आयोग द्वारा जनपद के ब्लॉक अवागढ़ को मध्यम तीव्र कुपोषण (मैम) एवं गंभीर तीव्र कुपोषण (सैम) बच्चों के उपचार, पोषण पुनर्वास और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया। वहीं ब्लॉक जैथरा को टी0बी0 उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने, रोगियों की पहचान, उपचार और

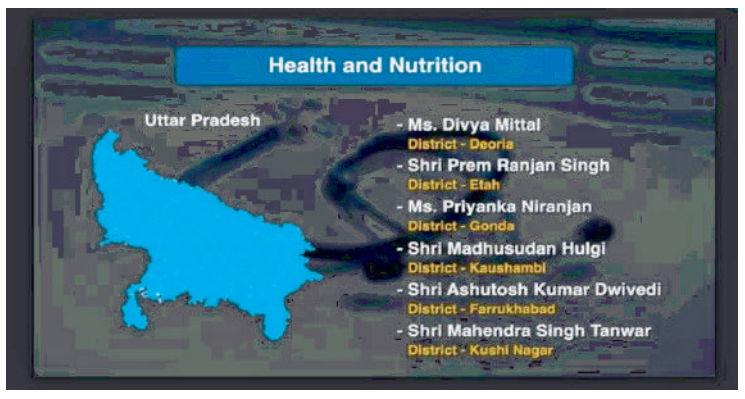

स्वास्थ्य सुधार में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है।

नीति आयोग द्वारा इन दोनों ब्लॉकों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए एक-एक लाख रुपये की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की गई है। इस सम्मान से जनपद का गौरव बढ़ा है तथा अन्य ब्लॉकों को भी प्रेरणा मिली है कि वे भी आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम के लक्ष्यों की दिशा में प्रभावी रूप से कार्य करें। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग ने देशभर के आकांक्षात्मक ब्लॉकों से एनएफएस पोर्टल के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास, बुनियादी ढाँचा तथा सामाजिक विकास जैसे छह प्रमुख विषयों में किए गए कार्यों का विवरण मांगा था। एटा जनपद के इन दोनों ब्लॉकों ने सभी निर्धारित मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी कार्यक्षमता एवं समर्पण का परिचय दिया।

बताते चलें कि विकसित भारत की दिशा में काम को प्रेरित करने के लिये, सीखने एवं साझा करने के लिये नीति आयोग ने साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने के लिए दिसंबर 2024 में नीति फॉर स्टेट्स यूज केस चैलेंज शुरू किया था। यह चैलेंज 9 अक्टूबर 2025 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मंसूरी में आयोजित एक सम्मान समारोह के साथ संपन्न हुआ। नीति आयोग द्वारा नवीनतम राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय जानकारी तक पहुचने के लिये विकसित एन0एफ0एस0 (Niti For States) पोर्टल पर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास बुनियादी ढाँचा, और सामाजिक विकास जैसे छह प्रमुख विषयों में डेटा-संचालित शासन के असाधारण उपयोग के लिए प्रस्तुतियों को मान्यता दी गई।

जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने इस उपलब्धि पर अवागढ़ एवं जैथरा ब्लॉकों की टीमों को बधाई देते हुए कहा कि यह पुरस्कार टीमवर्क, जनभागीदारी और बेहतर समन्वय का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी विकास खंड इसी प्रकार समन्वित प्रयासों से शासन की योजनाओं को धरातल पर उतारें, ताकि जनपद एटा राज्य में उत्कृष्टता का उदाहरण बन सके।

सुपरकंप्यूटिंग इंडिया 2025 ने एच पी सी, ए आई और क्वांटम नवाचार के लिए मंच तैयार किया

मुख्य संवाददाता

बेंगलुरु। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) के अधीन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक), बेंगलुरु द्वारा आयोजित सुपरकंप्यूटिंग इंडिया 2025 के उद्घाटन संस्करण सम्मेलन का आज पूर्वावलोकन कार्यक्रम प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों, उद्योग जगत के प्रमुखों और उद्यमियों की उपस्थिति में किया गया। एस सी आई 2025 का आयोजन एम ई आई टी वाई और डी एस टी, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एन एस एम - एच आर डी के तहत एच पी सी कौशल विकास और ज्ञान-साझाकरण केंद्र (सी-हक) की गतिविधि के विस्तार के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। सुपरकंप्यूटिंग इंडिया 2025 का विषय ₹भविष्य को सशक्त बनाना: एच पी सी, ए आई, क्वांटम तकनीकी₹ है, जो भारत की प्रमुख पहल, राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एन एस एम) के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार और राष्ट्रीय विकास के लिए उच्च प्रदर्शन वाले सुपरकंप्यूटरों का एक नेटवर्क बनाना है। एन एस एम के तहत, 39 पेटाफ्लॉप्स (PF) की संचयी क्षमता वाले 37 सुपरकंप्यूटर पहले ही शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में चालू किए जा चुके हैं, जो वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और छात्रों को अत्याधुनिक कम्प्यूटेशनल संसाधनों के साथ सशक्त बनाते हैं।

एस सी आई में सम्मेलन अनुसंधानकर्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों और सरकारी नेताओं को अभूतपूर्व नवाचारों को प्रदर्शित करने और अत्याधुनिक अनुसंधान को साझा करने के लिए एकजुट करता है। सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करते हुए, यह कार्यक्रम एच पी सी, ए आई और क्वांटम तकनीकी में कम्प्यूटेशनल विज्ञान और इंजीनियरिंग की प्रगति को बढ़ावा देता है।

इस आयोजन में अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग में ज्ञान, सहयोग और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला होगी। इनमें ट्यूटोरियल और कार्यशालाएं, मुख्य टिप्पणियाँ, पूर्ण वार्ता और विशेषज्ञ पैनल, एच पी सी, ए आई और क्वांटम में समानांतर सत्र, चिप डिजाइन कॉन्क्लेव, एन एस एम शिखर सम्मेलन, वीमेन इन टेक्नोलॉजी (एच पी सी, ए आई और क्वांटम), डॉक्टरेट संगोष्ठी, प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी, नेटवर्किंग और उद्योग राउन्ड टेबल, सहयोग मंच और बड्र्स-ऑफ-ए-फेदर सत्र शामिल हैं- जो पेशेवरों और शोधकर्ताओं को सुपरकंप्यूटिंग, ए आई और क्वांटम तकनीकी में सबसे आगे रहने के अवसर प्रदान करते हैं।

एस सी आई 2025 उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग (एच पी सी) के भविष्य और ए आई और क्वांटम तकनीकी के साथ इसके अभिसरण का खाका तैयार करने के लिए विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, उद्योग जगत के नेताओं, नवप्रवर्तकों और शिक्षाविदों के एक प्रतिष्ठित वैश्विक समुदाय को एक साथ लाएगा।

ग्रीन पटाखों की इजाजत पर मार्केट में खरीदारों की रौनक बढ़ेगी - परमजीत सिंह पम्मा

मुख्य संवाददाता

दिल्ली 15 अक्टूबर सदर बाजार: माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिवाली के उपलक्ष पर ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत देने के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। यह निर्णय न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि यह हमारे त्योहारों को मनाने के अधिकार को भी बरकरार रखता है।

सदर बाजार बारी मार्केट के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने इस निर्णय के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया है। उनका कहना है कि यह निर्णय न केवल हमारे शहर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाएगा, बल्कि यह हमारे त्योहारों को भी खुशियों से भर देगा।

पम्मा ने कहा ग्रीन पटाखे न केवल पर्यावरण अनुकूल हैं, बल्कि वे हमारे त्योहारों को भी रंगीन और आकर्षक बनाते हैं। हमें उम्मीद है कि यह निर्णय हमारे शहर को एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाएगा।

पम्मा ने कहा दिवाली का त्योहार रोशनी, मिठाई व पटाखों से ही मनाया जाता है इससे मार्केट में खरीदारों की और रौनक बढ़ेगी और दिवाली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा।

नारायण ने किया इंडियन आइडल में अपने नए रोल का खुलासा

सुषमा रानी

भारत का सबसे आइकॉनिक सिंगिंग रियलिटी शो, इंडियन आइडल, अपने नए सीजन के साथ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर लौट रहा है। इस बार शो का दिल को छूने वाले थीम ₹यादों की प्लेलिस्ट₹ यादों और संगीत की लहर लेकर आया है। ऐसे में, अब जाने माने सिंगर उदित नारायण ने इंडियन आइडल के नए सीजन में चौथे जज के रूप में जुड़ने की अटकलों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उदित नारायण ने साझा किया*, "मुझे मेरे लिए मिल रहे सभी प्यार से सच में बहुत खुशी हो रही है, और यह जानकर अच्छा लग रहा है कि लोग मुझे इंडियन आइडल के जज पैनल पर देखने के लिए उत्साहित हैं। लेकिन मैं साफ करना चाहता हूँ, इस सीजन में मैं कुछ बिल्कुल अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। सालों तक, मैं इंडियन आइडल में मेहमान के रूप में आया और हमेशा प्यार मिला। लेकिन यह पहली बार है कि एक पिता अपने बेटे के जूते में कदम रखेगा, आमतौर पर यह उल्टा होता है! आदित्य भी इसके लिए उत्साहित है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसे पसंद करेंगे!" यह सीजन पुराने समय के गानों के साथ आज के टैलेंट को जोड़ने का वादा करता है। यह भारतीय संगीत की आवाज़ों का एक शानदार जश्न होगा, जिसमें भावनाओं, यादों और बेहतरीन टैलेंट की एक खूबसूरत यात्रा दिखाई देगी। इंडियन आइडल का नया सीजन देखें 18 अक्टूबर 2025 से, हर शनिवार और रविवार रात 8:00 बजे, सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न और सोनी लिव पर।

श्रीपंचमुखी हनुमान मंदिर में धूमधाम से मनाया गया श्रीहनुमद् आराधन मण्डल का 14 वां वार्षिकोत्सव

डॉ. गोपाल चतुर्वेदी

वृन्दावन। अक्रूर ग्राम स्थित प्राचीन श्रीपंचमुखी हनुमान मंदिर में श्रीहनुमद् आराधन मण्डल के द्वारा मण्डल का चौदहवां वार्षिकोत्सव अनेक प्रख्यात संतों-विद्वानों एवं धर्माचार्यों की सन्निधि में अत्यन्त श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम श्रीहनुमानजी महाराज की प्रतिमा का वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य पूजन-अर्चन किया गया।साथ ही उनकी 108 बत्तियों से महाआरती की गई।तत्पश्चात संगीतमय सामूहिक सुंदरकांड का सस्वर पाठ किया गया।इसके अलावा श्रीहनुमानजी की झाकी नृत्य की अत्यंत मनमोहक व चित्ताकर्षक प्रस्तुति दी गई।

महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली विशिष्ट विभूतियों का श्रीहनुमद् आराधन मण्डल के संरक्षक डॉ. मनोज मोहन शास्त्री, अध्यक्ष अशोक व्यास एवं कोषाध्यक्ष आचार्य विपिन बापू आदि ने अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह, ठाकुरजी का छवि चित्र व पटुका-प्रसादी-माला आदि भेंट करके सम्मान किया।

इस अवसर पर जगद्गुरु पीपाद्वाराचार्य बाबा बलरामदास देवाचार्य महाराज, जगद्गुरु श्रीमद्विष्णुस्वामी विजयराम देवाचार्य भैयाजी महाराज (बल्लभगढ़ वाले), गौ ऋषि सन्त कृष्णानंद महाराज (भूरी वाले), विश्वविख्यात भागवताचार्य कृष्ण चंद्र शास्त्री ठाकुरजी महाराज, रयूपी रत्नर डॉ. गोपाल चतुर्वेदी, सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा, मथुरा-वृन्दावन नगर निगम के उप-सभापति मुकेश सारस्वत, प्रमुख भाजपा नेता पण्डित योगेश द्विवेदी, जगदीश ठाकुरजी, रासाचार्य राम वल्लभ शर्मा, आचार्य अश्विनी मिश्रा, पद्मनाभ शास्त्री, प्रमुख शिक्षाविद् प्रमोद गौतम, डॉ. अशोक शास्त्री, उमाशक्ति पीठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज नारायण द्विवेदी (राजू भैया), आचार्य युगल किशोर कटारे, पण्डित बिहारीलाल शास्त्री, आचार्य श्रीराम मुद्गल, स्वामी रामशरण शर्मा, स्वामी प्रेमशरण शर्मा, आचार्य विनय त्रिपाठी, आचार्य बुद्धिप्रकाश शास्त्री, श्रीमती मीरा शास्त्री, भागवत विदुषी कीर्ति किशोरी, श्रीहरि वर्षा कौशल, श्रीमती विनीता द्विवेदी, आचार्य ऋषि तिवारी, रसिया बाबा, सुरेश चन्द्र शास्त्री, डॉ. राधाकांत शर्मा, युवराज श्रीधराचार्य, संजीव कृष्ण ठाकुरजी महाराज, अभिषेक कृष्ण शास्त्री, संगीताचार्य बनवारी महाराज, आचार्य नेत्रपाल शास्त्री, डॉ. रमेश चंद्राचार्य विधिशास्त्री, आचार्य राजेश किशोर गोस्वामी, चैतन्य किशोर कटारे, देशी टार्जन पहलवान संजय सिंह, श्याम सुन्दर ब्रजवासी, स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज, आचार्य शिवम साधक, प्रमोद कुमार जालान, महेश भारद्वाज, सुरेश चन्द्र शर्मा, आदि के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।संचालन डॉ. मनोज मोहन शास्त्री ने किया।

महोत्सव का समापन संत ब्रजवासी वैष्णव सेवा एवं वृहद भंडारे के साथ हुआ।जिसमें हजारों भक्तों-श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया।

मालगाड़ी पटरी से उतरने से कानपुर में घंटों ठप रहा रेल यातायात अब सामान्य

सुनील बाजपेई

कानपुर। यहां बीती रात पनकी यार्ड के पास एक मालगाड़ी के दो पहिये पटरी से उतर जाने से दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग घंटों बाधित रहा। फिलहाल समाचार लिखे जाने तक रेल परिचालन पहले की तरह पटरी पर लौट आया है। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान राजधानी, गरीब रथ, श्रम शक्ति एक्सप्रेस, पुष्पक और महाबोधि एक्सप्रेस सहित तीन दर्जन से अधिक ट्रेन विलंब से चलीं। अधिकारियों के मुताबिक जांच के लिए एक समिति गठित की गई है और जांच के बाद ही घटना के असल कारण का पता लग सकेगा। बताया गया कि पनकी यार्ड में यह घटना उस समय हुई जब माल उतारकर लौट रही मालगाड़ी को उत्तर से दक्षिण लाइन पर भेजा जा रहा था। इसी दौरान पटरी के क्रॉसओवर (कैंची) बिंदु से गुजरते वक्त उसके दो पहिये पटरी से उतर गये साथ दी इंजन भी अचानक रुक गया। जिसकी वजह से एक बड़ा या हादसा भी होने से टल गया। इसकी सूचना मिलते ही बचाव एवं तकनीकी दल घटनास्थल पर पहुंचे । फिलहाल रात लगभग साढ़े 12 बजे तक तीसरी और चौथी लाइन पर आवाजाही फिर से शुरू कर दी गई ताकि फंसी हुई यात्री रेलगाड़ियों को निकाला जा सके। फिलहाल समाचार लिखे जाने तक रेल यात्रा यार सामान्य हो जाने का दावा किया गया है।

थाना मूसाझाग पुलिस की सांठ-गांठ में फल फूल रहा है अवैध खनन माफियाओं का कारोबार

सूचना पर खनन विभाग अधिकारी ने छापा मार कर दो ट्रैक्टर व एक जेसीबी को पकड़ा

परिवहन विशेष न्यूज

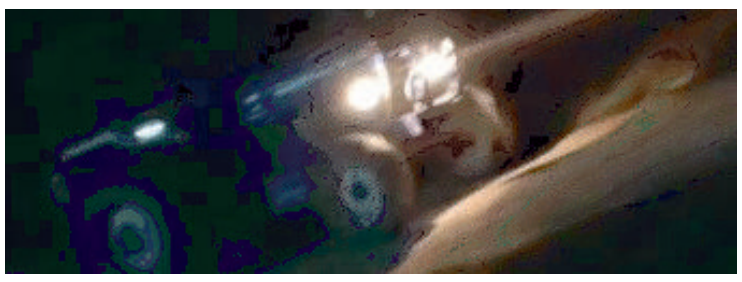

मूसाझागः यह खबर अवैध खनन के कारोबार में पुलिस की सांठगांठ की ओर इशारा करती है, जिसके कारण माफियाओं का कारोबार फलता-फूलता है। इसी संदर्भ में, खनन विभाग के अधिकारियों ने एक सूचना पर छापा मारा, जिसमें उन्होंने दो ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन को पकड़ा है।

यहां आपको बताते चले मामला बदायूं जिले के मूसाझाग थाने के धीमरी गांव के पास अवैध मिट्टी खनन करते हुए दो ट्रैक्टर और एक जेसीबी को जब्त कर सीज कर दिया गया है। बदायूं के तेज तर्रार खनन विभाग अधिकारी गुलशन कुमार ने यह कार्रवाई प्राकृतिक मिट्टी के टीले की खुदाई के दौरान की। जब्त किए गए वाहनों को मूसाझाग थाना परिसर में खड़ा कराया गया है।

बताया जा रहा है कि मूसाझाग थाना क्षेत्र में खेत खलिहानों से इन दिनों अवैध मिट्टी खनन कार्य जोरों पर है, जिसकी वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। खनन माफिया इतने हावी हैं कि इन पर पुलिस प्रशासन व उच्च अधिकारियों का भी असर नहीं पड़ रहा है। खनन माफिया रात्रि की आड़ में खेत खलिहानों से निकाली गई मिट्टी को अवैध रूप से बेच रहे हैं।

मंगलवार देर रात्रि खनन विभाग नव नवागत और तेज तर्रार अधिकारी गुलशन कुमार को अवैध खनन की सूचना मिली थी। इसके बाद बदायूं खनन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। खनन कर निकाली गई मिट्टी को लेकर रुखड़ा खोला मार्ग पर धीमरी गांव के मोड़ के पास प्लांटिंग में भराई के लिए ले जाया जा रहा था।

अधिकारियों ने मिट्टी का अवैध खनन कर रहे जेसीबी बा ट्रैक्टर संचालक सरदार सतनाम से रवन्ना, रॉयल्टी और खनन की अनुमति से संबंधित दस्तावेज दिखाने को कहा। कोई वैध कागजात प्रस्तुत न कर पाने पर दोनों ट्रैक्टर और एक जेसीबी को जब्त कर मूसाझाग थाने लाया गया।

बदायूं खनन विभाग अधिकारी गुलशन कुमार ने बताया की इस मामले में कार्रवाई की गई है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीनों वाहनों को जब्त कर थाना मूसाझाग पुलिस की सुपुर्दगी में कर दिया गया है।

हरियाणा को बचाना है, तो नफरत को हराना होगा।

(संकट का समय है साथियो — नफरत नहीं, भरोसा ज़रूरी है। समझदारों को आगे आना होगा। राजनीति नहीं, संवेदना चाहिए। हमारे समाज की असली ताकत है— भाईचारा। यह दो जातियों की नहीं, दो इंसानों की त्रासदी है।)

दो पुलिसकर्मियों की आत्महत्याएँ हरियाणा के लिए चेतावनी हैं। यह जातीय टकराव नहीं, व्यवस्था पर से भरोसे का टूटना है। समाज को अब संयम और समझ की जरूरत है। नफरत फैलाने से इंसाफ़ नहीं मिलेगा, बल्कि हालात और बिगड़ेंगे। जरुरी है कि व्यवस्था पारदर्शी और न्यायसंगत बने, लोगों में विश्वास लौटे और संवाद कायम रहे। समझदारों को आगे आकर नफरत को हराना होगा — तभी भाईचारा बचेगा और हरियाणा मजबूत बनेगा।

- डॉ. प्रियंका सौरभ

हरियाणा इस समय गहरे संकट से गुज़र रहा है। एक नहीं, दो पुलिसकर्मियों की आत्महत्याएँ हमारे समाज, हमारी व्यवस्था और हमारी सोच — तीनों पर सवाल उठा रही हैं। इंसाफ़ का रास्ता जब लोगों को बंद दिखाई देता है, तो वे ज़िंदगी से भी हार मान लेते हैं। यह सिर्फ दो जवानों की मौत नहीं, बल्कि उस तंत्र की पराजय है, जिस पर नागरिक भरोसा करते हैं।

आज जब चारों ओर गुस्सा, अफ़वाहें और जातीय बहसें हैं, तब सबसे ज़रूरी है संयम और समझ। क्योंकि अगर समाज भावनाओं में बह गया, तो यह सिर्फ दो परिवारों की त्रासदी नहीं रहेगी, बल्कि हरियाणा का सामाजिक ताना-बाना टूट जाएगा।

दोनों आत्महत्याएँ दिल को झकझोर देने वाली हैं। आईपीएस पूरन कुमार की मौत ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था, और फिर एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या ने इस दर्द को और गहरा कर दिया। दोनों ने अपने वीडियो या संदेशों में जो दर्द व्यक्त किया, वह किसी जातीय नफ़रत का परिणाम नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था के प्रति मोहभंग का परिणाम था जिसमें उन्हें इंसाफ़ का रास्ता दिखाई नहीं दिया।

हर आत्महत्या एक चीख़ होती है — ऐसी चीख़ जो कहती है कि "सुनो, अब और नहीं!" और जब सरकारी सिस्टम से जुड़े लोग ख़ुद अपनी जान दे देते हैं, तो यह संकेत होता है कि भीतर कुछ बहुत गंभीर रूप से सड़ चुका है।

आज सोशल मीडिया और राजनीति दोनों इस मामले को जातीय चश्मे से देखने में लगे हैं। कोई इसे एक जाति बनाम दूसरी जाति के संघर्ष की तरह दिखा रहा है, तो कोई इसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है — यह दो जातियों की नहीं, दो इंसानों की त्रासदी है।

पूरन कुमार और संदीप लाठर, दोनों ही अपने-अपने परिवारों, अपने-अपने समाजों और अपनी-अपनी ड्यूटी के लिए समर्पित थे। दोनों का उद्देश्य था न्याय और आत्मसम्मान। परंतु जब व्यवस्था में उन्हें विश्वास नहीं मिला, तो उन्होंने वह रास्ता चुना, जो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए सबसे दर्दनाक होता है।

हमें समझना होगा कि अगर हम इन घटनाओं को जातीय बहस में बदल देंगे, तो असली मुद्दा — व्यवस्था में गिरता विश्वास — हमेशा के लिए दब जाएगा। ऐसा करना न केवल इन आत्महत्याओं की पीड़ा का अपमान होगा, बल्कि यह समाज को और गहरे अंधकार में धकेल देगा।

हर आत्महत्या के पीछे एक कहानी होती है — कभी चुप रह जाने की, कभी आवाज़ न सुने जाने की, और कभी अन्याय से लड़ते-लड़ते थक जाने की। पूरन कुमार और संदीप लाठर की मौतें इसी थकान का परिणाम हैं। दोनों के पास शायद अभी बहुत वक्त था, बहुत संभावनाएँ थीं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी उस वक्त ख़त्म की जब उन्हें लगा कि अब उनकी बात कोई नहीं सुनेगा।

यही सबसे ख़तरनाक स्थिति होती है — जब कोई नागरिक यह मान ले कि व्यवस्था अब उसके लिए नहीं बनी। और जब लोग न्याय की उम्मीद छोड़ देते हैं, तब समाज अराजकता की ओर बढ़ता है।

इतिहास गवाह है कि जब भी समाज ने नफरत के रास्ते पर चलना शुरू किया, उसने ख़ुद को कमजोर किया। चाहे वह धर्म के नाम पर हो, भाषा के नाम पर हो या जाति के नाम पर — अंत में नुकसान हर बार समाज को ही हुआ है।

अगर आज हम इस दर्दनाक घटना को जातीय टकराव की शक्ल देंगे, तो हम फिर उसी पुराने गड्ढे में गिर जाएंगे, जिससे निकलने में हमें दशकों लगे। नफरत का जवाब नफरत नहीं हो सकता। इसका जवाब है — संवाद, सुधार और सहानुभूति।

हरियाणा पुलिस, प्रशासन और सरकार — सभी को अब आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। सवाल यह नहीं है कि कौन किस जाति से था, बल्कि यह कि क्यों एक अफ़सर और एक एएसआई को आत्महत्या जैसा कदम उठाने की नौबत आई? क्या हमारे सिस्टम में शिकायत दर्ज करने और सुनवाई की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि कोई अधिकारी भी न्याय की उम्मीद खो देता है? क्या हमारे उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं? क्या हमारे समाज में किसी की परेशानी को समझने का धैर्य ख़त्म हो गया है?

इन सवालों के जवाब ढूँढना ज़रूरी है। क्योंकि अगर यह सिस्टम दो अपने अफ़सरों का दर्द नहीं सुन पाया, तो आम जनता का क्या हाल होगा? सुधार वहीं से शुरू होता है जहाँ गलती स्वीकार की जाए। और यह समय वही है — गलती स्वीकार कर सुधार का रास्ता चुनने का।

दोनों आत्महत्याएँ एक सन्देश छोड़ गई हैं — कि व्यवस्था पर विश्वास लौटाना अब सबसे बड़ा सामाजिक कार्य है। पुलिस विभाग, प्रशासनिक तंत्र, मीडिया और समाज — सभी को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना होगा, जहाँ कोई व्यक्ति यह न सोचे कि उसकी आवाज़ दब जाएगी। भरोसा तभी लौटेगा जब न्याय तेज़ और निष्पक्ष हो, जांच पारदर्शी हो, राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हो। संवेदनशील नेतृत्व सामने आए जो केवल बयान न दे, बल्कि संस्थागत सुधार करे। मीडिया जिम्मेदारी निभाए जो सनसनी नहीं, सच्चाई दिखाए। और समाज संयम रखे जो अफवाहों और जातीय टिप्पणियों से दूर रहे।

भरोसा एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक गलत फैसले से वह पल में टूट जाता है। अब समय है उसे फिर से जोड़ने का। हर समाज में कुछ लोग होते हैं जो कठिन समय में दिशा दिखाते हैं। आज हरियाणा को ऐसे ही समझदार साथियों की जरूरत है — जो नफरत की आग में घी डालने के बजाय पानी डालें।

यह वक्त है कि हम सब मिलकर इस पीड़ा को जातीय नहीं, मानवीय नजरिए से देखें। समाज को समझाना होगा कि जो मरे हैं, वे किसी जाति के नहीं, इस प्रदेश के बेटे थे। उनकी मौत से अगर हमें कुछ सीखना है, तो वह यही कि कभी भी न्याय और संवाद के रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। इन घटनाओं के बाद कुछ राजनीतिक बयान आए — किसी ने कहा दोषी फलां जाति का है, किसी ने कहा जांच पक्षपातपूर्ण है। परंतु राजनीति का यही घेरा समाज में जहर घोल देता है। जरूरत इस समय बयानबाजी की नहीं, बल्कि संवेदना की है। राजनीति के बजाय अगर नेता व्यवस्था सुधार की मांग करें, तो यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि जो मरे हैं, वे राजनीति के लिए नहीं, न्याय के लिए लड़े थे।

हरियाणा की पहचान उसकी मेहनतकश जनता, किसानों, जवानों और भाईचारे से रही है। अगर हम जातीय विभाजन में बँट गए, तो यह ताकत खो जाएगी। हमें याद रखना होगा — जो समाज नफरत में उलझता है, वह विकास में पिछड़ जाता है।

इसलिए यह वक्त नफरत के खिलाफ खड़े होने का है। जो लोग सोशल मीडिया पर उकसाने वाली बातें फैला रहे हैं, उन्हें पहचानिए और उनसे दूरी बनाइए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए — हरियाणा को एक बार फिर भरोसे, एकता और शांति की राह पर लाना।

किसी समाज की परिपक्वता का पैमाना यह नहीं होता कि उसके पास कितनी ताकत या संपत्ति है, बल्कि यह होता है कि वह अपने पीड़ितों के प्रति कितना संवेदनशील है। आज अगर हम इन आत्महत्याओं को एक सबक की तरह लें और अपने संस्थानों को संवेदनशील बनाएं, तो यह इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

हमें ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि उसे न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार जरूरी है। अफसरों की समस्याओं को सुनने और सुलझाने के लिए स्वतंत्र शिकायत मंच बने। पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य परामर्श की व्यवस्था हो। नेतृत्व ऐसा हो जो अपने अधीनस्थों को परिवार की तरह समझे। समाज में संवाद बढ़े और जातीय दूरी घटे।

जब तक ये सुधार नहीं होंगे, तब तक हर आत्महत्या के साथ हमारा सामाजिक संतुलन थोड़ा और टूटता जाएगा। पूरन कुमार और संदीप लाठर की आत्महत्याएँ हमारे लिए गहरा सबक हैं। यह जातीय नहीं, मानवीय त्रासदी है। यदि हम इसे जातीय रंग देंगे, तो हम उनके बलिदान को अपमानित करेंगे।

हमें उनका संदेश समझना होगा — न्याय, सुधार और भाईचारा ही आगे बढ़ने का रास्ता है। आज हरियाणा के हर नागरिक से एक ही अपील है — संकट के समय में संयम रखिए। अफवाहों और नफरत से दूर रहिए। क्योंकि नफरत पर आधारित समाज कभी सुखी नहीं होता। समझदार साथियों को आगे आकर इस नफरत को हराना होगा और भरोसे की नींव फिर से मज़बूत करनी होगी। तभी हम उस हरियाणा को बचा पाएँगे, जो मेहनत, एकता और आपसी प्रेम की पहचान रहा है।

रोजगार विभाग हरियाणा के सक्षम योजना पोर्टल पर फर्जी मार्कशीट पर बर्खास्त हुई दोषी महिला सुनील कुमारी के दो-दो पद

परिवहन विशेष न्यूज़पेपर द्वारा 17 मार्च को प्रकाशित खबर से मची थी रोजगार विभाग हरियाणा के अंदर खलबली ।

परिवहन विशेष न्यूज़ पेपर द्वारा प्रकाशित खबर का हुआ था, हरियाणा राज्य के रोजगार विभाग में असर ।

दोषी महिला सुनील कुमारी अपने टर्मिनेशन के खिलाफ माननीय पंजाब एवं हरियाणा चंडीगढ़ में गई थी अंतरिम राहत पाने के लिए , माननीय अदालत द्वारा प्रदान नहीं की गई अंतरिम राहत।

टोहाना/फतेहाबाद,

आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि एम ए मनोविज्ञान की पूर्णतयाः फर्जी मार्कशीट पर सहायक रोजगार अधिकारी व्यावसायिक मार्गदर्शन की नौकरी हासिल करने वाली दोषी महिला सुनील कुमारी को रोजगार विभाग हरियाणा ने साक्षम पोर्टल पर नंबर 3 मण्डल रोजगार कार्यालय/अधिकारी में तो सहायक रोजगार अधिकारी का पद दर्शाया हुआ है, लेकिन विडंबना देखिए इस दोषी महिला सुनील कुमारी को पोर्टल पर नंबर 5 जिला रोजगार कार्यालय/अधिकारी मैं जिला रोजगार अधिकारी का पद दर्शाया हुआ है।

उन्होंने कहा कि दोषी माहिला सुनील कुमारी अपने टर्मिनेशन के खिलाफ माननीय पंजाब एवं हरियाणा चंडीगढ़ में भी अंतरिम राहत पाने के लिए गई थी, वहां पर भी उन्हें किसी प्रकार की कोई भी अंतरिम राहत माननीय अदालत द्वारा प्रदान नहीं की गई है ।

उन्होंने आरोप लगाया कि दोषी महिला सुनील कुमारी के खिलाफ आज तक रोजगार विभाग हरियाणा के उच्च अधिकारियों द्वारा ना तो आज तक किसी प्रकार की कोई भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है, और ना ही रिकवरी के लिए किसी प्रकार का कोई भी नोटिस जारी किया गया है ।

सत्य वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो- जिंदगी भर आनंद पाओ, झूठ वह कर्ज़ है- क्षणिक सुख पाओ जिंदगी भर चुकाते रहो

सच्चाई की राह, सुखद जीवन के लिए विनियोग- झूठ का गंतव्य दुखी जीवन की चरम सीमा-

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

भारत अपनी संस्कृति, आध्यात्मिकता, अहिंसा धर्मनिरपेक्षता,परमो धर्मा और सच्चाई की मूरत राजा हरिश्चंद्र इत्यादि अनेकों विशेषताओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र से यह मानता हूं कि एक झूठ के पीछे सव झूठ बोलना पड़ता है और झूठ के दलदल में मनुष्य घुसता चला जाता है।जिससे उसकी वर्तमान पीढ़ी तो ध्वस्त होती ही है पर आने वाली पीढ़ियों में भी यह दोष समाया रहता है।

साथियों बात अगर हम सच्चाई की साक्षात मूरत राजा हरिश्चंद्र की करें तो,सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सदैव सत्य बोलते थे। वह अपने सत्य और न्याय के लिए जाने जाते थे। इसलिए आज भी उनकी कहानियां बड़े सम्मान के साथ सुनाई जाती हैं।हमने अपने बड़े बुजुर्गों से अनेक कई किस्से सुने हैं।हम,आज की जनरेशन करीब-करीब हर सच्चाई वाली बात में इस महान मूरत का नाम ज़रूर जोड़तेहैं।हमारे बड़े बुजुर्गों से हमने कई वाक्य सुने हैं, जैसे सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सत्य की हार नहीं होती,सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं,सत्यमेव जयते।

साथियों बात अगर हम सत्यमेव जयते इसकी करें तो हम अनेक शासकीय,अशासकीय स्थानों पर इसका उल्लेख ज़रूर देखते हैं।यही सत्य है कि हमेशा सत्य की विजय होती है।

साथियों बात अगर हम भारतीय आध्यात्मिकता की करें तो हमें यही ज्ञान मिलता है कि सत्य व दौलत है जैसे पहले खर्च करो फिर जिंदगी भर आनंद पाओ और झूठ वह कर्ज है जिससे क्षणिक सुख पाओ और जिंदगी भर उसे चुकाते रहो बिल्कुल सत्य वचन !साथियों यह बात अगर मानव के हृदय में बस जाए तो वाह क्या बात है !हम पृथ्वी लोक में ही स्वर्ग के दर्शन कर सकेंगे।अगर हर भारतीय व्यक्ति चाहे वह सरकारी हो या शासकीय कर्मचारी, मंत्री हो या नेता, कार्यकर्ता हो या मालिक,सभी अगर सत्यता रूपी दौलत को पूरी निष्ठा से खर्च करें अर्थात ईमानदारी से अपनी अफसर शाही ड्यूटी, व्यापार-व्यवसायज दिनचर्या अर्थात जीवन के हर काम हर मोड़ पर सत्यता बरसाएगें तो वह खुद तो जीवन का आनंद जरूर पाएंगें परंतु उससे अधिक भारत को स्वर्ग जैसा सुंदर रचना बनाने में अहम रोल अदा करेगें। भारत एक अपराध मुक्त भारत की परिकल्पना में साकार होगा।कोई अदालत, पुलिस स्टेशन,जांच एजेंसियां नहीं होगी क्योंकि यह सब झूठ और अपराध को काटने के लिए ही बनाई गई हैं।

साथियों बात अगर हम झूठ की करें तो हमने अपने व्यवहारिक जीवन में देखा होगा कि बेईमान, रिश्वतखोर, झूठा, भ्रष्टाचारी, धोखेबाज इत्यादि तरह के मानव कभी अपने जीवन में सुखी नहीं होते। चाहे कितना भी अवैध धन कमा लें,उनके पीछे परिवार का, उनके स्वास्थ्य का, मानसिक हालत हमेशा दुखों में बनी रहती हैउनके शरीर के नसों में झूठ रूपी खून दौड़ता है और इन नकारात्मक झूठे व्यवहारों से उनका क्षणिक आर्थिक सुख मिलता है परंतु उसके लिए उनको जीवन भर कष्टों में गुजारना पड़ता है। जितना क्षणिक सुख प्राप्त होता है वह ब्याज सहित याने अतिरिक्त दुख सहित यहीं इस जीवन में भोगना पड़ता है और फिर अंत में पछताते हैं के ऐसा क्यों हुआ,ऊपर वाले से क्षमा याचना करते हैं।पर कहते हैं ना कि जब चिड़ियां चुग गई खेत,अब पछतावे क्या होए??

साथियों बात अगर हम सत्य की गहराई की करें तो,सत्य दो प्रकार का होता है- एक व्यवहारिक सत्य और दूसरा वास्तविक। व्यवहारिक सत्य का अर्थ है जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा अनुभव किया, उसको वैसा ही बोलना सत्य कहलाता है।व्यवहारिक सत्य में हो सकता है, जो एक के लिए सत्य है, वो दूसरे के लिए असत्य हो। वैसे तो हर व्यक्ति अपने मुताबिक अपना सत्य बना लेता है। यह व्यवहारिक सत्य, अनुभव, नजरिए और देश, काल के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। इसलिए इसमें मतभेद की संभावना बनी रहती है।ईमानदार और न्यायवादी व्यक्ति ही सत्य का पालन करता है।यह देखा गया है कि जो लोग ईमानदार होते हैं वह सदैव सच बोलते हैं। झूठे बेईमान और मक्कार लोग सदैव असत्य का फायदा लेकर अपना काम बनाते हैं। हम ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो अपने फायदे के लिए (झूठ) असत्य बोलते हैं।सत्य का अर्थ है 'सते हितम्' अर्थात जिसमें हित या कल्याण निहित हो। सत्य भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों काल में एक सा रहता है तथा इससे यथार्थ का ज्ञान होता है। साधारण बातचीत में जो सच है, यथार्थ है उसे जानना, समझना, मानना, कहना एवं उसके अनुसार ही व्यवहार करना सत्य है। मानव बोध में सत्य के प्रति श्रद्धा एवं असत्य के प्रति घृणा स्वाभाविक रूप से पाई जाती है।मनुष्य जीवन के लिए सत्य सबसे बड़ी शक्ति हैं।जीवन तथा संसार के सत्य की तलाश कर उसे जीवन में अपनाना मानव मात्र का मूल उद्देश्य हैं।हमारी संस्कृति में सत्य को बड़ा महत्व दिया गया हैं।इस सम्बन्ध में एक महापुरुष ने ठीक ही कहा कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं. भारत की भूमि पर हरिश्चन्द्र जैसे राजा हुए जिनकी सत्यनिष्ठा के चलते वे सत्यवादी कहलाए।सत्य के रास्ते पर चलकर व्यक्ति बड़ी-बड़ी समस्या का समाधान आसानी से कर सकता है।सत्य के मार्ग पर चलकर कई लोगों ने सफलता प्राप्त कर अपना और अपने परिवार का भला किया है।सत्य के मार्ग पर चलकर कई लोगों ने सफलता प्राप्त कर दुनिया को बदला है । सत्य बोलने से व्यक्ति को सभी सम्मान देते हैं।ऐसा कहा जाता है कि तीन चीजें छुपाए नहीं छुपती- सूरज, चंद्रमा और सत्य। जो लोग सत्य का, न्याय का पक्ष लेते हैं उनकी प्रशंसा सभी लोग करते हैं।सत्य का साथ देने वालों को इतिहास स्वर्णिम पन्नों पर दर्ज करता है। परंतु जो लोग झूठ,असत्य का साथ देते हैं उनकी चारों ओर आलोचना होती है।किसी ने खूब ही कहा है कि

चन्द्र टरै, सूरज टरै, टरै जगत व्यवहार।'

पै दृढ़ हरिश्चन्द्र को टरै न सत्य विचार।..

सांच बराबर तप नहीं, झूंठ बराबर पाप।

जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप

किसी ने धर्म के दस लक्षण बताए हैं, जिनमें सत्य भी प्रमुख स्थान रखता है।

'धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिनद्रियनिग्रहः। धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्।।'

अर्थात धैर्य, क्षमा, संयम, अस्तेय (चोरी न करना), शौच (अंतर्मन और शरीर की पवित्रता), इन्द्रिय निग्रह (इन्द्रियों से धर्म सम्मन आचरण), धी (सत्बुद्धि), विद्या, सत्य एवं अक्रोध यानी हमेशा शांत रहना।

अतः अगर हम पूरे उपरोक्त विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करेंगे तो हम पाएंगे के सत्य व दौलत है जिसे पहले खर्च करो फिर जिंदगी भर आनंद पाओ और झूठ वह कर्ज है जिसमें सैनिक सुख पाओ फिर जिंदगी भर जो करते रहो और सच्चाई की राह सुखद जीवन के लिए एक विनियोग है तथा झूठ का गंतव्य दुखी जीवन की चरम सीमा है।

स्लाइट में ए.एफ.एस.टी.आई. राष्ट्रीय फूड सम्मेलन 2025 की शुरुआत

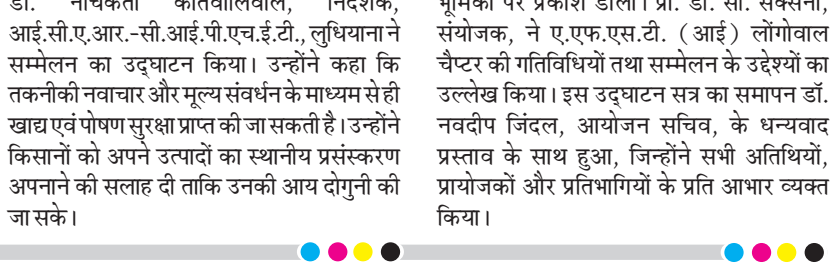

परिवहन विशेष न्यूज

लोंगोवाल, (जगसीर सिंह) - संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी), लोंगोवाल में आज से दो दिवसीय रराष्ट्रीय फूड सम्मेलन 2025र का शुभारंभ हुआ। यह आयोजन एसोसिएशन ऑफ फूड साइंटिस्ट्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट्स (इंडिया) के तत्वावधान में किया जा रहा है। सम्मेलन में देशभर के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और युवा शोधकर्ताओं ने भाग लिया। लगभग 27 संस्थानों और विश्वविद्यालयों से 100 से अधिक प्रतिनिधि मौखिक एवं पोस्टर सत्रों के माध्यम से अपने शोध प्रस्तुत कर रहे हैं। विश्व खाद्य दिवस 2025 की थीम रबेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथों में हाथ पर आधारित यह सम्मेलन रसतत खाद्य प्रणालियाँ, नवाचार और पोषण-सुरक्षित भविष्यर विषय पर केंद्रित है। मुख्य अतिथि डॉ. नचिकेता कोतवालिवाले, निदेशक, आई.सी.ए.आर.-सी.आई.पी.एच.ई.टी., लुधियाना ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि तकनीकी नवाचार और मूल्य संवर्धन के माध्यम से ही खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने किसानों को अपने उत्पादों का स्थानीय प्रसंस्करण अपनाने की सलाह दी ताकि उनकी आय दोगुनी की जा सके।

विशिष्ट अतिथि डॉ. राकेश शारदा, परियोजना समन्वयक, ए.आई.सी.आर.पी. ने प्लास्टिक के संतुलित एवं दक्ष उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया जिससे संसाधन दक्षता और फसलोत्तर प्रबंधन में नवाचार को प्रोत्साहन मिल सके। संस्थान के निदेशक एवं सम्मेलन के संरक्षक प्रमुख डॉ. मणिकांत पासवान ने ए.एफ.एस.टी.आई की उन पहलों की सराहना की जो विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों को जोड़ने और खाद्य प्रौद्योगिकी में अंतःविषय सहयोग को बढ़ावा देती हैं। प्रो. सुखचरण सिंह, आयोजन सचिव ने स्वागत भाषण में सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का अभिनंदन किया। प्रो. सी. एस. रियार, विभागाध्यक्ष (फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी) ने विभाग की उपलब्धियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए शिक्षण, अनुसंधान एवं औद्योगिक सहयोग के क्षेत्र में उसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रो. डी. सी. सक्सेना, संयोजक, ने ए.एफ.एस.टी. (आई) लोंगोवाल चैप्टर की गतिविधियों तथा सम्मेलन के उद्देश्यों का उल्लेख किया। इस उद्घाटन सत्र का समापन डॉ. नवदीप जिंदल, आयोजन सचिव, के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ, जिन्होंने सभी अतिथियों, प्रायोजकों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

ग्रीन पटाखों की दीवाली: रोशनी भी, जिम्मेदारी भी

दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर हर दीवाली धुंध का घना परदा छा जाता है, जहां पटाखों की चमक खुशी की बजाय आंसुओं, खांसी और सांस की तकलीफ का सबब बनती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार क्रांतिकारी मोड़ लाकर प्रदूषण और परंपरा के बीच एक संकुचित लेकिन उम्मीद जगाने वाला पुल बांध दिया—18 से 21 अक्टूबर तक केवल एनईईआरआई (नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) प्रमाणित ग्रीन पटाखों को ही हरी झंडी, जो पारंपरिक विस्फोटकों से 30-40% कम धुआं और विषैले गैसें उगलते हैं। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने 10 अक्टूबर को याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया, जिसमें केंद्र व दिल्ली सरकार की अपीलों पर ग्रीन पटाखों की वैज्ञानिक वैधता को कसौटी पर कसते हुए सख्त शर्तें लगाईं। सवाल वही, क्या यह सीमित छूट दिल्ली की जहरीली हवा पर असली प्रहार साबित होगी, या नकली उत्पादों की बाढ़ और ढीली निगरानी में पुरानी त्रासदी दोहराएगी?

ग्रीन पटाखों का विज्ञान सरल लेकिन प्रभावी है—इनमें बेरियम, स्ट्रॉन्शियम जैसी भारी धातुओं की जगह पोटैशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम पाउडर और ग्लाइसरीन जैसे कम विषैले रसायनों का संतुलित मिश्रण होता है, जो धमाके की चमक तो पैदा करता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर (पीएम2.5) का उत्सर्जन न्यूनतम रखता है। एनईईआरआई की कठोर लैब टेस्टिंग के बाद जारी क्यूआर कोड इसकी प्रामाणिकता का चिन्ह है, जिसे वेबसाइट पर स्कैन कर वैधता तुरंत सिद्ध की जा सकती है। अदालत ने बिक्री व जलाने की अनुमति सुबह 6-7 बजे और रात 8-10 बजे तक सीमित रखी, ताकि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पर रातोंरात हमला न हो और सुबह की हवा साफ रह सके। बाहर से पटाखों की आयात पर पूर्ण पाबंदी, नकली उत्पादों पर लाइसेंस तत्काल रद्दीकरण, और बिक्री केवल प्रमाणित दुकानों व कंपनियों से—ये कदम तस्करी के काले बाजार को जड़ से कुचलने का दावा करते हैं।

पुलिस को विशेष गश्ती दलों का गठन करने का सख्त आदेश दिया गया, जो फैक्ट्रियों से लेकर बाजारों तक नियमित छापेमारी करेंगे, जबकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और एनसीआर राज्य बोर्डों को रीयल-टाइम मॉनिटरिंग व दैनिक रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह डेटा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप-जीआरएपी) को सक्रिय करने का आधार बनेगा, जो एक्यूआई के स्तर पर तत्काल कदम सुझाएगा। कानूनी बंधनों से आगे, यह फैसला तकनीकी पारदर्शिता का नया मॉडल रचता है—क्यूआर ट्रैकिंग से ब्लॉकचेन-आधारित सत्यापन प्रणाली उभर सकती है, जो न केवल नकली पटाखों को रोकेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगी।

दिल्ली का प्रदूषण महाकाव्य हर सर्दी में खौफनाक अध्याय जोड़ता है—पराली का घना धुआं, 2 करोड़ वाहनों का काला जहर, 5,000 फैक्टरियों का विषैला सांस, और मौसमी उलटफेर मिलकर एक्यूआई को 500 पार धकेल देते हैं, जो डब्ल्यूएचओ के सुरक्षित 50 माइक्रोग्राम पीएम2.5 मानक से सैकड़ों गुना घातक है। फेफड़ों में जहर घोलते ये कण कैंसर, अस्थमा और लाखों असमय मौतों का सबब बनते हैं। 2017 से सुप्रीम कोर्ट की तलवार चमकी, जब अनुच्छेद 21 के तहत 'स्वच्छ हवा का अधिकार' को मौलिक हक घोषित कर प्रदूषण को संवैधानिक अपराध बना दिया। 2018 का पूर्ण पटाखा बैन, 2019 में ग्रीन पटाखों की संकोचपूर्ण एंट्री, और 2023 की सीमित अनुमति—ये चरणबद्ध क्रांतियां सांस्कृतिक जड़ों को झुकाए बिना स्वास्थ्य संकट से जंग लड़ रही हैं।

दीवाली का सांस्कृतिक महत्व निर्विवाद है। राम की अयोध्या विजय, जहां पटाखों की गर्जना रावण वध की प्रतीक है और रोशनी अमावस्या की काली चादर को चीरती है। लेकिन चिकित्सक चीख-चीखकर चेताते हैं—ग्रीन पटाखे भी पूर्णतः निर्दोष नहीं; इनसे बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड जैसे कार्सिनोजेंस रिसते हैं, जो कैंसर और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) को आमंत्रित करते हैं। पिछले वर्षों के आंकड़े साफ बोलते हैं - ग्रीन अनुमति से एक्यूआई में महज 10-15% गिरावट, जबकि पराली का 40% योगदान ज्यों का त्यों लटका है। अदालत का यह फैसला संतुलन की महीन कला है—गश्ती दलों को ड्रोन और एआई कैमरों से सशक्त बनाकर अवैध फोड़ को जड़ से उखाड़ना, और जनता को लेजर शो, वर्चुअल रियलिटी (वीआर) दीवाली, ड्रोन स्वार्म जैसे डिजिटल चमत्कारों की ओर मोड़ना।

हिमालय-सी ऊंची चुनौतियां दिल्ली पुलिस के सामने हैं: 1.5 लाख जवान कैसे 5 करोड़ की एनसीआर आबादी पर नजर रखें? चाइनीज तस्करी के नकली क्यूआर कोड बाजारों को घेरने के लिए सीमा पर कस्टम चेकपोस्ट, सैटेलाइट इमेजरी और एआई-संचालित ट्रैकिंग अनिवार्य हैं। स्कूलों से मेट्रो स्टेशनों तक क्यूआर स्कैनर कियोस्क लगाएं, जहां ग्रीन पटाखों के फायदे आकर्षक वीडियो में चमकें। व्यापारियों को दोगुनी खुशी—ग्रीन उत्पादों की 20% ऊंची कीमत पर बढ़ती मांग—लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया सरल बनाएं, वरना काला बाजार फलता-फूलता रहेगा।

पराली को बायोगैस प्लांट्स में तब्दील करना, ईवी चार्जिंग नेटवर्क का विस्फोटक विस्तार, फैक्टरियों पर कार्बन टैक्स का प्रहार। ग्रैप स्टेज 4 में स्कूल बंदी, कंस्ट्रक्शन बैन के बावजूद प्रदूषण न थमे, तो पटाखे अकेले बलि का बकरा नहीं। पर्यावरण योद्धा चेताते हैं, ग्रीन पटाखे संक्रमणकालीन सीढ़ी हैं, सच्चा विजय जीरो-एमिशन दीवाली है। वहीं, सांस्कृतिक संरक्षक चिल्लाते हैं—परंपरा कुचलना सामाजिक विद्रोह को जन्म देगा। सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक हस्तक्षेप एमसी मेहता केस 2015 (दिल्ली एनसीआर में 100% अपशिष्ट प्रबंधन) से प्रेरित होकर कार्यपालिका को झकझोर रहा है: अब वक्त है कि हवा का अधिकार कागज से सड़क तक उतरे, वरना दिल्ली का सांस फूलेगा या थम जाएगा?

यह फैसला हर नागरिक के अंतस को झकझोरने वाला आईना है—व्यक्तिगत जिम्मेदारी की चीख! खरीदते वक्त क्यूआर कोड स्कैन कर प्रामाणिकता जांचें, समय-सीमा का कठोर पालन करें, और अतिरिक्त फोड़ से कड़ाई से बाज आएं—क्योंकि एक माचिस की चिंगारी पूरे शहर की सांसें थाम सकती है। समुदायों में 'ग्रीन दीवाली चैलेंज' का तूफान लाएं: कम पटाखे फोड़ने वाले योद्धाओं को सम्मान, पुरस्कार और सोशल मीडिया पर तहलका—जिससे पड़ोसी प्रतिस्पर्धा में उतरें। सरकारें एनईईआरआई जैसे संस्थानों को धन की बाढ़ दें, ताकि नेक्स्ट-जन ग्रीन टेक—शून्य-धुएं वाले लेजर पटाखे या बायो-ल्यूमिनसेंट रोशनी—का जन्म हो। सीपीसीबी की रिपोर्ट यदि चमके, तो अगले साल अनुमति का द्वार चौड़ा खुल सकता है, लेकिन यह चार दिनों की मखमली छूट नहीं, सतत विकास का गर्जन है।

दिल्ली-एनसीआर की दीवाली अब चमक और सांस दोनों की हो सकती है—बशर्ते हम अदालत के आदेश को रगों में उतार लें। नकली धुंध की विषैली चादर फाड़ें, सच्ची रोशनी का सूरज उगाएं, क्योंकि स्वच्छ हवा संवैधानिक हक है—उसका उल्लंघन हत्या के समान अपराध। इस फैसले की लौ से प्रज्वलित होकर पूरे भारत को ग्रीन फेस्टिवल का मॉडल अपनाएं: होली में जैविक रंग, दशहरा में डिजिटल रावण दहन—जहां उत्सव पर्यावरण का साथी बने, दुश्मन न। भविष्य की पीढ़ियां हमें धन्यवाद देंगी कि हमने घातक धुंध को जीवंत चमक में तब्दील किया, न कि अमिट कालिख में दफनाया—यह क्रांति हमारी सांसों की जीत होगी।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी

मारिया की राजनीति और राहुल गांधी की सियासी उलझन

हरीश शिवनानी

वैश्विक राजनीति अक्सर ऐसी जटिल उलझनें पैदा कर देती है जहाँ सिद्धांत और व्यावहारिक राजनीति के बीच का अंतर पेचीदा हो जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार २०२५ विजेता वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो और भारत के कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक दिलचस्प परिदृश्य उत्पन्न हो गया गया है। मारिया अपने देश में सरकार के खिलाफ, लोकतंत्र, मतदान में धांधली, भ्रष्टाचार आदि को लेकर संघर्ष कर रही है। कांग्रेस और राहुल गांधी उनकी इस राजनीति की सराहना करते हैं क्योंकि ऐसा ही वे भारत में अपनी राजनीति में कर रहे हैं। कांग्रेसी मारिया और राहुल को एक ही डाल का पंछी मानते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने तो राहुल गांधी के लिए भी नोबेल की मांग कर डाली। वे मारिया को राहुल गांधी की समर्थक मानते हैं। मारिया ने एक बार राहुल गांधी की तारीफ में ट्वीट भी किया था। दूसरी ओर वास्तविकता यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की सियासत और मारिया की राजनीति और विचारधारा में गहरा अंतर्विरोध है। यह अंतर्विरोध ही राहुल और कांग्रेस के लिए जटिल उलझन और गले की फांस बन गया गया है। मारिया की राजनीति अपनी जगह उनके लिए मुफ़ीद है लेकिन राहुल गांधी की सियासत अलग है।

मारिया को नोबेल की घोषणा करते हुए नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने उन्हें 'लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही के खिलाफ अथक प्रयास' के लिए सराहा। हालांकि, माचाडो की धुर दक्षिणपंथी विचारधारा—जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प का समर्थन, इजराइल की नीतियों की पक्षधरता और आर्थिक निजीकरण की वकालत शामिल है— ने कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए पसोपेश वाली स्थिति पैदा कर दी है।

मारिया कोरिना माचाडो का राजनीतिक उदय वेनेज़ुएला की समाजवादी सरकारों के खिलाफ प्रतिरोध पर आधारित है। 1967 में जन्मी माचाडो, एक पूर्व सांसद और इंजीनियर, २०१२ से विपक्षी गठबंधन की प्रमुख रही हैं। उन्होंने ह्यूगो चावेज़ और निकोलास मादुरो की सरकारों पर चुनावी धांधली, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगाए। ऐसा ही राहुल गांधी भारत में भाजपा सरकार के ख़िलाफ़ करते हैं। २०२४ के राष्ट्रपति चुनावों में, मादुरो सरकार ने मारिया को अयोग्य घोषित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने एडमुंडो गोंजालेज़ को समर्थन देकर विपक्ष को एकजुट किया। इन प्रयासों ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाई, जिसमें अमेरिकी प्रतिबंधों और विदेशी सहायता की मांग शामिल थी।

मारिया की विचारधारा की अपनी राजनीति है। उन्होंने अपना पुरस्कार ट्रम्प को समर्पित करते हुए उन्हें 'हमारे संघर्ष का निर्णायक समर्थक' बताया। मारिया ने अपने देश मे अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप की भी वकालत की, जिससे वेनेज़ुएला में आर्थिक संकट बढ़ा। इजराइल के प्रति उनका रुख साफ है। उन्होंने इजराइल को 'स्वतंत्रता का सच्चा सहयोगी' कहा और गाजा संघर्ष में इजराइली कार्रवाइयों का समर्थन किया। इसके अलावा, माचाडो राज्य तेल कंपनी पीडीवीएसए के निजीकरण की भी पक्षधर हैं, जो समाजवादी विचारधारा के विपरीत है।

इस बीच मारिया को नोबेल की घोषणा होते ही भारत में कांग्रेस ने मारिया के पुरस्कार को अपने राजनीतिक नैरेटिव से जोड़ने का प्रयास किया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि "मारिया ने वेनेज़ुएला में लोकतंत्र के लिए जो संघर्ष किया, वही राहुल गांधी भारत में कर रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सोशल मीडिया पर माचाडो की तुलना राहुल गांधी से की, उन्हें 'संविधान बचाने का योद्धा' बताते हुए उनके लिए भी नोबेल पुरस्कार की मांग कर डाली। यह तुलना कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, जहां राहुल गांधी को चुनावी धांधली, संस्थागत क्षरण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर मुखर दिखाया जाता है। विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें तो यह नैरेटिव बहुत सतही है और राहुल तथा मारिया के बीच वैचारिक विरोधाभासों को अनदेखा करता है।

कांग्रेस की ऐतिहासिक विचारधारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और साम्राज्यवाद-विरोध पर टिकी है। पार्टी ने फिलिस्तीन मुद्दे पर हमेशा समर्थन दिया, जो उसके मुस्लिम मतदाता आधार और वामपंथी सहयोगियों से जुड़ा है। मारिया का इजराइल-समर्थक रुख कांग्रेस की नीतियों से सीधा टकराव पैदा करता है। कांग्रेस ने गाजा हमलों की निंदा की है, जबकि मारिया ने इजराइल को 'स्वतंत्रता का सहयोगी' बताया।

इसी प्रकार, माचाडो का ट्रम्प समर्थन कांग्रेस के लिए असहज है, जिसने भाजपा पर 'ट्रम्प-मोदी गठजोड़' के आरोप लगाए हैं। माचाडो की निजीकरण नीति भी कांग्रेस की समाजवादी नीति के विपरीत है। विश्लेषणात्मक रूप से, ये अंतर्विरोध कांग्रेस की वैचारिकता को चुनौती देते हैं। यदि कांग्रेस मारिया का समर्थन जारी रखती है, तो यह उसके वोट बैंक और सहयोगी दलों में दरार डाल सकती है, विशेष रूप से मुस्लिम और वामपंथी समूहों में, जहां माचाडो को 'इजराइल-समर्थक' माना जाता है।यदि पार्टी माचाडो का समर्थन करती है, तो वह वैचारिक समझौता करेगी, जिससे वोट बैंक दरक सकता है—उदाहरण के लिए, २०२४ चुनावों में मुस्लिम वोटों का करीब 70 प्रतिशत कांग्रेस को मिला था। यदि मौन साधती है या आलोचना करती है, तो भाजपा इसे 'लोकतंत्र-विरोधी' बताकर प्रचार करेगी। राहुल गांधी की व्यक्तिगत स्थिति और भी जटिल है; वे न तो पूर्ण समर्थन कर पा रहे हैं और न विरोध। यह गहन दुविधा,जटिल उलझन कांग्रेस की रणनीतिक कमजोरी को उजागर करती है। राजनीतिक विश्लेषण की दृष्टि से उनके मारिया कोरिना माचाडो का नोबेल पुरस्कार लोकतंत्र संघर्ष को मान्यता तो देता है, लेकिन यह वैचारिक जटिलताओं को भी सामने लाता है। कांग्रेस के लिए यह एक अवसर था जो दुविधा में बदल गया और गले की फांस बन गया जिससे निपटना बहुत मुश्किल है।

अपोलो डॉक्टर की चेतावनी:दो आम दवाइयाँ जो शरीर में विटामिन B12 के अवशोषण को प्रभावित करती हैं

डायबिटीज़ और एसिडिटी की आम दवाइयाँ आपकी ऊर्जा और एकाग्रता को प्रभावित कर सकती हैं।

सारांश: हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल्स के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक कुछ सामान्य दवाओं — जैसे मेटफॉर्मिन (Metformin) जो डायबिटीज़ के लिए ली जाती है, और प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स (PPIs) जो एसिडिटी के लिए ली जाती हैं — का उपयोग शरीर में विटामिन B12 के अवशोषण को कम कर सकता है।

इसकी कमी से थकान, झुनझुनी, हाथ-पैरों में सुन्नपन, या याददाश्त में कमी जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।

वे सलाह देते हैं कि जो लोग इन दवाओं का लंबे समय से सेवन कर रहे हैं, वे नियमित रूप से अपने विटामिन B12 के स्तर की जांच करवाएँ, क्योंकि शुरुआती चरण में इसकी कमी का उपचार बहुत सरल है।

मेटफॉर्मिन और B12 अवशोषण पर उसका प्रभाव

डॉ. कुमार ने बताया कि मेटफॉर्मिन, जो डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए सबसे ज़्यादा दी जाने वाली दवा है (और PCOS या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में भी दी जाती है), शरीर में विटामिन B12 के अवशोषण को कम कर सकती है।

यह दवा छोटी आंत (small intestine) में B12 के अवशोषण की प्रक्रिया को बाधित करती है।

यदि यह दवा लंबे समय तक ली जाए, तो शरीर में धीरे-धीरे विटामिन B12 की कमी हो सकती है।

संभावित लक्षण:

लगातार थकान या कमजोरी

हाथ-पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन

ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई

मूड में बदलाव या भूलने की आदत

सलाह:

मेटफॉर्मिन लेने वाले लोगों को हर 1–2 साल में विटामिन B12 की जांच करवानी चाहिए।

PPIs और पेट के एसिड की भूमिका

दूसरी श्रेणी की दवाएँ जिनका उल्लेख डॉ. कुमार ने किया, वे हैं प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स (PPIs) — जो पेट की एसिडिटी या अल्सर के लिए दी जाती हैं।

इनमें शामिल हैं:

ओमेप्राज़ोल (Omeprazole), पैंटोप्राज़ोल (Pantoprazole), रैबेप्राज़ोल (Rabeprazole), एसोमेप्राज़ोल (Esomeprazole) आदि।

डॉ. कुमार के अनुसार, ये दवाएँ पेट में एसिड के स्तर को घटाती हैं, जिससे शरीर भोजन से विटामिन B12 को अलग और अवशोषित नहीं कर पाता।

लंबे समय तक PPIs का सेवन करने वाले लोगों में भी B12 की कमी का खतरा बढ़ जाता है।

महत्वपूर्ण सुझाव

जो लोग मेटफॉर्मिन या PPIs ले रहे हैं, उन्हें अपनी दवाएँ बिना डॉक्टर से सलाह के बंद नहीं करनी चाहिए।

इसके बजाय, वे नियमित रूप से विटामिन B12 की जांच करवाएँ।

यदि कमी पाई जाए, तो सप्लीमेंट्स या आहार में बदलाव से इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

लंबे समय तक डायबिटीज़ या एसिडिटी की दवाएँ लेने वाले मरीजों को अपने विटामिन B12 स्तर पर ध्यान देना चाहिए।

समय पर जांच और सही उपचार से थकान, सुन्नपन, और मानसिक कमजोरी जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है।

रंगोली, दीए और मिठास-पर्यावरण संग मनाएं दिवाली खास !

कार्तिक अमावस्या को दीपावली है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है।खुशी, उमंग, उल्लास, आपसी मेलजोल का त्योहार है।पाठक जानते हैं कि यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई तथा अज्ञान पर ज्ञान की जीत का संदेश देता है। वास्तव में दीपावली का पर्व हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और आंतरिक शांति लाने के लिए अपने भीतर के द्वेष, ईर्ष्या और नकारात्मकता को दूर करने का भी प्रतीक है।सरल शब्दों में कहें तो दीपावली का पर्व हमारी आंतरिक चेतना को भी रौशन करने की प्रेरणा देता है।'दीपावली' शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है — 'दीप' अर्थात दीया (प्रकाश) और 'आवली' अर्थात पंक्ति (श्रृंखला)।इस प्रकार दीपावली का शाब्दिक अर्थ है — 'दीपों की पंक्ति।' दीपावली का असली अर्थ प्रकाश और खुशियों का त्योहार है, न कि धन और संसाधनों की बर्बादी का अवसर। हमारे देश में हर वर्ष अरबों रुपए पटाखों पर खर्च किए जाते हैं, जिससे न केवल धन का अपव्यय होता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी हानि पहुंचती है। पाठक जानते होंगे कि तमिलनाडु में शिवकाशी, जिसे लिटिल जापान के नाम से भी जाना जाता है, पटाखों/आतिशबाजी का हब कहलाता है।एक उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश के 90% पटाखे तमिलनाडु के शिवकाशी में बनते हैं। एक प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक में प्रकाशित एक खबर के अनुसार यहां करीब 1108 फैक्ट्रियां हैं, जो 8 लाख रोजगार देती हैं, तथा इनमें 60% महिलाएं हैं। यह ठीक है कि पटाखों के कारण देश में बहुत से लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि हर वर्ष पटाखों के कारण आगजनी से जान-माल को भी बहुत नुक्सान पहुंचता है, पशु-पक्षी, मानव से लेकर हमारा पूरा पर्यावरण पटाखों से निकलने वाले धुएं, तेज़ आवाज़ से प्रभावित होता है। गौरतलब है कि इस बार तमिलनाडु के शिवकाशी और आसपास के इलाकों के पटाखा निर्माताओं ने लगभग 7,000 करोड़ रु. की बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल से करीब 17% ज्यादा है। बहरहाल, पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के उपयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जिन पटाखों में बैरियम या अन्य हानिकारक रसायन होते हैं, उनका निर्माण, बिक्री और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। गौरतलब है कि बैरियर या अन्य हानिकारक रसायनों से वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और भारत में बने पटाखों में यह बहुत इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं कोर्ट द्वारा केवल ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति दी गई है। वास्तव में ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों की तुलना में पर्यावरण के लिए कहीं अधिक सुरक्षित और लाभदायक हैं। इन पटाखों में बैरियम, नाइट्रेट और हानिकारक धातुएं नहीं होतीं, जिससे वायु प्रदूषण लगभग 30 से 40 प्रतिशत तक कम होता है।इनसे निकलने वाला धुआं और गैसें सीमित होती हैं, जिससे हवा में हानिकारक कणों की मात्रा घटती है। इनका ध्वनि स्तर भी कम होता है, जिससे बुजुर्गों, बच्चों और पशु-पक्षियों को परेशानी नहीं होती। ऐसे पटाखों से आँखों और साँस की बीमारियों का खतरा भी घट जाता है। इसके अलावा, ग्रीन पटाखे स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं, जिससे देशी उद्योग और रोजगार को भी प्रोत्साहन मिलता है। इनकी पैकेजिंग पर QR कोड होता है, जिससे उपभोक्ता असली ग्रीन पटाखे की पहचान कर सकते हैं। कुल मिलाकर, ग्रीन पटाखे दीपावली की खुशियों को बनाए रखते हुए पर्यावरण की रक्षा करने का संतुलित उपाय हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही हो सकती है और ऑनलाइन बिक्री पर पूर्ण रोक है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि दीपावली जैसे अवसरों पर पटाखे केवल निर्धारित समय, आमतौर पर रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़े जाएँ। सड़कों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों पर पटाखे फोड़ना निषिद्ध है। बच्चों को बिना निगरानी के पटाखे चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने सरकारों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि केवल मानक परीक्षण वाले ग्रीन पटाखे ही बाजार में उपलब्ध हों। साथ ही, किसी भी व्यक्ति या कंपनी का लाइसेंस बिना कोर्ट आदेश के रद्द नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रदूषण नियंत्रण केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह देशव्यापी नीति होनी चाहिए। माननीय कोर्ट ने नागरिकों से दीवाली को प्रदूषण मुक्त और सुरक्षित तरीके से मनाने की अपील की है, ताकि पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों की रक्षा हो सके। हाल फिलहाल कहना चाहूंगा कि यह दीपावली न केवल रोशनी और उत्सव का प्रतीक बने, बल्कि देशभक्ति, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की भावना का भी सुंदर उदाहरण साबित होना चाहिए। अंत में यही कहूंगा कि पटाखों से उत्पन्न धुआं और विषैली गैसें वातावरण को प्रदूषित करती हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता घटती है और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। कई बार आगजनी और दुर्घटनाओं से जान-माल का भी भारी नुकसान होता है। सच्ची दीपावली वह है जिसमें दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैले। यदि हम पटाखों की जगह गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और मिठाइयां बांटें, तो यही सच्ची खुशी होगी। इससे हमारे समाज में प्रेम, सहयोग और मानवता का दीप जलेगा। दीपावली का सच्चा आनंद तभी है जब हर चेहरे पर मुस्कान हो और हर घर में उम्मीद का उजाला फैले।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर,

ट्रंप नेतन्याहू की जीत लेकिन शांति की आस नहीं

राजेश कुमार पासी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव के पहले चरण पर अमल शुरू हो गया है । हमास ने इजराइल के 20 बंधकों को रिहा कर दिया है और 28 बंधकों के शवों की वापसी होने वाली है । इजराइल ने भी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया है । इससे डोनाल्ड ट्रंप की वाहवाही हो रही है । वैसे उनका शांति प्रस्ताव अपने आप में अनोखा है क्योंकि जिनके बीच यह समझौते की बात कहता है, उसमें से एक पक्ष इसमें शामिल नहीं हैं । बेशक समझौते के पहले चरण पर अमल शुरू हो गया है लेकिन अगले चरण कब पूरे होते हैं या नहीं होते हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा ।

इसके बावजूद इजराइल और हमास के बीच युद्ध रुकवाने का श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को देना होगा । उनकी कोशिशों से दोनों पक्ष युद्ध रोकने को सहमत हो गए हैं । इस शांति प्रस्ताव का आंशिक रूप से लागू होना भी ट्रंप और नेतन्याहू की बड़ी जीत माना जाएगा । युद्ध रुकने से हमास ने भी राहत की सांस ली है । अरब देश भी इस समझौते के बाद खुश दिखाई दे रहे हैं. सिर्फ पाकिस्तान में इस मुद्दे पर आग लगी हुई है । वैसे तो हमास-इजराइल युद्ध से पूरी दुनिया परेशान है लेकिन दोनों पक्षों के अलावा अमेरिका और अरब देशों के लिए ये युद्ध बड़ी सिरदर्दी बन चुका है ।

ये सोचना गलत है कि ट्रंप ने सिर्फ वाहवाही हासिल करने के लिए ये समझौता करवाया है बल्कि उन्होंने इस समझौते से सबकी समस्याओं को कुछ समय के लिए टाल दिया है । उनका बड़बोलापन और आत्ममुग्धता से भरे बयान उन्हें अविश्वसनीय बनाते हैं लेकिन इस समझौते के लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए । उन्होंने बड़ी चालाकी से इजराइल को बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल लिया है । उन्होंने नेतन्याहू से माफी मंगवा कर इजराइल के प्रति बढ़ती नफरत को थाम लिया है । जब से इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला करके हमास के अधिकारियों की हत्या की है, तब से सभी अरब देश डरे हुए हैं कि कहीं वो इजराइल के अगले हमले का शिकार न बन जाएं । यही वो डर था, जिसके कारण सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता कर लिया । इस समझौते के बाद अरब देशों ने राहत की सांस ली है।

डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बंधकों की रिहाई से ही इस समझौते की सफलता का ढिंढोरा पीट रहे हैं । उनका कहना है कि उन्होंने हज़ारों सालों से दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। ऐसा ही बयान उन्होंने भारत-पाकिस्तान के युद्ध विराम के लिये दिया था। देखा जाए तो हमास और इजराइल के बीच भी युद्ध विराम ही हुआ है। स्थायी शांति की उम्मीद करना पूरी तरह से व्यर्थ है । युद्ध-विराम कभी भी शांति का प्रतीक नहीं होता । युद्ध-विराम का अर्थ ही होता है कि दोनों पक्ष लड़ना छोड़कर अब अगले युद्ध की तैयारी करेंगे । हमास और इजराइल दोबारा नहीं लड़ेंगे, ये सोचना गलत है । इजराइली सरकार पर जनता का भारी दबाव पड़ रहा था कि वो तत्काल बंधकों की रिहाई करवाये । दूसरी तरफ हमास पर भी गाजा की जनता का दबाव था कि वो बंधकों को छोड़ दे ताकि इजराइल गाजा की नाकाबंदी खत्म कर दे । वहाँ भुखमरी के हालात पैदा हो गए थे। देखा जाए तो दोनों पक्ष लड़ते-लड़ते थक गए थे, इसलिए दोनों को थोड़े आराम की जरूरत थी ।

इस समझौते को नेतन्याहू की बड़ी सफलता माना जाएगा क्योंकि इतने बड़े नरसंहार के बाद भी वो अपने बंधकों को छुड़ाने में कामयाब रहे हैं । वैसे भी यह समझौता इजराइल के पक्ष में झुका हुआ दिखाई देता है, इसलिए मुस्लिम देशों में इसका विरोध बढ़ता दिखाई दे रहा है । दूसरे चरण में जब इजराइली सेना पीछे हटेगी तो देखना होगा कि वो कहां तक पीछे जाती है । हमास ने हथियार छोड़ने के लिए शर्त रख दी है कि वो स्वतंत्र फिलिस्तीन का रास्ता साफ होने पर ही हथियार छोड़ेगा । इजराइल इसके लिए तैयार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है । हमास ईरान का प्रॉक्सी है, इसलिए ईरान की भूमिका भी देखनी पड़ेगी कि वो क्या करता है । ईरान ने इजराइल को मिटाने की कसम खा रखी है, इसलिए इजराइल का ईरान पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है । ईरान सिर्फ हमास को ही इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहा है बल्कि वो हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों से भी इजराइल पर हमले करवा रहा है । इस युद्ध को इसलिए याद रखा जाना चाहिए क्योंकि इजराइल ने लेबनान से हिजबुल्लाह का लगभग सफाया कर दिया है । इसके अलावा इस युद्ध के कारण सीरिया में भी सत्ता परिवर्तन हो गया है।

इजराइली हमलों के कारण गाजा में लगातार लोग मारे जा रहे थे । मरने वालों की संख्या 65000 से ऊपर जा चुकी है और इससे कई गुना ज्यादा लोग घायल हैं । इसके कारण इजराइल पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वो तत्काल युद्ध-विराम कर दे । पूरी दुनिया में बड़ी-बड़ी रैलियां निकाल कर इजराइल का विरोध किया जा रहा था । इजराइल के विरोध में यूरोप के कई देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता प्रदान कर दी थी । सवाल यह है कि 7 अक्टूबर, 2023 से पहले गाजा और इजराइल के बीच युद्ध-विराम ही चल रहा था. इस दिन किसने इजराइल पर बर्बर हमला करके इस युद्ध-विराम को भंग किया था । जब इजराइल पर हमास ने यह भयंकर हमला किया था तो एक समुदाय ने पूरी दुनिया में इसका जश्न मनाया था । देखा जाए तो गाजावासियों की हत्याओं के लिए इजराइल नहीं बल्कि हमास जिम्मेदार है । अगर वो इजराइल पर इतना बर्बर हमला नहीं करता तो इजराइल कैसे गाजा में इतना बड़ा नरसंहार कर सकता था । गाजा के लोगों की हत्याओं के लिए किसी भी मुस्लिम देश ने हमास को जिम्मेदार नहीं ठहराया है । पूरे मुस्लिम जगत की ये मानसिकता है कि इजराइल धरती पर होना ही नहीं चाहिए और यहूदियों को धरती से खत्म करना है। हमास वही कर रहा है जो मुस्लिम जगत चाहता है, इसलिए मुस्लिम देशों में उसके समर्थन में बड़े-बड़े प्रदर्शन होते हैं।

इजराइल का सपना भी एक ग्रेटर इजराइल बनाने का है जिसके लिए युद्ध जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप इस समस्या को दो देशों की लड़ाई समझते हैं जबकि सच्चाई यह है कि ये दो सभ्यताओं की जंग है । ये जंग सिर्फ यहूदियों और मुस्लिमों के बीच नहीं है बल्कि शिया और सुन्नी की भी जंग है । अरब देश फिलीस्तीनियों से नफरत करते हैं इसलिए वहां हमास का ज्यादा समर्थन नहीं है। जो समर्थन है वो सिर्फ यहूदियों से नफरत के कारण है। ईरान इस्लामिक देशों का रहनुमा बनने के चक्कर में आतंकियों के संगठन खड़े कर रहा है जो इजराइल से लड़ते रहते हैं । हमास से जब पूछा गया कि अगर तुम्हें पता होता कि इजराइल तुम्हारे हमले का ऐसा जवाब देगा तो क्या तब भी हमला करते। हमास का जवाब था हम बार-बार ऐसे हमले करेंगे, फिर चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ये संभव ही नहीं है कि हमास हथियार छोड़कर गाजा से बाहर चला जाये, जबकि ये शांति प्रस्ताव की जरूरी शर्त है। सवाल यह है कि हथियार छोड़कर हमास क्या करेगा और वो कहां जाएगा । क्या कोई देश उसे शरण देगा । सवाल यह भी है कि जो आज हमास के लिए लड़ रहे हैं, क्या सिर्फ उन्हें ही हमास माना जाए । अगर हमास के लड़ाके गाजा छोड़ देते हैं तो जो लोग पीछे बचेंगे, वो एक नया हमास खड़ा कर सकते हैं । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो उसे गाजा की जनता का पूरा समर्थन हासिल था ।

हमास की ताकत को इससे समझा जा सकता है कि दो वर्ष की लड़ाई के बाद भी इजराइल उससे बंधकों को छुड़ा नहीं पाया । इजराइल ने पूरे गाजा को समतल कर दिया लेकिन समझौते के बाद हमास पूरी ठसक से बंधकों को दुनिया के सामने लेकर आ गया । हमास भारी नुकसान के बाद भी नई भर्तियां करने में सफल रहा है । सवाल यह है कि जो संगठन अभी भी नए लोगों को शामिल कर रहा है, वो कैसे हथियार छोड़कर गाजा से चला जाएगा । उम्मीद की किरण सिर्फ यह है कि इजराइल ने सभी मुस्लिम देशों को संदेश दे दिया है कि फिलिस्तीन की जंग की आंच उन तक भी पहुंचेगी । कोई देश ये न सोचे कि इजराइल आतंकियो से लड़ता रहेगा और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी । कतर पर हमला करके उसने बता दिया है कि हमास जैसे संगठनों को शरण देने का नतीजा सबको भुगतना पड़ेगा।

वास्तव में सच यही है कि जब इजराइल-हमास जंग की आंच अरब देशों को महसूस हुई, तब उन्होंने हमास पर इतना दबाव बनाया कि उसे समझौते के लिए सहमति देनी पड़ी। पाकिस्तान में जनता की प्रतिक्रिया बता रही है कि इस्लामिक देशों के शासकों और उनकी जनता की सोच में बड़ा अंतर है। बेशक मुस्लिम देश इस समझौते से खुश हैं लेकिन इन देशों की जनता के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसकी वजह यह है कि फिलिस्तीन के बारे में गलत प्रचार किया गया है जिसका खामियाजा अब मुस्लिम देश भुगत रहे हैं । इजराइल के लिए जरूरी है कि वो फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दे और उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक अपना देश चलाने दे । यह तब हो सकता है, जब इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना छोड़ दे । अरब देशों और मुस्लिम समाज के लिए जरूरी है कि वो यहूदियों से नफरत का त्याग कर दे और फिलिस्तीन में शांति और स्थिरता स्थापित करने में मदद करें ।

गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं: अल्फ्रेड नोबेल ने गणितीय क्षेत्र को सम्मान से क्यों बाहर रखा

विजय गर्ग

नोबेल पुरस्कार दुनिया भर में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जिसे स्वीडन के आविष्कारक, इंजीनियर और उद्योगपति ने स्थापित किया था। अपनी इच्छानुसार, नोबेल ने अपना भाग्य उन पुरस्कारों को बनाने के लिए समर्पित किया जिन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति जैसे क्षेत्रों में मानवता में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

यह पुरस्कार हर वर्ष उन खोजों और उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए प्रदान किए जाते हैं जिनका विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है, समाज के लिए दूरदर्शी लाभ वाले काम को मान्यता देने तथा नवाचार और प्रगति को प्रोत्साहित करने के नोबेल की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए।

गणित के लिए कोई नोबेल पुरस्कार नहीं है दिलचस्प बात यह है कि नोबेल द्वारा सम्मानित विभिन्न विषयों के बावजूद, उन्होंने पुरस्कारों में गणित को कभी शामिल नहीं किया। इस उपेक्षा ने वर्षों में बहुत सी जिज्ञासा और अटकलें लगाई हैं, विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गणित की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए।

ऐसा क्यों

गणित के लिए विशेष रूप से कोई नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं है, यह समझने के लिए इतिहास, पुरस्कार के मूल इरादों और वैकल्पिक पुरस्कारों का विकास करना आवश्यक है जो गणितीय प्रतिभा को पहचानते हैं।

अल्फ्रेड नोबेल की अपनी पुरस्कार श्रेणियों में गणित को शामिल न करने का निर्णय जानबूझकर लिया गया था, हालांकि सटीक कारण ऐतिहासिक संदर्भ और अटकलों का मिश्रण बने हुए हैं। सबसे मजबूत स्पष्टीकरणों में से एक यह है कि नोबेल उन विषयों को पुरस्कृत करना चाहता था जिनके पास मानवता के लिए तत्काल और व्यावहारिक लाभ थे, जैसे चिकित्सा और भौतिकी, जबकि वाटरलू विश्वविद्यालय के अनुसार गणित को उस समय अधिक अमूर्त और सैद्धांतिक माना जाता था।

लोकप्रिय मिथकों में व्यक्तिगत कारणों का सुझाव दिया गया है, जैसे कि नोबेल और , लेकिन ऐतिहासिक अनुसंधान के अनुसार, इन कहानियों का समर्थन करने वाले कोई ठोस सबूत नहीं हैं। नोबेल ने कभी शादी नहीं की, हालांकि उनके पास एक प्रेम त्रिभुज या पेशेवर ईर्ष्या के बारे में कहानियां उजागर कर दी गई हैं।

इसके अतिरिक्त, कुछ इतिहासकारों का सुझाव है कि चूंकि स्वीडिश गणितज्ञ गोस्टा मिटाग-लेफलर द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित गणित पुरस्कार पहले से ही मौजूद थे, इसलिए नोबेल को उस क्षेत्र में एक और प्रतिस्पर्धी पुरस्कार बनाना अनावश्यक लगता था। गणितज्ञों को नोबेल पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है विशेष नोबेल पुरस्कार की अनुपस्थिति के बावजूद, गणितज्ञों को नोबल से संबंधित श्रेणियों में मान्यता दी गई है। उदाहरण के लिए, जॉन नैश को खेल सिद्धांत में उनके काम के लिए आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह दर्शाता है कि गणित की अंतर्दृष्टि तब मूल्यवान होती है जब इसमें व्यावहारिक, वास्तविक दुनिया का उपयोग होता है।

गणित समुदाय के पास अपना पुरस्कार है इस अंतर के जवाब में गणित समुदाय ने अपना विशिष्ट सम्मान विकसित किया। सबसे प्रसिद्ध फील्ड्स मेडल है, जिसे 1936 में स्थापित किया गया था और इसे अक्सर ₹नॉबेल गणित पुरस्कार₹ कहा जाता है इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन और विकिपीडिया के अनुसार, यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम आयु के युवा गणितज्ञों को प्रत्येक चार साल में दिया जाता है जिन्होंने उपलब्धि और भविष्य की प्रतिज्ञा दोनों को मान्यता देने का लक्ष्य रखा है। नोबेल पुरस्कार के विपरीत, इसमें आयु सीमा है और प्रत्येक चक्र में कई प्राप्तकर्ता प्रदान किए जाते हैं।

एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में भी एक सम्मानित सम्मान है एबेल पुरस्कार, जो 2002 में नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर द्वारा स्थापित किया गया था, को नोबल से अधिक सीधे तुलनात्मक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में डिजाइन किया गया था। यह आयु सीमा के बिना जीवन भर की उपलब्धि का सम्मान करता है और इसमें नोबेल पुरस्कार जैसा ही मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है।

सेवानिवृत्त निदेशक, पूर्व पीईएस शैक्षिक स्तंभकार प्रतिष्ठित शिक्षाविद् सड़क कुर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

संपादकीय

चिंतन-मनन

सेवा, सुरक्षा, सहयोग... या आत्मघात ? हरियाणा पुलिस का संकट काल

डॉ. सत्यवान सौरभ

हरियाणा इन दिनों एक ऐसे दौर से गुज़र रहा है, जहाँ पुलिस महकमे की साख, मनोबल और संवेदनशीलता तीनों एक साथ संकट में दिखाई दे रहे हैं। पहले आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की आत्महत्या ने पूरे राज्य को झकझोर दिया और अब एएसआई संदीप लाठर की खुदकुशी ने इस त्रासदी को और गहरा कर दिया है। दोनों घटनाएँ न केवल पुलिस विभाग के भीतर की बेचैनी को उजागर करती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि कानून के रखवाले ही जब अपने जीवन से हार मानने लगें, तो समाज की बुनियाद कितनी डगमगा जाती है।

एएसआई संदीप लाठर ने आत्महत्या से पहले जो वीडियो जारी किया, उसमें उसने अपने अफसरों और सिस्टम के रवैये पर सवाल उठाए। इससे पहले आईपीएस पूरन कुमार की मौत के बाद भी कई सवाल अनुत्तरित रह गए थे। अब इन दो आत्महत्याओं ने मिलकर एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसने हरियाणा पुलिस की छवि पर गहरा धब्बा छोड़ दिया है। आम जनता यह सोचने पर मजबूर है कि जो विभाग सुरक्षा और न्याय का प्रतीक माना जाता है, उसके भीतर इतना असंतोष, अविश्वास और भय कैसे पनप गया।

हरियाणा पुलिस देश की सबसे अनुशासित और जुझारू पुलिस बलों में गिनी जाती रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हालात ऐसे बने हैं कि इस बल के भीतर मनोबल टूटने लगा है। कहीं राजनीतिक दबाव है, कहीं जातिगत खींचतान, तो कहीं अफसरों के बीच अंतर्विरोध। आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में कई लोगों ने सवाल उठाया था कि क्या उन्हें किसी साजिश का शिकार बनाया गया ? और अब संदीप लाठर की मौत के बाद यह सवाल और भी गंभीर रूप ले चुका है।

यह पूरा घटनाक्रम किसी वेब सीरीज़ की तरह उलझा हुआ प्रतीत होता है, जिसमें हर पात्र का अपना दर्द है और हर मोड़ पर नया रहस्य खुलता है। परंतु यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि एक वास्तविक त्रासदी है — उन परिवारों की जिनके सदस्य कानून के रक्षक थे और अब उनकी आत्माएं न्याय की पुकार लगा रही हैं।

कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिन लोगों के कंधों पर होती है, जब वही खुद अवसाद, निराशा और असहायता के शिकार हों, तो यह किसी भी राज्य के लिए चेतावनी की घंटी है। हरियाणा में हाल के वर्षों में कई बार पुलिस कर्मियों ने खुले मंच से यह स्वीकार किया है कि उनकी कार्यस्थितियाँ बेहद तनावपूर्ण हैं। लंबी ड्यूटी, छुट्टियों की कमी, ऊपरी आदेशों का दबाव और समाज की नकारात्मक धारणा — ये सभी कारण एक पुलिसकर्मी के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं।

चिंता की बात यह है कि आत्महत्या जैसे चरम कदम का सिलसिला अब पुलिस में आम होता जा रहा है। पहले चंडीगढ़, अब रोहतक — हर बार एक नई जगह से वही खबर आती है कि एक और वर्दीधारी ने अपनी जान दे दी। यह सवाल उठाना लाज़मी है कि आखिर पुलिस विभाग में ऐसा माहौल क्यों बन रहा है जहाँ मनोबल इतना कमजोर पड़ रहा है कि जीवन ही बोझ लगने लगे।

कुछ लोगों का तर्क है कि इन घटनाओं के पीछे जातिवाद और राजनीति की भूमिका है। हरियाणा जैसे राज्य में, जहाँ जातीय समीकरण राजनीति से लेकर प्रशासन तक गहराई से जुड़े हुए हैं, यह संभावना पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकती। किसी अधिकारी के साथ भेदभाव या दबाव, चाहे वह जातिगत हो या राजनीतिक, मानसिक रूप से तोड़ सकता है। यह वही आग है जो धीरे-धीरे पूरे सिस्टम को निगल रही है। हरित प्रदेश हरियाणा का सामाजिक ताना-बाना तभी सुरक्षित रहेगा, जब प्रशासन जातिवाद से ऊपर उठकर ईमानदार और निष्पक्ष कार्रवाई करेगा।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शहीद कौन है — आईपीएस पूरन कुमार या एएसआई संदीप लाठर ? दोनों ही अपने-अपने स्तर पर सिस्टम से लड़ते हुए हार गए। अगर कोई पुलिसकर्मी अपने अफसरों से न्याय की उम्मीद खो दे, तो वह किससे उम्मीद करेगा ? जब "सेवा, सुरक्षा और सहयोग" का आदर्श वाक्य ही खोखला लगने लगे, तो यह न केवल संस्थागत विफलता है बल्कि मानवीय करुणा का भी अंत है।

जॉब पाने में मददगार छोटे-छोटे कोर्स (माइक्रो-क्रेडेंशियल्स कोर्स)

विजय गर्ग

माइक्रो-क्रेडेंशियल्स वे छोटे-छोटे सर्टिफिकेशन या स्किल बेस्ड कोर्स होते हैं, जिन्हें पारंपरिक डिग्री की तरह सालों तक करने की जरूरत नहीं होती, ये किसी स्पेसिफिक स्किल टूल या प्रैक्टिकल नॉलेज पर केंद्रित होते हैं। जैसे- डाटा एनालिटिक्स विद एक्सेल, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ग्रीन फाइनेंस और डिजिटल मार्केटिंग आदि। इन्हें कोई भी कुछ हफ्तों या महीनों में ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से पूरा कर सकता है। आमतौर पर ये मॉड्यूलर होते हैं यानी इन कुशलताओं या स्किल्स को एक-एक करके जोड़ते जाओ और चाहो तो बाद में डिग्री या एडवांस कोर्स में क्रेडिट के तौर पर भी इस्तेमाल कर लो।

बहरहाल आज माइक्रो-क्रेडेंशियल्स का प्रभाव कैरियर की दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। केवल डिग्री सब कुछ नहीं रह गई। कंपनियां और नियोक्ता आजकल यह देखते हैं कि वह जिसे भर्ती कर रहे हैं या जॉब दे रहे हैं, वह अपने काम में कितना दक्ष है, उसे नई तकनीक या ज्ञान की समझ है या नहीं। अगर नहीं है, तो भी वह कितनी जल्दी यह समझ हासिल कर सकता है। माइक्रो-क्रेडेंशियल्स की अवधारणा बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रही है।

इसलिए बढ़ रही है मांग

कैरियर बाजार बड़ी तेजी से बदल रहा है। पहले जहां कंपनियां डिग्रियों को पहली प्राथमिकता देती थीं, वहीं अब ये सीधे सीधे स्किल्स को महत्व दे रही हैं। रिज़्यूमे में किसी माइक्रो-क्रेडेंशियल्स का उल्लेख उम्मीदवार को यह वजन देता है कि वह विशेष कौशल से युक्त है और उद्योग की मौजूदा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, ब्लॉकचेन, साइबरसिक्योरिटी और ग्रीनएनर्जी जैसे क्षेत्रों में हर महीने कुछ न कुछ नये तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। नये नये टूल्स और सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में चार साल की डिग्री पूरी होने तक पूरा सिलेबस ही अप्रासंगिक हो सकता है। ऐसे में माइक्रो-क्रेडेंशियल्स उपयोगी साबित हो रहे हैं।

मिड-कैरियर अपस्किलिंग

यह सिर्फ नये नौकरी ढूंढ़ रहे उम्मीदवारों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि ऐसे पेशेवर जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, मगर इनके कामकाज का तरीका पुराना हो चुका है, तो उन्हें खुद को नई तकनीक और कार्यसंस्कृति में एडजेस्ट करने के लिए समय पर कर लिए जाने वाले माइक्रो-क्रेडेंशियल्स या सर्टिफिकेशन मजबूत सहारा देते हैं। माइक्रो-क्रेडेंशियल्स की बदौलत अधेड़ लोग भी अपने मिड-कैरियर में यह अपस्किलिंग कर सकते हैं। इससे उन्हें बेहतर पोजीशन या नई इंडस्ट्री में जगह बनाना आसान होता है। नई कार्यसंस्कृति में पढ़ने और सीखने की लाइफ लांग कल्चर बन चुकी है।

भारत में बढ़ती मांग

भारत में यह ट्रेंड तेजी से अपने पांव पसार रहा है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे कोरसेरा, ईडीएक्स, यूडेमी, लिंक्डइन लर्निंग और भारत सरकार का स्वयं पोर्टल इस ट्रेंड को लोकप्रिय बनाने में बेहद मददगार साबित हो रहा है। ये सभी प्लेटफॉर्म जरूरतमंदों को माइक्रो-क्रेडेंशियल्स उपलब्ध करा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भी 'अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' और 'मॉड्यूलर डिग्री' की अवधारणा को मान्यता दी है। कंपनियां अब भर्ती और प्रमोशन में माइक्रो-क्रेडेंशियल्स को स्किल्ड प्रूफ की तरह मान्यता दे रही है।

मिड-कैरियर प्रोफेशनल को अपनी जॉब में प्रमोशन के लिए इसकी जबर्दस्त जरूरत महसूस हो रही है। फ्रीलांसर और उद्यमियों के लिए यह बहुत कारगर है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य का कैरियर पाथ डिग्री+माइक्रो-क्रेडेंशियल्स के कॉम्बिनेशन से ही बनेगा।

चुनौतियां भी कम नहीं

यह अवधारणा सुनने और समझने में बेहद आकर्षक है, पर कुछ चुनौतियां भी सामने हैं। हर प्लेटफॉर्म पर माइक्रो-क्रेडेंशियल्स एक स्तर के ही नहीं होते, कई जगहों पर गुणवत्ता की मांग उससे कहीं ज्यादा होती है। इसलिए यह नहीं सोचा जा सकता कि सिर्फ माइक्रो-क्रेडेंशियल्स से ही काम चल जायेगा। कई कंपनियां अभी भी डिग्री पर ही जोर दे रही हैं। वहीं कई बार एक डिग्री करने के बजाय अगर हम कई छोटे छोटे कोर्स करते हैं तो उनकी लागत कहीं ज्यादा आ जाती है। दरअसल माइक्रो-क्रेडेंशियल्स एक नये युग की शुरुआत हैं और उन युवाओं तथा पेशेवरों को मदद कर रहे हैं जो तेजी से बदलते कैरियर बाजार में खुद को अपडेट रखना चाहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले पांच सालों में भारतीय कैरियर परिदृश्य का सबसे ताकतवर पहलू माइक्रो-क्रेडेंशियल्स ही होंगे।

जलवायु संकट का भावनात्मक सेहत पर असर

विजय गर्ग

जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय समस्या या आर्थिक चुनौती नहीं है। यह एक मानसिक स्वास्थ्य संकट भी है जो दुनिया के सबसे गरीब लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। मौसम संबंधी आघातों को रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटना महत्वपूर्ण है।

जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता तापमान दुनियाभर के लाखों लोगों के भावनात्मक स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान, आर्द्रता और धूप जैसी मौसम की स्थितियां आपके मूड, ऊर्जा और संज्ञानात्मक कार्यों पर असर डाल सकती हैं। अत्यधिक तापमान अक्सर मूड को खराब कर देता है, जबकि मध्यम, धूप वाली स्थितियां मूड को बेहतर बना सकती हैं। कुछ लोग जिनमें वृद्ध और मनोविकार वाले लोग शामिल हैं, मौसम परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। संभवतः चिड़चिड़ापन, माइग्रेन और अनिद्रा जैसे लक्षणों का अनुभव कर सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाएं मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे तनाव, चिंता, डिप्रेशन और पीटीएसडी (पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर) बढ़ सकता है। सोशल मीडिया डेटा के एक बड़े अध्ययन से पता चला है कि अत्यधिक गर्मी में लोग काफी ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। शोधकर्ताओं ने 157 देशों के 1.2 अरब सोशल मीडिया पोस्ट की समीक्षा की। ये सभी 2019 के दौरान पोस्ट किए गए थे। उन्होंने 65 अलग-अलग भाषाओं में लिखे गए पोस्ट का विश्लेषण करने के लिए उन्नत कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल किया और प्रत्येक पोस्ट को उसके सकारात्मक या नकारात्मक होने के आधार पर स्कोर दिया।

शोधकर्ताओं ने लोगों के मूड स्कोर का मिलान स्थानीय मौसम के आंकड़ों से किया ताकि यह देखा जा सके कि तापमान का लोगों की ऑनलाइन बातों पर क्या असर पड़ा। इसके नतीजे दुनिया भर में स्पष्ट और एक जैसे थे। जब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया, तो कम आय वाले देशों में लोगों के पोस्ट लगभग 25 प्रतिशत ज्यादा नकारात्मक हो गए। अमीर देशों में नकारात्मकता लगभग 8 प्रतिशत बढ़ गई। चीनी विज्ञान अकादमी के विज्ञानी जियांगहाओ वांग ने कहा, सोशल मीडिया डेटा हमें विभिन्न संस्कृतियों और महाद्वीपों में मानवीय भावनाओं की एक अभूतपूर्व झलक प्रदान करता है। यह डेटा हमें जलवायु परिवर्तन के भावनात्मक प्रभावों के पैमाने को मापने में मदद करता है जो पारंपरिक सर्वेक्षणों से संभव नहीं है। यह हमें वास्तविक समय में यह जानकारी देता है कि तापमान दुनिया भर में मानवीय भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है।

शोधकर्ताओं ने विश्व बैंक के आंकड़ों का उपयोग करके देशों को आय स्तर के आधार पर अलग किया, जिसकी विभाजन रेखा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 13,845 डॉलर निर्धारित की गई। इस सीमा से नीचे के देशों में गर्मी के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रियाएं धनी देशों की तुलना में अधिक प्रबल थीं। यह इस बात को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत है कि अमीर देशों में अधिक एयर कंडीशनिंग और बेहतर स्वास्थ्य सेवा है। चरम मौसम से निपटने के लिए उनके पास मजबूत बुनियादी ढांचा है।

इस अध्ययन का नेतृत्व करने वाले एमआईटी के सिकी झेंग ने कहा कि हमारे अध्ययन से पता चलता है कि बढ़ता तापमान न केवल शारीरिक स्वास्थ्य या आर्थिक उत्पादकता के लिए खतरा है बल्कि यह दुनियाभर में लोगों की दैनिक भावनाओं को भी प्रभावित करता है। शोधकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त एआई सिस्टम दर्जनों

भाषाओं में लिखे गए पाठ के भावनात्मक लहजे को समझ सकता है, जिससे विभिन्न संस्कृतियों और देशों में भावनाओं की तुलना करना संभव हो जाता है।

शोधकर्ता वर्तमान परिस्थितियों तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने जलवायु मॉडल का उपयोग करके यह अनुमान लगाया कि 2100 तक अत्यधिक गर्मी मानवीय भावनाओं को कैसे प्रभावित कर सकती है। यह मानते हुए कि लोग समय के साथ उच्च तापमान के साथ कुछ हद तक अनुकूलित हो जाएंगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि सदी के अंत तक गर्मी के कारण भावनात्मक कल्याण 2.3 प्रतिशत तक बिगड़ जाएगा। अमेरिका में टल्सा स्थित सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन लैब के वैज्ञानिक निक ओब्राडोविच ने कहा की हमारे वर्तमान अध्ययन और पिछले अध्ययनों के निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि मौसम वैश्विक स्तर पर भावनाओं को बदलता है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे मौसम और जलवायु बदलते हैं, व्यक्तियों को अपनी भावनात्मक स्थिति पर पड़ने वाले झटकों के प्रति अधिक लचीला बनने में मदद करना समग्र सामाजिक अनुकूलन का एक महत्वपूर्ण घटक होगा।

दरअसल, यह शोध जलवायु परिवर्तन के बारे में सोचने के बिल्कुल नए रास्ते खोलता है। ज्यादातर अध्ययन शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों, आर्थिक क्षति या पर्यावरणीय विनाश पर केंद्रित हैं। लेकिन यह शोध दर्शाता है कि बढ़ता तापमान हमारे मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है, जिससे एक तरह का भावनात्मक प्रदूषण पैदा होता है जो पूरे ग्रह में फैल जाता है। इस अध्ययन की कुछ सीमाएं हैं। सोशल मीडिया उपयोगकर्ता सभी का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग अन्य आयु समूहों की तुलना में इस प्लेटफार्म का कम उपयोग करते हैं। विडंबना यह है कि ये लोग अक्सर अत्यधिक गर्मी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, जिसका अर्थ है कि गर्म मौसम का वास्तविक भावनात्मक प्रभाव अध्ययन में दर्शाए गए प्रभाव से भी अधिक गंभीर हो सकता है।

यह शोध एमआईटी की सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन लैब की ग्लोबल सेंटीमेंट प्रोजेक्ट से आया है। वैज्ञानिकों ने अपना पूरा डेटासेट अन्य शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया है। उम्मीद है कि यह समुदायों और नीति-निर्माताओं को एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार होने में मदद करेगा जो लगातार गर्म होती जा रही है। झेंग ने कहा, हमें उम्मीद है कि यह संसाधन शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और समुदायों को एक गर्म होती दुनिया के लिए बेहतर ढंग से तैयार होने में मदद करेगा।

जैसे-जैसे वैश्विक स्तर पर तापमान बढ़ता जा रहा है, इन भावनात्मक प्रभावों को समझना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अध्ययन बताता है कि जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय समस्या या आर्थिक चुनौती नहीं है। यह एक मानसिक स्वास्थ्य संकट भी है जो दुनिया के सबसे गरीब लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। मौसम संबंधी आघातों को रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटना महत्वपूर्ण है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम

विजय गर्ग

कृषि हमेशा से ही भारत की अर्थव्यवस्था का आधार रहा है, जिसमें लगभग आधी आबादी को रोजगार दिया गया है और देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। हालांकि, इस क्षेत्र को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे श्रम की कमी, बढ़ते इनपुट लागत, कम उत्पादकता और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव। साथ ही कृषि में लिंग असमानता जारी है। महिलाएं भारत की कृषि कार्यबल का लगभग 33 प्रतिशत हिस्सा हैं और 48 प्रतिशत से अधिक स्वयंसेवक किसान हैं, फिर भी प्रौद्योगिकी, निर्णय लेने और प्रशिक्षण के अवसरों तक उनकी पहुंच सीमित है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत (आत्मनिर्भर भारत) दृष्टिकोण के तहत कई परिवर्तनकारी योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से ड्रोन दीदी योजना एक अग्रणी पहल के रूप में सामने आ रही है। यह कार्यक्रम कृषि उत्पादकता और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए आधुनिक ड्रोन प्रौद्योगिकी से लैस ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है। यह योजना न केवल तकनीकी हस्तक्षेप है, बल्कि एक सामाजिक सुधार भी है जो कृषि में महिलाओं की भूमिका को पुनः परिभाषित करता है।

ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य कृषि में लिंग अंतर को कम करना है तथा साथ ही कृषि प्रथाओं को आधुनिक बनाना है। यह 21वीं सदी में भारतीय कृषि को बढ़ाने के लिए आवश्यक तीन स्तंभों जैसे नवाचार, सशक्तिकरण और स्थिरता को एक साथ लाता है।

ड्रोन दीदी योजना के उद्देश्य

ड्रोन दीदी योजना भारत भर में महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के आसपास घूमती है। इन महिलाओं को लोकप्रिय रूप से ₹ड्रोन डिडिज़₹ कहा जाता है, उन्हें कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन संभालने में प्रशिक्षण मिलता है

कीटनाशकों, जड़ी-बूटियों और उर्वरकों को सटीक रूप से छिड़कना हवाई इमेजिंग के माध्यम से फसल स्वास्थ्य की निगरानी करना। कृषि कार्यों में मैन्युअल श्रम को कम करना। जल और उर्वरक जैसे इनपुट का कुशल उपयोग को बढ़ावा देना। योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं

महिला सशक्तिकरणः उन्हें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करके और उन्हें प्रमुख हितधारक बनाकर कृषि में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना। रोजगार सृजनः ग्रामीण महिलाओं को किराये के आधार पर ड्रोन सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाकर स्वरोजगार का अवसर बनाना। कृषि उत्पादकता में सुधारः सटीक खेती के माध्यम से फसल प्रबंधन की दक्षता में सुधार।

कृषि उत्पादकता में सुधारः सटीक खेती के माध्यम से फसल प्रबंधन की दक्षता में सुधार। सतत प्रथाओं को बढ़ावा देनाः कीटनाशकों, उर्वरकों और पानी जैसे संसाधनों के बर्बादी को कम करना। स्वास्थ्य जोखिम को कम करनाः ड्रोन के साथ मैनुअल स्प्रेइंग की जगह लेकर किसानों का हानिकारक रसायनों से प्रत्यक्ष संपर्क कम करना। इस पहल के माध्यम से, महिलाएं न केवल निष्क्रिय प्रतिभागी हैं बल्कि कृषि आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने वाली नेता भी हैं।

कार्यान्वयन रणनीति

ड्रोन दीदी योजना में कई हितधारकों को शामिल करने वाली एक समग्र कार्यान्वयन योजना है

ड्रोन की आपूर्तिः सरकार, नाबार्ड जैसे कृषि विभागों और एजेंसियों के समर्थन से महिला स्व-सहायता समूहों

(एसएचजी) को सब्सिडी दरों पर ड्रोन प्रदान करती है। वित्तीय सहायता क्रेडिट लिंक और अनुदान के माध्यम से व्यवस्था की जाती है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माणः महिला लाभार्थियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्हें ड्रोन चलाने, रखरखाव करने, समस्या निवारण करने और सुरक्षा प्रोटोकॉल को समझने में प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण मॉड्यूल कृषी विज्ञान केन्द्रों (केवीके), कृषि विश्वविद्यालयों और ड्रोन विनिर्माण कंपनियों के सहयोग से डिजाइन किए गए हैं। सेवा-उन्मुख मॉडलः हर किसान के पास ड्रोन होने की बजाय, एसएचजी महिलाएं नाममात्र किराये पर सहकर्मियों को ड्रोन सेवाएं प्रदान करती हैं। यह महिला ऑपरेटरों को आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करते हुए छोटे और सीमांत किसानों के लिए किफायती सुनिश्चित करता है। संस्थागत सहायताः तकनीकी पकड़, रखरखाव समर्थन और निरंतर प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करता है कि महिलाएं प्रारंभिक तैनाती के बाद पीछे न रह जाएं। सरकार ड्रोन के लिए बीमा और लाइसेंसिंग की सुविधा भी प्रदान करती है। निगरानी और मूल्यांकनः राज्य सरकारें तथा स्थानीय कृषि निकाय इस योजना की प्रगति पर नजर रखते हैं ताकि इसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके तथा चुनौतियों का समय पर समाधान किया जा सके।

ड्रोन दीदी योजना के लाभ

ड्रोन दीदी योजना सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से बहुआयामी प्रभाव प्रदान करती है।

1। महिला सशक्तिकरण के लिए

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी और सेवा प्रदाता के रूप में आधुनिक पहचान प्रदान करता है। कृषि निर्णयों के लिए परिवार के पुरुष सदस्यों पर उनकी निर्भरता को कम करता है। वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाकर आय की नई धाराएं उत्पन्न करती है। महिला एसएचजी सदस्यों के बीच आत्मविश्वास और नेतृत्व गुणों को बढ़ावा देता है।

2. कृषि के लिए

ड्रोन कीटनाशकों और उर्वरक के समान छिड़काव को अनुमति देते हैं, जिससे अपशिष्ट कम हो जाता है। समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करके फसल उपज में सुधार करता है। हवाई छवियों का उपयोग करके कीटों के हमलों और बीमारियों का प्रारंभिक पता लगाने में मदद करता है। श्रम निर्भरता को कम करता है और कृषि कार्यों में तेजी लाता है। 3. किसानों के लिए

ड्रोन डिडिस से खरीदने के बजाय लागत प्रभावी सेवाएं। रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष संपर्क से बचकर सुरक्षित कृषि प्रथाएं। प्रभावी इनपुट उपयोग और बेहतर फसल स्वास्थ्य के कारण लाभप्रदता में वृद्धि। 4. पर्यावरण के लिए

सटीक छिड़काव से अत्यधिक रासायनिक उपयोग कम होता है, जिससे मिट्टी और पानी का प्रदूषण कम हो जाता है। संसाधन कुशल और सतत कृषि को बढ़ावा देता है। कार्यान्वयन में चुनौतियां

ड्रोन दीदी योजना में बहुत वादा है, लेकिन इसका ग्राउंड लेवल कार्यान्वयन चुनौतियों का सामना कर सकता है

तकनीकी ज्ञान अंतरः कई ग्रामीण महिलाओं के पास प्रौद्योगिकी का सीमित संपर्क है, जिसके लिए गहन प्रशिक्षण और निरंतर सहायता की आवश्यकता होती है। ड्रोन की उच्च लागतः सब्सिडी के बावजूद, ड्रोन महंगे रहते हैं, जिससे वित्तपोषण और बीमा महत्वपूर्ण होता है। बुनियादी ढांचे की सीमाएंः ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर उचित मरम्मत सुविधाओं, तकनीकी सहायता या ड्रोन सेवा केंद्रों का अभाव होता है। नियामक ढांचाः ड्रोन का संचालन करने के लिए अनुमति, लाइसेंस और विमानन मानकों का अनुपालन की आवश्यकता होती है जो ग्रामीण महिलाओं के लिए नेविगेट करना कठिन हो सकता है। किसानों द्वारा स्वीकृतिः कई छोटे किसान जागरूकता या पारंपरिक मानसिकता की कमी के कारण ड्रोन सेवाओं को अपनाने में संकोच करते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने से योजना की दीर्घकालिक सफलता निर्धारित होगी।

निष्कर्ष

ड्रोन दीदी योजना केवल तकनीकी हस्तक्षेप से अधिक है; यह एक सामाजिक क्रांति है। ग्रामीण महिलाओं के हाथों में ड्रोन डालकर यह योजना उन्हें आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाती है। यह कृषि को आधुनिक बनाता है, संसाधन दक्षता में सुधार करता है

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद्, गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

भूख की आँच में झुलसती मानवता: क्या यही प्रगति है?

जब एक भूखे बच्चे की आँखों में रोटी का सपना धुँधला पड़ता है, तो मानवता की सारी चमक एक पल को थम सी जाती है। न चाँद की उड़ानें, न टेक्नोलॉजी की चकाचौंध, न ही गगनचुंबी इमारतें उस एक निवाले का मोल रखती हैं, जो किसी की भूख मिटा दे। हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस यह कसक जगाता है—यह महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक आह्वान है: एक ऐसी दुनिया बनाने का, जहाँ हर थाली में पौष्टिक भोजन हो और हर भविष्य सुरक्षित। २०२५ की थीम, "बेहतर भोजन, बेहतर भविष्य के लिए एकजुटता," हमें भोजन की उपलब्धता, गुणवत्ता और टिकाऊपन के लिए सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश देती है। यह वह सपना है, जहाँ भूख सिर्फ एक भूली-बिसरी कहानी बन जाए।

1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की स्थापना ने विश्व खाद्य दिवस की नींव रखी, जिसका लक्ष्य था हर इंसान तक भोजन को गरिमा के साथ पहुँचाना। मगर 80 साल बाद भी यह मिशन अधूरा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के मुताबिक, ८२.८ करोड़ लोग आज भी भूख की चपेट में हैं—यह आँकड़ा सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि उन माँओं की चुप्पी है, जो अपने बच्चों को भूखा सुलाती हैं; उन किसानों की पीड़ा है, जो दुनिया को खिलाते हुए खुद भूख से जूझते हैं। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हर साल 1.3 अरब टन भोजन बर्बाद होता है—इतना कि यह पूरे उप-सहारा अफ्रीका को एक साल तक खिला सकता है। एक ओर खाली थालियाँ बेचैन हैं, तो दूसरी ओर डस्टबिन भोजन से अटे पड़े हैं। यह विडंबना हमसे सवाल करती है: क्या हमारी प्रगति अधूरी नहीं?

भारत में यह संकट और गहरा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश होने के बावजूद, ग्लोबल हंगर इंडेक्स २०२४ में भारत 127 देशों में से 105वें पायदान पर है। यहाँ 19.4 करोड़ लोग भूखे हैं, और 43% बच्चे कुपोषण की मार झेल रहे हैं। "अन्नदाता" कहलाने वाला किसान कर्ज, बेमौसम बारिश और बाजार की अनिश्चितताओं में फँसकर अपने परिवार को दो जून की रोटी नहीं दे पाता। फिर भी, भारत की मिट्टी में वह शक्ति है, जो न सिर्फ देश, बल्कि पूरी दुनिया को खिला सकती है। २०२५ की थीम हमें यही सिखाती है कि सरकार, किसान, वैज्ञानिक और समाज की एकजुटता ही वह पुल है, जो खेतों से थालियों तक भोजन पहुँचाएगा। हाथ में हाथ मिलाकर भूख को इतिहास बना दें। भोजन का संकट केवल मात्रा का नहीं, बल्कि पहुँच, गुणवत्ता और समानता का है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि २०२० के बाद से खाद्य कीमतों में २०% की उछाल ने गरीब देशों में भोजन को और दुर्लभ बना दिया। भारत में राशन प्रणाली और सब्सिडी जैसी योजनाएँ हैं, मगर भ्रष्टाचार और अक्षमता के कारण लाखों जरूरतमंद भूखे रह जाते हैं। इससे भी गंभीर है "छिपी भूख" की मार—लाखों लोग भोजन तो खाते हैं, लेकिन पोषण की कमी के कारण बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग जैसे रोग बढ़ रहे हैं। २०२५ की थीम "बेहतर भोजन" यही माँग करती है कि हम केवल पेट भरने नहीं, बल्कि हर व्यक्ति तक पौष्टिक, संतुलित आहार पहुँचाने पर ध्यान दें, जो उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत को संवारे।

२०२५ की थीम पर्यावरण और भोजन के अटूट रिश्ते को भी उजागर करती है। जलवायु परिवर्तन, मिट्टी की घटती उर्वरता, और जल संसाधनों का दोहन हमारी खाद्य प्रणाली को कमजोर कर रहे हैं। एफएओ के मुताबिक, विश्व का 70% जल कृषि में खर्च होता है, जिसका बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। सतत कृषि, जैविक खेती, ड्रिप इरिगेशन, और वर्षा जल संचय अब जरूरत बन चुके हैं। हमें स्थानीय, मौसमी भोजन को बढ़ावा देना होगा, ताकि आयात कम हो और किसानों को लाभ मिले। साथ ही, भंडारण और परिवहन में होने वाली बर्बादी को रोकने के लिए खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना होगा। यह थीम हमें सिखाती है कि बेहतर भविष्य तभी संभव है, जब हम प्रकृति के साथ कदम मिलाएँ।

भारत में भोजन केवल भौतिक जरूरत नहीं, बल्कि संस्कृति और प्रेम का प्रतीक है। "अन्नपूर्णा" का रूप लिए भोजन गाँवों में मेहमानों को खिलाने का गर्व और एकता का संदेश देता है। मगर आधुनिक उपभोक्तावाद ने हमें फास्ट फूड और पैकेज्ड भोजन की चमक में उलझा दिया, जबकि हम अपनी जड़ों बाजरा, ज्वार, रागी जैसे पौष्टिक और टिकाऊ अनाजों को भूलते जा रहे हैं। "बेहतर भोजन" हमें अपनी परंपराओं की ओर लौटने और स्थानीय, पर्यावरण-अनुकूल भोजन को अपनाने का आह्वान करता है, जो न केवल सेहत दे, बल्कि धरती को भी बचाए।

भारत सरकार की योजनाएँ—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम २०१३, मिड-डे मील, पोषण अभियान, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना—भूख और कुपोषण से लड़ने की दिशा में अहम कदम हैं। मगर इनकी सफलता समाज की भागीदारी पर टिकी है। भारत में हर साल 67 मिलियन टन भोजन (अनुमानित कीमत लगभग ९२,००० करोड़) बर्बाद होता है—यह एक त्रासदी है। जरूरत के हिसाब से खाना खरीदना, बचे हुए भोजन को दान करना, और सामुदायिक रसोईघरों में योगदान देना जैसे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। "हाथ में हाथ" मिलाकर भूख को हराएँ और हर थाली को समृद्ध करें। तकनीक भूख के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार बन सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ड्रोन, और सैटेलाइट्स के जरिए फसलों की निगरानी, सटीक मौसम भविष्यवाणी, और स्मार्ट आपूर्ति श्रृंखलाएँ भोजन की बर्बादी को कम कर रही हैं। मगर यह ताकत तभी सार्थक है, जब यह भारत के 86% छोटे और सीमांत किसानों तक पहुँचे, जिनके पास आधुनिक संसाधनों की कमी है। यदि हम इन किसानों को तकनीक, प्रशिक्षण, और बाजार से जोड़ सकें, तो खाद्य सुरक्षा का सपना हकीकत में बदल सकता है। यह एकजुटता ही खेतों से थालियों तक भोजन का सफर सुनिश्चित करेगी। विश्व खाद्य दिवस हमें सिखाता है कि भूख केवल पेट की नहीं, आत्मा की भी होती है। किसी भूखे को भोजन देना सिर्फ उसका पेट भरना नहीं, बल्कि उसकी गरिमा और उम्मीद को पोषित करना है। "हाथ में हाथ" का मतलब है कि यह जिम्मेदारी हम सबकी है। हर थाली में अन्न का होना महज एक लक्ष्य नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक जवाबदेही है। इस विश्व खाद्य दिवस पर संकल्प लें कि हम भोजन की बर्बादी रोकेंगे, जरूरतमंदों के साथ अन्न बाँटेंगे, और एक ऐसी दुनिया बनाएँगे जहाँ भूख सिर्फ एक भूली-बिसरी कहानी हो। क्योंकि जब हर चेहरे पर भोजन की मुस्कान खिलेगी, तभी हमारी धरती सही मायनों में समृद्ध और शांतिपूर्ण होगी।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

उपमण्डल रोजगार कार्यालय बड़खल की सहायक रोजगार अधिकारी डॉ. निकिता यादव ने उड़ाई आरटीआई नियमों की सरेआम धज्जियां

नरेश गुणपाल

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा 1 के तहत उपमण्डल रोजगार कार्यालय बड़खल से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी। लेकिन सहायक राज्य जन सूचना अधिकारी एवं सहायक रोजगार अधिकारी बड़खल द्वारा सूचनाओं का गलत जवाब देकर तथा आधी अधूरी सूचनाएं मुहैया करवाकर आरटीआई नियमों की सरेआम धज्जियां उडाई है ।

उपमण्डल रोजगार कार्यालय बडखल की सहायक राज्य जन सूचना अधिकारी कम सहायक रोजगार अधिकारी द्वारा बिंदु नंबर 1 में मांगी गई सूचना में जवाब दिया कि आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 8(1)(जे) के अंतर्गत मुहैया नहीं करवाई जा सकती है जो यह सूचना थर्ड पार्टी से संबंधित है ।

जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत जब चाहे रोजगार अधिकारी की बायोमेट्रिक एवं हाजरी रजिस्टर की स्थापित कॉपी की मांग की गई तो उन्होंने जवाब दिया कि आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 8(1)(जे) के तहत निजी सूचना के रूप में छूट प्राप्त है ।

उपमण्डल रोजगार कार्यालय बडखल की सहायक राज्य जन सूचना अधिकारी कम सहायक रोजगार अधिकारी द्वारा बिंदु नंबर 1 में मांगी गई सूचना में जवाब दिया कि आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 8(1)(जे) के अंतर्गत मुहैया नहीं करवाई जा सकती है जो यह सूचना थर्ड पार्टी से संबंधित है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जब सहायक रोजगार अधिकारी की बायोमैट्रिक एवं हाजिरी रजिस्टर की स्थापित कॉपी की मांग की गई तो उन्होंने जवाब दिया कि आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 8(1)(जे) के तहत निजी सूचना के रूप में छूट प्राप्त है ।

उपमाण्डल रोजगार कार्यालय बड़खल की सहायक रोजगार अधिकारी द्वारा आरटीआई नियमों के तहत जवाब न देकर यह साबित कर दिया है कि उन्हें आरटीआई नियमों के बारे में पूर्ण रूप से किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है ।

अगर सही स्पष्ट पॉइंट वाइज सूचना सहायक राज्य सूचना अधिकारी बड़खल द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो इस संदर्भ में प्रथम अपील में सुनवाई के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेशों का हवाला देकर मांगी गई सूचनाओं का जवाब लिया जाएगा।

अगर जरूरत पड़ी तो द्वितीय अपील भी की जाएगी द्वितीय अपील में अगर असंतुष्ट हुए तो माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की शरण आरटीआई के गलत जवाब देने की संदर्भ में ली जाएगी ।

सहायक रोजगार अधिकारी बडखल द्वारा आधी अधूरी सूचनाएं देकर तथा आधी अधूरी सूचनाओं के साथ में शिकायत करके यह साबित कर दिया है कि यह नां तो आरटीआई का जवाब है और ना ही यह शिकायत है । इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि साहायक रोजगार अधिकारी बड़खल की बुद्धि लब्धि अपने कार्य के प्रति सही रूप से कार्य नहीं कर रही है ।

इन्दौर के वरिष्ठ पत्रकार अनिल कुमार धडवईवाले जी के 75 वें जन्मदिन पर विशेष –

सच्चाई के लिए लडाने व लिखाने वाले सच्चे कलमकार – अनिल कुमार धडवईवाले जी

हरिहर सिंह चौहान इन्दौर

ये सब कुछ तकदीर की ही बात होती है, देखना है कि नीली छतरी वाला और कितना समय देता है।

इसी तरह समाज सेवा करने हेतु अपना तन-मन और धन समर्पित करने वाले, अपनी बात के पक्के पत्र लेखक से शुरुआत करने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनिल कुमार धडवईवाले जी का नाम इन्दौर में बहुत सम्मनिय स्थान रखता है। अपनी निर्भीकता व बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। आज 16 अक्टूबर 2025 को आप 75 वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहां हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। क्योंकि एक पत्र लेखक से मराठी समाज व अन्य संस्थानों में आप ने सेवा देते हुए वरिष्ठ पत्रकार व समाजसेवी की भूमिका में आप के बढ़ते कदम वाकई काबिले तारीफ है। जमीन से आसमान तक का यहां संघर्ष आप की सफलता की कहानी है। इन्दौर के मराठी समाज के लिए हमेशा जो दीवार की भांति खड़े रहते हैं। जो समाज हित के लिए हर किसी से प्रखर हो जाते हैं । अपनी निर्भीकता व बात के पक्के रहते थे वह ऐसे समाज रत्न अनिल कुमार धडवईवाले जी का व्यक्तित्व पानी की तरह सरल व सहज रहा है। लेकिन वे अपनी बेबाक राय और बोलचाल में परिपक्व है। सत्य व साहस के बल पर ही आप ने यह मुकाम हासिल किया है। जब आप युवावस्था में थे तभी से आप संघर्ष शीलता के साथ अन्याय के खिलाफ मोर्चा खोल लेते थे। मराठी साहित्य कला संस्कृति व समाज के लिए अनिल जी का योगदान पूरे भारत में रहा। वहां जोड़ना जानते लोगों को तभी तो आप क़लम के सच्चे प्रहरी के रूप में अभी भी काम कर रहे हैं। 75 वें बसंत में आप का प्रवेश बहुत प्रेरणादायक है। आप का स्वतंत्र लेखन व पत्रकारिता में महत्वपूर्ण रहा तभी तो आप समाज चिंतन पर पैनी नजर रखते थे। सच्चाई पहुंचाने हेतु आप हमेशा सुत्रधार बने रहे । महाराष्ट्र ब्राह्मण सरकारी बैंक के बारे में आप की बातों पर ध्यान नहीं देने की ग़लती से नुकसान बहुत हुआ । पर समय अनुरूप जो जाग गये उनके लिए अनिल कुमार धडवईवाले जी ने बहुत अच्छा काम किया। जो समझ गये वह समझ गये पर जो नहीं समझें वो अनाड़ी है। आज जरुर वह उम्र की दहलीज पर है शरीर की परेशानी को दरकिनार करते हुए आप आज भी हिम्मत व विश्वास के साथ अपने मिशन में लगे हुए हैं । उनकी दहाड़ आज भी शेर के जैसी है। इस लिए सच्चाई के लिए लडाने वाले क़लम के सच्चे प्रहरी बने हुए हैं। समाजिक, सहकारिता, साहित्यिक, ललित कला अकादमी और पत्रकारिता में आप की उपलब्धि बहुत है। ऐसे तो आप को इन्दौर में बहुत मान सम्मान मिला पुरस्कार भी बहुत मिलें , पर आप का सबसे बड़ा पुरस्कार 1987 में जब आप के नागरिक अभिनंदन में आप की मां के द्वारा आशीष मिला था। वहीं आशीर्वाद ने आपको सच्चाई की दिशा दिखाई थी। आप को बहुत बड़े बडे. पत्रकारों का प्यार व स्नेह और मागदर्शन मिलता रहा है। मुर्धन्य पत्रकार राजेन्द्र माथुर जी की बातों से आप बहुत प्रभावित थे। माथुर जी ने अनिल जी से कहा था कि निरंतर लौ लगाकर काम करते रहो, तो यह संभव ही नहीं की कोई असर न हो। 16 अक्टूबर 2025 आज आप के जन्मदिन पर हम यही चाहतें हैं कि दिलदार व जिंदादिल समाजिक कार्यकर्ता व चौथे स्तंभ के सजग प्रहरी आप की क़लम से हमें आगे बढ़ने व सच को बोलने व लिखने की प्रेरणा मिलती रहे। आप को सभी साहित्यकारों लेखकों व पत्रकारों की और से बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आप ने अपनी सृजनात्मकता रचानात्मकता अभिव्यक्ति के मध्यम से कहा है , कि ज़िन्दगी की असली उड़ान अभी बाकी है

ज़िन्दगी के कई इन्तिहान अभी बाकी है
अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने नापी
अभी तो सारा आसमां जीतना बाकी है।

यहीं सच्चाई के लिए लडाने वाले क़लम के सच्चे प्रहरी की पत्रकारिता व साहित्यिक कला संस्कृति का परिदृश्य है ।

शीर्षक - धनत्रयोदशी

तीज तेरस अनूठे शुभ मुहूर्त ये, नव निधि और सौभाग्य लाएं,
आरोग्यता और सुख समृद्धि, जीवन में ₹आनंद₹ को बढाएं ।

धनत्रयोदशी तिथि को सभी, धनवंतरि का आशीर्वाद पाएं,
स्वस्थ तन–मन संग अक्षय धन, का ये संयोग खुशियॉं बरसाएं ।

कर आराधना यक्षराज कुबेर की, अपने भाग्य को स्वयं चमकाएं,
धन–धान्य का हो शुभ आगमन, श्रद्धा प्रेम भाव से कीर्तन गाएं ।

गृह क्लेश मनमुटाव से दूर रहें, परिवार संग सदा हॅंसे मुस्काएं,
बहुत चंचल है माता महालक्ष्मी, प्रेम सौहार्द शांति आप बनाएं ।

सुखों का करें हम आदान–प्रदान, फूल खुशियों के मिलकर खिलाएं,
ऊॅंच–नीच की बेतूकी लकीरों को, चलो चुपचाप आज हम मिटाएं ।

प्रसन्नता का संगीत हो बिखरा, त्योहारों की जगमग रौनक बढाएं,
सेतू बनकर गरीब परिवारों तक, नयी खुशियॉं धीरे से पहुंचाएं ।

कुछ खुशियों को सहर्ष बांटे, भीतर आत्मिक चमक जगाएं,
धन के प्रवाह को प्रेम रंग में रंग, करोड़ों दिलों में जगह बनाएं ।

व्यवसाय की हो चौगुनी प्रगति, थोड़ा अवश्य दान धर्म अपनाएं,
संस्कारों का रखें सदा मान भी, और खुशी–खुशी नाचें गाएं ।

निज संस्कृति पर करें गर्व, व्यहवार को हमेशा मृदु बनाएं,
स्वार्थ की सवारी को त्याग, सूरज सा उजाला सर्वत्र फैलाएं ।

महत्ता उत्सवों की है अलग, जाने समझे व अपनी रूचि बढ़ाएं,
भक्ति और भाव का हो संगम, अनगिनत दुआएं जीवन में कमाएं ।

मोनिका डागा "आनंद" , चेन्नई, तमिलनाडु
आपके स्नेह और प्यार का धन्यवाद !

यह सरायकेला का बालू है लूटना आसान है, लूट सके तो लूट

एन जी टी आदेश आज समाप्त होगा ,फिर तो चांदी ही चांदी ......

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची, ईचागढ़ अनुमंडल से अवैध बालू कारोबार पर जहां सरायकेला खरसावां पुलिस की भागीदारी , अन्तर लिप्तता के कारण प्रशासन की निष्क्रियता देखी जा रही वह मौनम् सम्मति लक्षणम् कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कदाचित नहीं कहलायेगा । वहीं विगत सोमवार को बुंडू के एक प्रशासनिक पदाधिकारी रंगमाटी टिकर मोड़ में शाम गाड़ी पकड़ते देखें गये । बताया जाता है कि उन्होंने यहां पांच हाईवा को धर दबोचा। पर कुछ देर के बाद हाईवा छुट गये । जहां बूडूं अधिकारी ने क्या पाया, क्या कारवाई की यह अब तक पता नहीं चला है !!

अलबत्ता उन पांच हाईवा के मालिक का नाम हमें पता है । उनमें एक ने तो उसी दिन इस अभियान में स्वयं को उतारा था । आर्थिक भार से बेचारी की कमर अब टूट चुकी है ।

उसके एक दिन बाद से जरगोडीह से अवैध हाईवा लोड लेकर समुह में निकल रहा हैं । अब अवैध बालू चलाने वाले भी बुंडू प्रशासन के कारवाई से अपना टाइमिंग अब चेंज किये हुए हैं । गाड़ियां अब भी सैकड़ों की संख्या में चल रही है। गत रात से पूरी रात अवैध बालू का कारोबार जारी रहा । इचागढ़ थाना क्षेत्र में यह कारोबार जारगोडीह बालू घाट से रोज रात को अवैध बालू उठाया जा रहा है इसका तस्करी थाना द्वारा संरक्षण देकर किये जाने का आरोप है। राजस्व नुकसान के इस कारोबार में राज्य का खनिज लूटा रहा है और लूट से तिजोरियां भर अपनी-अपनी संपत्ति बना रहे हैं रक्षक पुलिस , माफिया, अधिकारी !

घाटशिला विधानसभा चुनाव हेतु चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल को भाजपा ने दिया टिकट

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

जमशेदपुर , विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा उप-चुनाव 2025 हेतु संप्रति सरायकेला विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री पुत्र बाबूलाल सोरेन घाटशिला सीट से चुनाव लड़ेंगे.भाजपा पार्टी स्तर से इसकी विधिवत अधिकारिक घोषणा कर दी गई है.

उस सत्तर - अस्सी के दशक में जेएमएम के एक साधारण आन्दोलन कर्ता के रूप में उभरे चंपाई सोरेन ने लम्बी पारी खेलते हुए झामुमो पार्टी के महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने के बाद भाजपा में विगत चुनाव पूर्व चले गये थे . जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्रवाई से जेल से निकले के बाद उन्हें कुर्सी मांग रख दी थी । इस राजनीति खेल ने अब अगली पीढ़ी के नेताओं को घाटशिला मैदान में उतारा है । देखना दिलचस्प होगा ऊट किस दिशा में करबट ले रहा है ।

विधायक चंपाई के बेटे बूबूलाल सोरेन ने 2024 का विधानसभा चुनाव भी यही से पहली वार लड़ा था, 80 दशक के झारखंड अलग राज्य आन्दोलन के उपज रहे दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से वे हार गये थे. झारखंड राज्य बनने के बाद साल 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान घाटशिला सीट पर कांग्रेस के प्रदीप कुमार बलमुचू ने जीत दर्ज कराई थी. 2009 के इलेक्शन में जेएमएम के टिकट पर रामदास सोरेन की जीत हुई. 2014 के चुनाव में भाजपा के लक्ष्मण टुडू यहां से विधायक चुने गए. जो चंपाई सोरेन से सरायकेला सीट प्रतिद्वंद्वी रहते हार गये थे. इतना ही नहीं चंपाई सोरेन को सरायकेला - (51आ ज जा सीट से) हराने वाले आर एस एस छवि के उस लोकप्रिय नेता अनंत राम टुडू का टिकट काट कर 2005 चुनाव मे तब पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा खेमे ने लक्ष्मण टुडु को उतारा गया था, तब अडवाणी एवं राजनाथ सिंह द्वारा नव गठित प्रदेश में भाजपा की भविष्य लिखी जा रही थी .उस समय ईचागढ़ विधायक अरविंद सिंह, मंत्री मधुकोड़ा आदि सिटिंग विधायक , मंत्रियों तक का टिकट रणनीतिकारों ने छीना था . नतीजतन कुछ समय के बाद भाजपा काफी कमजोर हो गयी .जिसकी आजतक समिक्षात्मक आकलन हुआ ही नहीं अला कमान द्वारा , इसे करना मतलब अपने पैर मे कुल्हाड़ी मारने बराबर माना जा रहा है . उल्टे जेएमएम तथा उन दिनों की हाईजैक्ड भाजपा आगे यहां मिलकर राजनीति कर सरकार बनाती गिराती रही . परिणाम यह हुआ कि जेएमएम नामक पौधे को पल्लवित पुष्पित होने का भरपुर उर्जा मिलाता रहा . आज भाजपा की अन्दरूनी हालात को देखने से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है उस दौर का हकीकत !

इसी प्रकार घाटशिला सीट से 2019 में हुई विधानसभा चुनाव में जेएमएम के रामदास सोरेन ने जीत दर्ज की. 2024 के विधानसभा चुनाव में भी जेएमएम के रामदास सोरेन जीते थे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन दूसरे नंबर थे । जिनके पिता चंपाई जेएमएम से मुख्यमंत्री बने थे ।

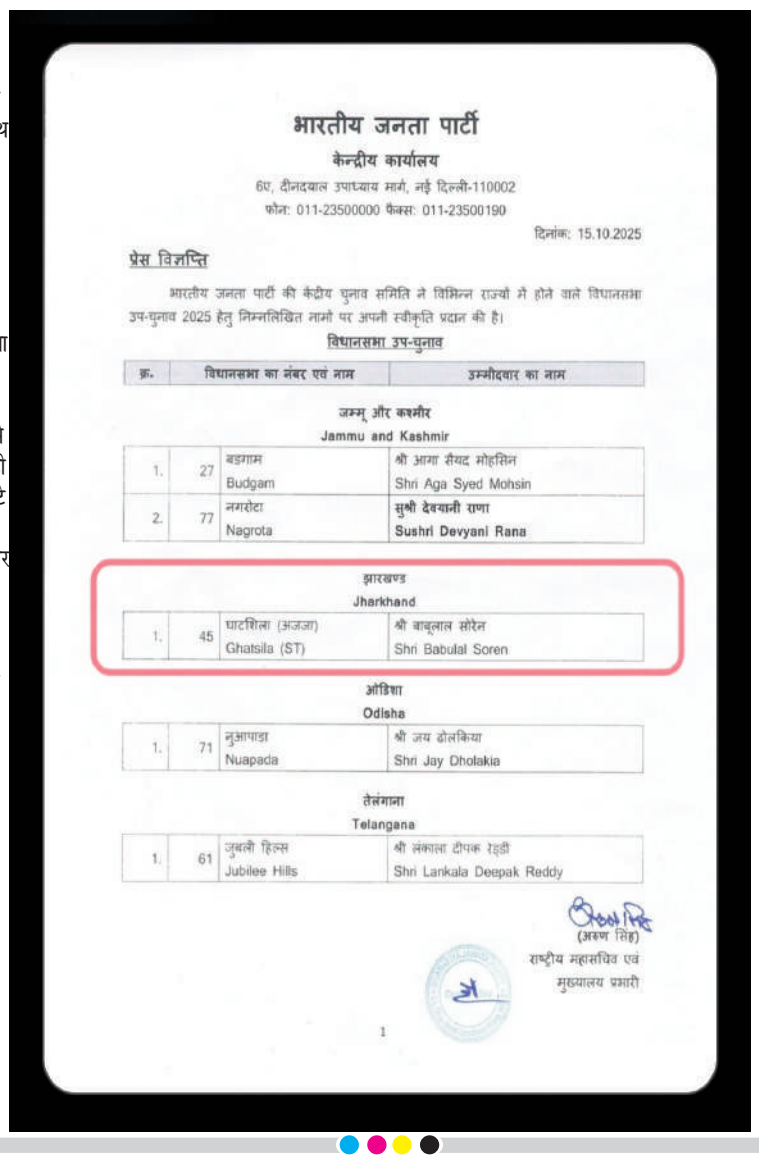

भारतीय जनता पार्टी
केन्द्रीय कार्यालय
6ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन: 011-23500000 फैक्स: 011-23500190

दिनांक: 15.10.2025

प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा उप-चुनाव 2025 हेतु निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

विधानसभा उप-चुनाव

क्र.	विधानसभा का नंबर एवं नाम		उम्मीदवार का नाम
	जम्मू और कश्मीर / Jammu and Kashmir		
1.	27	बडगाम Budgam	श्री आगा सैयद मोहसिन Shri Aga Syed Mohsin
2.	77	नगरोटा Nagrota	सुश्री देवयानी राणा Sushri Devyani Rana
	झारखण्ड / Jharkhand		
1.	45	घाटशिला (अजजा) Ghatsila (ST)	श्री बाबूलाल सोरेन Shri Babulal Soren
	ओडिशा / Odisha		
1.	71	नुआपाडा Nuapada	श्री जय ढोलकिया Shri Jay Dholakia
	तेलंगाना / Telangana		
1.	61	जुबली हिल्स Jubilee Hills	श्री लंकाला दीपक रेड्डी Shri Lankala Deepak Reddy

(अरुण सिंह)
राष्ट्रीय महासचिव एवं
मुख्यालय प्रभारी

1

झारखंड के ग्यारह अरब डीएमएफटी फंड घोटाले के पर कोर्ट ने सरकार से मांगा जबाव

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड

रांची , झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में डीएमएफटी फंड में अनियमितता की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।

इस दौरान अदालत ने शिकायतकर्ता की ओर से दाखिल हस्तक्षेप याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया। अदालत ने हस्तक्षेप याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में डा. राजकुमार ने हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा ने अदालत को बताया कि बोकारो में डीएमएफटी फंड की लूट हुई है। बिना टेंडर और बिना काम के ही पैसे की निकासी कर ली गई है। वर्ष २०16 से लेकर अब तक 11 अरब रुपये की गड़बड़ी हुई है। डीएमएफटी फंड केंद्र सरकार की ओर से प्रदान किया जाता है।

उक्त राशि खनन क्षेत्र और वहां के लोगों के विकास पर खर्च किया जाना है। राज्य सरकार के अधिकारी और उपायुक्त की समिति पैसे खर्च करने की अनुशंसा करती है। लेकिन बोकारो में 80 प्रतिशत राशि बिना काम के ही हड़प ली गई है। उच्च न्यायालय ने डीएमएफटी में 11 अरब रुपये के घोटाले पर सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि बिना काम किए ही राशि निकाल ली गई। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर घोटाले के आरोपों पर स्पष्टीकरण देने को कहा है और पूछा है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है।

कांग्रेस प्रत्याशी घासीराम माझी ने नामांकन दाखिल किया

मनोरंजन सासमल , बरिष्ठ पत्रकार

भूबनेश्वर : घासीराम माझी ने नामांकन दाखिल किया। घासीराम माझी कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए हैं। घासीराम ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। 2024 के चुनाव में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और दूसरे स्थान पर रहे थे। पिछले चुनाव में गाजीराम को 51,000 वोट मिले थे, जो सिर्फ़ आदिवासी जुड़ाव की वजह से ही मिले थे ।पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था कि यह उनका आखिरी चुनाव है। अगर वे हार भी गए, तो भी संघ के साथ बने रहेंगे। लेकिन हार के बाद वे फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए, जो आदिवासी कल्याण संघ को पसंद नहीं है। खबर तो यह भी है कि संघ ने उन्हें आदिवासी विरोधी गतिविधियों के लिए एक साल के लिए निष्कासित भी कर दिया है।

गौरतलब है कि कांग्रेस उम्मीदवार घासीराम माझी ने 2024 का आम चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ा था। वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शरत पटनायक पार्टी के उम्मीदवार बन गए। इससे असंतुष्ट होकर घासीराम निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे। घासीराम का बीजद उम्मीदवार राजेंद्र ढोलकिया से कड़ा मुकाबला था। कांग्रेस उम्मीदवार और तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शरत पटनायक महज 15,000 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे। नुआपाड़ा उपचुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दिवंगत राजेंद्र ढोलकिया के पुत्र जय ढोलकिया भाजपा उम्मीदवार हैं। वह 11 तारीख को भाजपा में शामिल हुए। जय 16 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जय ढोलकिया के नामांकन के समय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मौजूद रहेंगे।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जोरदार ऐलान: बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को सिंबल वितरण के साथ जीत की अग्रिम बधाई!

परिवहन विशेष न्यूज

पटना: बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को जोरदार धक्का देते हुए अपने उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल सौंपा और जीत की अग्रिम बधाई के साथ जोश भर दिया। यह टिकट वितरण समारोह न केवल एक औपचारिकता था, बल्कि पार्टी की अटूट एकजुटता और विजयी संकल्प का प्रतीक बन गया, जहां हर उम्मीदवार ने बिहार की जनता के प्रति अपनी निष्ठा का संकल्प दोहराया।

केंद्रीय पर्यवेक्षक डॉ. राजकुमार यादव ने उम्मीदवारों के साथ गहन बातचीत के दौरान चुनावी रणनीति का खुलासा किया, जो बिहार की सड़कों से लेकर गांवों तक गूंजने वाली है। डॉ. यादव ने कहा, ₹यह चुनाव केवल सीटें जीतने का नहीं, बल्कि बिहार की युवा शक्ति, किसानों की समृद्धि और महिलाओं की गरिमा को मजबूत करने का अवसर है। हमारी रणनीति जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन, डिजिटल अभियान और जन-जन से सीधा संवाद पर आधारित है। हर बूथ पर विजय का नारा गूंजेगा!₹ उनकी यह बातें उम्मीदवारों में नई ऊर्जा का संचार कर गईं, जो अब मैदान में उतरने को बेताब हैं।

समारोह में पार्टी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी ने इसे और भी प्रभावशाली बना दिया। प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत सिंह ने उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए कहा, ₹बिहार की धरती पर राष्ट्रवाद की लहर छाने वाली है। हम हर चुनौती को अवसर में बदलेंगे!₹ वहीं, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष रंजन प्रियदर्शी ने रणनीतिक योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए जोर दिया कि ₹हमारा फोकस विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय पर रहेगा।₹ समिति के सदस्य अतुल्य गुंजन और राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस बिहार प्रदेश अध्यक्ष अदनान अजीम ने युवाओं की भूमिका पर बल देते हुए युवा शक्ति को चुनावी मशीनरी का इंजन बताया।

यह सिंबल वितरण समारोह पार्टी की मजबूत संगठनात्मक क्षमता का प्रमाण है, जो बिहार चुनाव में अप्रत्याशित प्रदर्शन की उम्मीद जगाता है। उम्मीदवारों ने एक स्वर में कहा, ₹जनता का आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जीत निश्चित है!"

आखिरकार पूर्व न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने हिंदुत्व के प्रति अपनी निष्ठा साबित कर दी...

हर्ष मंदर, अनुवाद : ज़फ़र इक़बाल

"अयोध्या में विवादित भूमि पर आए महत्वपूर्ण फ़ैसले के बाद भारत में कुछ परिवर्तन हो गया है, कुछ बदल गया है, कुछ टूट गया है।"

2019 में सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सर्वसम्मति से दिए गए ऐतिहासिक फ़ैसले के कुछ दिनों बाद मैंने यह पंक्ति लिखी थी, जिसमें इस पूरी जगह को, जहां कभी मध्ययुगीन बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, हिंदू पक्षकारों को भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए दे दिया गया था। 1992 की सर्दियों में हिंसक भीड़ ने मस्जिद को गिरा दिया था, जिसे कई लोग गांधीजी की हत्या के बाद स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे दुखद दिन मानते हैं।

हाल के महीनों मेरी लिखी यह पंक्ति मुझे कई बार परेशान करती रही। सबसे पहले तब, जब इस मामले में निर्णय देने वाले न्यायाधीश ने दावा किया कि उस फ़ैसले को लिखने में उन्हें ईश्वर द्वारा मार्गदर्शन मिला था, और वह एक धर्मनिष्ठ हिंदू हैं। इसलिए, उनके अनुसार, एक ऐसा फैसला लिखने में उन्हें एक हिंदू ईश्वर ने रास्ता दिखाया, जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक धार्मिक विवाद था!

और अब जब उसी न्यायाधीश ने यह घोषित किया कि 1528-29 में बाबर के एक सैन्य कमांडर द्वारा मस्जिद का निर्माण ही **'अपवित्र कृत्य'** था, न कि 1992 में लोकतांत्रिक भारत में एक उन्मादी भीड़ द्वारा क़ानून, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और संवैधानिक नैतिकता की अवहेलना करते हुए उसे ध्वस्त करना, यह हिंसक भीड़ द्वारा मस्जिद को ध्वस्त करने का नैतिक बचाव है। कई पत्रकारों को दिए गए ग़ैर पारंपरिक साक्षात्कारों के बाद डीवाई चंद्रचूड़ की नैतिक और राजनीतिक स्थिति सार्वजनिक जांच के दायरे में आ गई है। डीवाई चंद्रचूड़ हाल ही तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदस्थ थे और 2019 का वह फ़ैसला उन्होंने अन्य न्यायाधीशों के साथ मिलकर लिखा था, जिस फ़ैसले ने मध्ययुगीन बाबरी मस्जिद को भीड़ द्वारा ढहा दिए जाने के बाद उस परिसर की भूमि को भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए दे दिया गया था।

उनका यह अवलोकन आरएसएस और उसकी राजनीतिक शाखा, भाजपा के हिंदुत्व के मूल वैचारिक दृष्टिकोण के प्रति उनकी अडिग निष्ठा को दर्शाता है।

22 जनवरी, 2024 को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का वृहद सार्वजनिक आयोजन तथा धार्मिक समारोह उसी भूमि पर हुआ, जहां बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखित और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के बाद यह संभव हुआ।

आरएसएस के सर्वोच्च नेता मोहन भागवत ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को भारत की **'सच्ची स्वतंत्रता'** के रूप में चिह्नित किया, जिसने सदियों के **'पराचक्र'** या विदेशी आक्रमण को समाप्त कर दिया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कुछ दिनों बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री को उन्हीं शब्दों में बधाई दी, जो बाद में आरएसएस प्रमुख ने कहे। कैबिनेट ने घोषणा की कि 1947 में भारत का केवल शरीर मुक्त हुआ था। इसकी आत्मा तब मुक्त हुई, जब बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। और फिर चंद्रचूड़ ने मस्जिद के निर्माण को **'अपवित्र कृत्य'** बताया और इस तरह इसके विध्वंस तथा इसके खंडहरों पर हिंदू मंदिर के निर्माण को उचित ठहराया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल, आरएसएस प्रमुख और अब भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई ये तीनों सार्वजनिक अभिव्यक्तियां इतिहास के हिंदुत्ववादी संस्करण से पूरी तरह मेल खाती हैं।

प्रधानमंत्री अक्सर यह बात दोहराते रहते हैं कि भारतीय जनता ने दो शताब्दियों तक केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों की दासता ही सहन नहीं की है, भारत के लोगों ने मुस्लिम **'विदेशी आक्रमणकारियों'** की ग़ुलामी भी झेली, जो कहीं अधिक क्रूर थे, जिन्होंने 1000 वर्षों तक निरंकुश शासन किया। वे समान रूप से क्रूर, बर्बर और कट्टरपंथी थे, जिन्होंने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, हिंदू धर्म का अपमान किया, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया और बड़ी संख्या में हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया।

मस्जिद निर्माण के **'काल्पनिक'** दावे?

मोदी सरकार द्वारा हाल ही में संशोधित इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में, अकबर को भी एक धार्मिक कट्टरपंथी के रूप में फिर से पेश किया गया है। यह भारतीय इतिहास का अत्यधिक दोषपूर्ण, भड़काऊ और सांप्रदायिक पुनर्लेखन है, जिसे डीवाई चंद्रचूड़ मौन समर्थन देते हैं, जब वह अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण को मौलिक अपवित्र कृत्य के रूप में चित्रित करते हैं, लेकिन 1992 में एक हिंसक भीड़ द्वारा मस्जिद को ढहाए जाने को नहीं। अपनी परिणति में यह विध्वंस सांप्रदायिक आक्रामकता और हिंसा का एक आपराधिक कृत्य नहीं था, जिसके बाद देश भर में हिंसा हुई। इसके बजाय यह पुनर्स्थापना का एक ऐसा काम था, जिसका बचाव किया जाना चाहिए।

यह वही वैचारिक तर्क है जिसका सहारा लेकर उन्होंने 1991 के उपासना स्थल अधिनियम के स्पष्ट निषेधों के बावजूद वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति दी। इसके लिए जटिल तर्क का सहारा लिया गया कि 1991 का क़ानून धार्मिक स्थलों की धार्मिक स्थिति को बदलने पर रोक लगाता है, लेकिन यह धार्मिक स्थिति की तथ्यात्मक पड़ताल से नहीं रोकता है।

उनका दावा है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि सदियों से मंदिर के नीचे तहख़ाने में हिंदू पद्धति से पूजा होती रही है। हालांकि यह पूरी तरह से असत्य है, जिसका मुस्लिम पक्षकारों ने खंडन किया है, और साथ ही यह क़ानून के अक्षरशः अर्थ तथा भावना के उनके विरोधाभासी अर्थ को भी स्पष्ट नहीं करता। इस मौखिक आदेश से उन्होंने इतिहास में किसी समय मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों के कई दावों के लिए दरवाज़े खोल दिए, जिससे पीढ़ियों तक सांप्रदायिक नफ़रत, आक्रोश और रक्तपात की आग भड़कना तय है।

उनके इस दावे में कई पेचीदा समस्याएं हैं —

अनुभवजन्य, ऐतिहासिक, क़ानूनी, नैतिक और संवैधानिक — कि 1528-29 में मस्जिद का निर्माण मौलिक या प्राथमिक रूप से अपवित्र कृत्य था। इसी आधार पर राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि सौंपने वाले 2019 के फ़ैसले का उनका बचाव, स्वयं फ़ैसले से भी अधिक उलझा हुआ और अतार्किक है।

सबसे पहले, यह दावा उनके अपने फ़ैसले के निष्कर्षों का खंडन करता है। फ़ैसले में पुरातात्विक निष्कर्षों का हवाला दिया गया है कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक अन्य पूजा स्थल -- संभवतः हिंदू — के खंडहर थे। लेकिन शोध इस बात की पुष्टि करता है कि मूल मंदिर के अनुपयोगी होने के बाद से लगभग चार शताब्दियां बीत चुकी थीं। इससे स्पष्ट होता है कि मस्जिद का निर्माण मूल मंदिर को ध्वस्त करके नहीं किया गया था।

पुरातात्विक शोध इस बात की भी पुष्टि नहीं करता है कि मंदिर को चार शताब्दी पहले ध्वस्त ही किया गया था। यह भी संभव है कि किसी प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गया होगा, या किसी अन्य कारण से इसे त्याग दिया गया होगा। फिर मस्जिद के निर्माण से हुई अपवित्रता कहां थी, जिसकी ओर चंद्रचूड़ इशारा करते हैं?

कथित ऐतिहासिक ग़लतियों का सुधार चुनिंदा?

पुरातात्विक शोध के निष्कर्षों से परे भी, उनके तर्क में एक गहरी नैतिक और क़ानूनी त्रुटि है।

भले ही सदियों पहले किसी विशेष पहचान के लोगों द्वारा ऐतिहासिक ग़लतियां की गई हों, फिर भी आज उस पहचान के लोगों को नुक़सान पहुंचाकर इतिहास की वास्तविक और कथित ग़लतियों को सुधारना किस तरह से नैतिक, न्यायसंगत या वैध है? और अगर समाज इस बात पर ज़ोर देता है कि ऐसे सुधार ऐतिहासिक ग़लतियों के प्रतिशोध या प्रतिपूर्ति के लिए उचित हैं, तो फिर ये चयनात्मक क्यों होने चाहिए?

यह निर्विवाद है कि विशेषाधिकार प्राप्त जातियों ने वंचित जातियों में जन्मे लोगों को कम-से-कम 2000 वर्षों से लगातार उत्पीड़न का शिकार बनाया है, ऐसा उत्पीड़न जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसमें अस्वच्छ माने जाने वाले कामों में जबरन मज़दूरी, यौन हिंसा, शिक्षा और साझा पूजा के अधिकारों से वंचित करना, और अनगिनत अन्य प्रकार के दैनिक अपमान तथा भेदभाव शामिल हैं। प्रत्येक जाति की महिलाओं को अधीनस्थ का दर्जा दिया गया है, जिसमें स्वतंत्रता, शिक्षा और काम से वंचित करना तथा निरंतर हिंसा का एक दंडात्मक चक्र शामिल है।

ये मुस्लिम शासकों द्वारा किए गए वास्तविक या काल्पनिक अत्याचारों के सामने बौने हैं। तो फिर, अगर इतिहास के अपराधों का प्रतिशोध क़ानून और सार्वजनिक नैतिकता में स्वीकार्य है, तो हमें सुविधासंपन्न जातियों और पुरुषों से इसकी शुरुआत क्यों नहीं करनी चाहिए?

फैसले के बचाव की कमज़ोर कोशिशें

पूर्व न्यायाधीश ने जिस फ़ैसले का बचाव करने की कोशिश की, उसमें भी तर्क की कई रहस्यमयी फांकें हैं। न्यायाधीश स्वीकार करते हैं कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का कोई सबूत नहीं है। अदालत इस बात को भी ध्यान में रखती है कि मंदिर निर्माण स्थल पर कम-से-कम दो आपराधिक कृत्य हुए थे।

इनमें से पहला था 1949 में मस्जिद में राम की मूर्ति को चोरी-छिपे और ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से स्थापित करना, जिसके कारण मस्जिद में इबादत बाधित हुई। दूसरा था, 1992 में एक उन्मादी भीड़ द्वारा मस्जिद को ढहा दिया जाना, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने जिसका जश्न मनाया और उसे बढ़ावा दिया। और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तथा सभी धर्मों की समानता की संवैधानिक गारंटी की खुलेआम अवहेलना थी। इसके परिणामस्वरूप सांप्रदायिक जनसंहारों का एक दौर शुरू हो गया, जिसमें हज़ारों मौतें हुईं और सामाजिक ताना-बाना बुरी तरह से छिन्न-भिन्न हो गया।

न्यायाधीश इसे एक गंभीर आपराधिक कृत्य बताते हैं। इन सबके बावजूद, जिन लोगों ने क़ानून की धज्जियां उड़ाईं, उन्हें पुरस्कृत किया गया और जिन लोगों ने क़ानून का पालन किया, उन्हें दंडित किया गया।

पूर्व न्यायाधीश चंद्रचूड़ अब पांच न्यायाधीशों की ओर से लिखे गए 2019 के ऐतिहासिक फ़ैसले का बचाव करने के लिए जो तर्क दे रहे हैं, उनमें भी यही क़ानूनी और नैतिक विसंगतियां है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्षकारों को प्रतिकूल क़ब्ज़े का क़ानूनी अधिकार इसलिए नहीं दिया गया, क्योंकि मुसलमानों ने **'संरचना के संपूर्ण भाग** पर निर्विवाद और पूर्णतः निश्चित तथा निरंतर क़ब्ज़ा स्थापित नहीं किया था', लेकिन यह स्वीकार किया जाता है कि मुसलमान कम-से-कम 100 वर्षों तक मस्जिद में लगातार नमाज़ पढ़ते रहे।

दूसरी ओर, बाहरी प्रांगण में हिंदुओं की पूजा पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई थी, इसलिए वे प्रतिकूल क़ब्ज़े के लिए योग्य थे। इसका अर्थ यह हुआ कि हिंदू पक्षकारों ने मुस्लिम पूजा में ग़ैरक़ानूनी व्यवधान डाला था, जबकि मुस्लिम पक्षकारों ने क़ानून का पालन किया और हिंदुओं के पूजा के अधिकार का सम्मान किया। लेकिन यह फिर से उनके ख़िलाफ़ गया, जबकि क़ानून तोड़ने वालों को पुरस्कृत किया गया।

मुसलमानों को इसलिए दंडित किया गया, क्योंकि उन्होंने ग़ैर-क़ानूनी तरीक़े से लड़ने के बजाय क़ानून का पालन करने का रास्ता चुना!

आस्था बनाम कानून

यह भी सवाल उठा कि अदालत के फ़ैसले आस्था पर आधारित थे या क़ानून पर। मामले की सुनवाई करने वाली पीठ के पांच सदस्यों में से एक अनाम न्यायाधीश ने मुख्य निर्णय के परिशिष्ट में लिखा कि उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं के कारण इस फ़ैसले का समर्थन किया। निर्णय के मुख्य भाग में यह दावा भी शामिल है कि हिंदुओं का मानना है कि विवादित भूमि **'भगवान** विष्णु के अवतार, भगवान राम का जन्मस्थान' थी। पहली नज़र में यह तथ्यात्मक रूप से असत्य है।

अयोध्या में ऐसे कई मंदिर हैं, जो दावा करते हैं कि राम का जन्मस्थान यहीं था। और कुछ उपासकों का मानना है कि अयोध्या कहीं और स्थित थी। इससे भी ज़्यादा प्रासंगिक बात यह है कि यह उस निर्णय के लिए कैसे प्रासंगिक हो सकता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह आस्था पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से क़ानून पर आधारित है?

बाद में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा यह दावा करने से मामला और भी उलझ जाता है कि ईश्वर ने ही उन्हें यह निर्णय लिखने के लिए प्रेरित किया।

जब पूछा गया कि मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए विवादित स्थल के एक हिस्से पर ज़मीन क्यों नहीं दी गई, तो चंद्रचूड़ द्वारा दिया गया तर्क एक ऐसे न्यायाधीश के लिए अजीब था, जिसे मालिकाना हक़ के मुक़दमे (टाइटल सूट) में क़ानून के सवालों पर विचार करने के लिए कहा गया हो।

उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों ने ऐसा न करने का फ़ैसला इसलिए किया, क्योंकि वे **'उसी स्थिति को बरक़रार नहीं** रखना चाहते थे, जिसने सदियों से अनगिनत हिंसा और संघर्ष को जन्म दिया है'। वे एक ऐसे फ़ैसले के ज़रिए सामाजिक शांति बहाल करना चाहते हैं, जो मुस्लिम वादी पक्ष के क़ानूनी तथा संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ अपने निहितार्थ में व्यापक मुस्लिम समुदाय के साथ स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण है।

सिर्फ़ उस न्यायाधीश की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता ही दांव पर नहीं है, जो देश के सर्वोच्च पद पर थे और जिन पर न्याय देने वाले अंतिम मध्यस्थ होने का दायित्व था। इससे यह निष्कर्ष तो निकलता ही है कि वे भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संविधान की रक्षा करने में बुरी तरह विफल रहे।

लेकिन सड़ांध की कई और परतें हैं। यह स्पष्ट है कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं, जिनमें न्यायालय भी शामिल हैं, बहुसंख्यकवादी राजनीतिक संरचनाओं के विजय अभियान को रोकने में सक्षम नहीं हैं, जो भारत के संवैधानिक व्यवस्था से पूरी तरह से विचलित हैं, या यहां तक कि हर धर्म तथा पहचान के लोगों के लिए समान अधिकार और समान सम्बद्धता वाले गणराज्य के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया भी रखती हैं।

भारत आज एक ऐसे राज्य का गवाह बन रहा है, जो अपने मुस्लिम नागरिकों के साथ प्रभावी रूप से युद्धरत है और उनके कई संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है। ऐसे समय में, न्यायपालिका ही उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए अंतिम सहारा है। लेकिन अगर भारत के न्यायाधीश बहुसंख्यकवादी विचारधाराओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करते हैं और यहां तक कि उसका सार्वजनिक प्रदर्शन भी करते हैं, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संविधान की गारंटी को नष्ट करता है और नकारता है, तो वे किधर जाएंगे?

जैसा कि मैंने 2019 के अयोध्या फ़ैसले के बाद लिखा था: "यह फ़ैसला, अंततः, इस बात का एक बेहद चिंताजनक संकेत है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से यह दिशा स्पष्ट रही है। हालांकि, हमें अभी भी उम्मीद थी कि भारत की सर्वोच्च अदालत इस भयावह अंधकार तथा इस तूफ़ान के ख़तरों में हमारे जहाज़ को संभालेगी; कि यह हवाओं से लड़ने के लिए उठ खड़ी होगी और हमें उस शांति और समान नागरिकता के रास्ते पर वापस लाएगी, जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता संग्राम में की गई थी और जिसका संकल्प हमारे संविधान में किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतिहास इस क्षण को लंबे समय तक याद रखेगा, कि जैसा यह था, और जैसा यह हो सकता था।"

(लेखक एक स्तंभकार, शोधकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज के निदेशक हैं।)

फिक्की फ्लो अमृतसर ने सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्याओं को दी आर्थिक सहायता — अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर

अमृतसर, 15 अक्टूबर (साहिल बेरी)

जिला अमृतसर के गांवों में चल रहे पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए गए स्वयं सहायता समूहों में ग्रामीण महिलाएं अपने परिश्रम से आत्मनिर्भर बनने और अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर श्रीमती परमजीत कौर ने बताया कि हाल ही में अमृतसर जिले के अंतर्गत आने वाले रमदास क्षेत्र के गांवों में आई बाढ़ के कारण लोगों को काफी नुकसान हुआ था, जिससे इन स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियाँ भी प्रभावित हुई थीं।

इन महिलाओं को दोबारा अपने काम की शुरुआत करने में सहायता प्रदान करने के लिए फिक्की फ्लो अमृतसर की चेयरपर्सन श्रीमती मोना सिंह, श्रीमती मिनी संधू, डॉ. शारिता नागरा, श्रीमती निधि भल्ला और श्रीमती जानवी कटारिया द्वारा अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (पी.वी.) अमृतसर के कार्यालय में स्वयं सहायता समूहों की 10 महिला सदस्यों को प्रत्येक 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

इस सहयोग के लिए महिला सदस्यों ने फिक्की फ्लो अमृतसर की टीम का धन्यवाद किया। इस अवसर पर श्रीमती अम्मिका वर्मा (नोडल अधिकारी), श्री प्रभप्रीत सिंह (लेखाकार) और श्री चरणबीर सिंह (ब्लॉक इंचार्ज, रमदास) उपस्थित रहे।

दिवाली की तैयारियों को लेकर मेयर जतिंदर सिंह भाटीया द्वारा नगर निगम के विभिन्न विभागों के मुखियों के साथ एक बैठक की गई

अमृतसर 15 अक्टूबर (साहिल बेरी)

दिवाली की तैयारियों को लेकर मेयर जतिंदर सिंह भाटीया द्वारा नगर निगम के विभिन्न विभागों के मुखियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें नगर निगम के कमिश्नर बिक्रमजीत सिंह शेरगिल भी मौजूद थे। इस दौरान मेयर भाटीया ने सभी विभागों के मुखियों को दिशा-निर्देश दिए कि दिवाली के मौके पर शहर को साफ-सुथरा रखने और नगर निगम की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सभी विभाग अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने यह भी कहा कि गुरु नगरी अमृतसर की दिवाली का विशेष महत्व है, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री हरिमंदर साहिब और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए आते हैं।

उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए श्री दरबार साहिब जाने वाले सभी रास्तों की दिन में दो बार सफाई और रात को अलग से सफाई करवाई जाए। इस दौरान उन्होंने फायर ब्रिगेड विभाग को निर्देशित किया कि वे 24 घंटे चौकस रहें, ताकि शहर में किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। साथ ही, उन्होंने सीवरेज विभाग को आदेश दिया कि शहर की सीवरेज प्रणाली को सुचारू रूप से रखा जाए।

करमजीत सिंह रिंटू ने दयानंद नगर पंचायत के देवी नगर क्षेत्र में शत प्रतिशत विकास कार्य कार्रवाए शुरू

उत्तरी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी इलाका विकास से अधूरा नहीं रहेगा: करमजीत सिंह रिंटू

अमृतसर, (साहिल बेरी) इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन एवं उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के इंचार्ज करमजीत सिंह रिंटू ने दयानंद नगर पंचायत के देवी नगर क्षेत्र की सभी गालियो को पक्का बनवाने और स्ट्रीट लाइटे लगाने केशत प्रतिशत विकास कार्य का शुभारंभ किया। करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के हर मोहल्ले में तेजी से विकास कार्य पहुंचाए रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तरी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी इलाका विकास से अधूरा नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तरी विधानसभा क्षेत्र की नगर निगम की सभी वार्डों के साथ-साथ सभी पंचायतो के भी अधूरे पड़े विकास कार्य शुरू करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या सुनकर उन समस्याओं का जल्द ही हल भी निकाला जा रहा है।

करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर विकास कार्यों के लिए कोई भी कमी नहीं आने दे रही है। उन्होंने कहा कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की अलग-अलग स्कीमों में शेष रहते विकास कार्यों को मंजूरी दे दी गई है। आने वाले दिनों में यह सभी विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। रिंटू ने कहा कि उत्तरी विधानसभा क्षेत्र की अधूरी पड़ी सड़कों को प्रीमिक्स से पक्का करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले 1 महीने तक लगातार सड़कों पर प्रिमिक्स का कार्य जारी रहेगा।

करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि ₹रंगला पंजाब योजना₹ के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपए ग्रांट के रूप में जारी करने पर वह आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के धन्यवादी है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए पंजाब सरकार की ओर से फंड की कोई कमी नहीं आने दी जा रही है। इस अवसर पर सरपंच पवन कुमार हैप्पी, पंचायत सदस्य, अवतार औजला, जितेंद्र पाल सिंह, रीमा देवी, अमरजीत कौर, राकेश कुमार रमदास, सुविंदर शिंदी, साहिल सग्गर, प्रणव धवन और भारी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद थे।

लाभार्थियों को अब पांच किलो की जगह दस किलो चावल मिलेगा - आपूर्ति मंत्री

मनोरंजन सासमल, बरिष्ठ पत्रकार

भूबनेश्वर : मंत्री ने पहले बताया कि चावल कार्ड के लाभार्थियों को जल्द ही 5 किलोग्राम के बजाय 10 किलोग्राम चावल प्रति माह मिलेगा।विभाग द्वारा मुख्यमंत्री को इस संबंध में सूचित किए जाने के बाद, मंत्री श्री पात्रा ने बताया कि सरकार गरीब लाभार्थियों की समस्याओं पर अंतिम निर्णय लेगी।

मंडल विकास अधिकारी सुभाशीष पलटा की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में स्थानीय विधायक शारदा प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। विधायक श्री प्रधान ने बताया कि महांगा प्रखंड की 37 पंचायतों में रहने वाले सभी गरीब, उपेक्षित और निराश्रित परिवारों को पक्के मकान, भत्ता और राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 371 विधवाओं, दिव्यांगों, अविवाहित, पति द्वारा परित्यक्त और वृद्ध महिलाओं को विभिन्न भत्ते प्रदान किए गए। इसी प्रकार, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 357 और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में 334 नए लाभार्थियों को

शामिल किया। मंत्री श्री पात्रा और विधायक श्री प्रधान ने पंचायती राज विभाग की ओर से अंत्योदय गृह जन योजना के अंतर्गत 331 लाभार्थियों को कार्यादेश दिए। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के. चंद्रशेखर ने कार्यक्रम में अतिथि वक्ता के रूप में भाग लिया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com

(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। **RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023**